खण्ड-07 सत्र-05 अंक-67

शुक्रवार 15 मार्च, 2024 / 25 फाल्गुन, 1945 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा

पाँचवां सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-07 सत्र-05 में अंक 50 से अंक 70 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

राज कुमार

सचिव

RAJ KUMAR

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप-सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-5 शुक्रवार, 15 मार्च, 2024/25 फाल्गुन, 1945 (शक) अंक-67

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	जलापूर्ति एवं सीवेज रख-रखाव से संबंधित संकल्प पर चर्चा	3-79
3.	अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)	80-110
4.	ध्यानाकर्षण (नियम-54)	111-115

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 शुक्रवार, 15 मार्च, 2024/25 फाल्गुन, 1945 (शक) अंक-67

दिल्ली विधान सभा

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1. श्री अजेश यादव
2. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
3. श्रीमती ए. धनवंती चंदीला ए.
4. श्री अजय दत्त
5. श्री अब्दुल रहमान
6. श्रीमती बंदना कुमारी
7. सुश्री भावना गौड
8. श्री बी. एस. जून
9. श्री धर्मपाल लाकड़ा
10. श्री दिनेश मोहनिया
11. श्री दुर्गेश कुमार
12. श्री गिरीश सोनी
13. श्री गुलाब सिंह
14. श्री हाजी युनूस
15. श्री जय भगवान
16. श्री जरनैल सिंह
17. श्री करतार सिंह तंवर
18. श्री मुकेश अहलावत
19. श्री नरेश बाल्यान
20. श्री नरेश यादव

21. श्री प्रीति जितेंद्र तोमर
22. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस
23. श्री राजेश गुप्ता
24. श्री राजेन्द्रपाल गौतम
25. श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों
26. श्री राजेश ऋषि
27. श्री रोहित कुमार
28. श्री शरद कुमार चौहान
29. श्री सोमदत्त
30. श्री शिव चरण गोयल
31. श्री एक. के. बग्गा
32. श्री विनय मिश्रा
33. श्री वीरेंद्र सिंह कादियान
34. श्री अभय वर्मा
35. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
36. श्री अजय कुमार महावर
37. श्री जितेंद्र महाजन
38. श्री महेंद्र गोयल
39. श्री महेन्द्र यादव
40. श्री मदन लाल
41. श्री मोहन सिंह बिष्ट
42. श्री ओमप्रकाश शर्मा
43. श्री पवन शर्मा
44. श्री प्रलाद सिंह साहनी
45. श्री प्रवीण कुमार
46. श्री ऋतुराज गोविंद
47. श्री सुरेंद्र कुमार
48. श्री विजेंद्र गुप्ता
49. श्री विशेष रवि

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 शुक्रवार, 15 मार्च, 2024/25 फाल्गुन, 1945 (शक) अंक-67

दिल्ली विधान सभा

सदन 11.21 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आज जल बोर्ड पर चर्चा है और ये 280 पढ़े हुये माने जायें। एक बार माइक नहीं था, मैं दोबारा से प्रलाद सिंह साहनी जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई शुभकामनायें देता हूं। वो अपने व्यक्तिगत तथा राजनीतिक जीवन में नई उंचाईयाँ प्राप्त करें ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूं। संकल्प पर चर्चा- अब श्री दिलीप कुमार पाण्डेय, माननीय मुख्य सचेतक द्वारा दिल्ली के निवासियों को हो रही जल आपूर्ति एवं सीवेज़ लाइनों के रख-रखाव से संबंधित गंभीर समस्याओं के संबंध में दिनांक 09 मार्च, 2024 को प्रस्तुत और सदन द्वारा स्वीकृत संकल्प पर चर्चा होगी। अब श्री दिलीप कुमार पाण्डेय, माननीय मुख्य सचेतक संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति लेंगे।

श्री दिलीप पाण्डेयः अध्यक्ष महोदय ये संकल्प अभी प्रस्तुत करें या चर्चा के बाद करें?

माननीय अध्यक्षः अभी तो अनुमति मांगिये चर्चा की।

श्री दिलीप पाण्डेयः अध्यक्ष महोदय में सदन के पटल पर दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ी हुई समस्याओं के ऊपर पिछले हाउस में सदन में चर्चा हुई थी उसके ऊपर संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति मांगता हूं।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

सदन द्वारा श्री दिलीप कुमार पाण्डेय, माननीय मुख्य सचेतक को संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। अब इस संकल्प पर, अब माननीय सदस्य संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री दिलीप पाण्डेयः अध्यक्ष महोदय On 9th of March of this month this House has passed a resolution regarding rising sewer and water problems across Delhi and giving its responsibility to Hon'ble Chief Secretary to resolve these issues.

This House appreciates the fact that in the last one week several grievances have been taken up in a speedy manner and brought relief to the residents of Delhi. This House also finds that a complaint from some of the members were not very specific and hence could not be resolved, however, many of them have orally expressed their grievances in the Assembly during rule 280 and other discussions that took place in the House. Members were also requested to give their specific grievances to the Hon'ble Speaker and the Hon'ble Water Minister.

Whereas there has been some relief to some residents of Delhi in the last one week, however, many grievances still remain same and these grievances need to be resolved within next one week.

Even for the grievances that have not been resolved, there is a need to work on a long term and permanent solution and resolution of those problems.

Therefore, in the interest of the people of Delhi this House resolves that:

1. the Chief Secretary shall continue to monitor and supervise the short term and long term resolution of the water and sewer related problems across Delhi.

2. Since Delhi faces shortage of water supply specially in December months, a detailed plan will be made for augmentation of water resources from ground water. This will be done on a war footing to ensure relief to the people of Delhi from this summer itself.

3. Since many complaints have been received and that tankers have been reduced, the water tankers shall be brought back to earlier numbers. Chief Secretary shall reduce number of tankers, only after consultation with area MLAs.

4. Since many parts of Delhi face sewer overflows due to absence of storm water drains, the Chief Secretary will coordinate with MCD to resolve this problem.

5. Till resolution of issue of storm water drains is done, an estimation needs to be done of the number of sewer cleaning machines and the frequency with which sewer cleaning and desilting needs to be done to prevent sewer overflows across Delhi. Adequate number of small and large machines need to be available for this purpose with Delhi Jal Board.

6. Desilting of all trunk and peripheral sewers needs to be done in a very time bound manner.

7. Timelines need to be provided regarding the award and completion of works that have been reported in the 'Action Taken Report' as being 'in the tendering process'.

8. Chief Secretary to ensure better coordination between Delhi Jal Board, Urban Development Department and Finance as well, so that critical utilities like water and sewerage do not get affected.

9. It is appreciable that Delhi Jal Board has worked on a war footing in the last 5 days to resolve grievances being faced by the residents of Delhi; however, strong action needs to be taken against officers who have not done their duties in resolving water and sewerage related grievance of the people of Delhi in the last few months.

The Chief Secretary shall be responsible for actioning all the aforementioned issues, as well as the pending grievances. A sitting of the House be called on 22.3.2024, where the Chief Secretary will provide a report on the same. Thank you.

माननीय अध्यक्षः श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी 9 मार्च, 2024 को मैंने आपको एक लैटर लिखा था और उसके अंदर मेरी विधानसभा के अंदर कुछ जो समस्यायें हैं उसके बारे में बात करी थी। मैं विधानसभा का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन ऑफिसरों ने इस पर बहुत अच्छा काम किया उनको भी देना चाहता हूं। माननीय केजरीवाल जी की सरकार जिस तरीके से लोगों के लिये काम करती रही है उसका एक ज्वलंत उदाहरण आपके सामने है इस तरीके से काम हो रहा है। मैं एक-एक

प्वांइट को पढ़ना चाहता हूं पहला प्वांइट है वजीरपुर इन्डस्ट्रियल एरिया में जगह-जगह पानी नहीं आता है जैसे उधमसिंह पार्क, गदाघर, पार्वती चौक आदि। इसमें से अगर मुझे कोई बता सके यहां पर कुछ हुआ है तो या मैं बताऊँ कि क्या मेरे पास में रिपोर्ट आई है अभी।

माननीय अध्यक्षः नहीं आप अपनी बात रखिये ना।

श्री राजेश गुप्ताः जी, तो मेरी बात तो ये है कि सर इसके अंदर जो मैंने तीन जगह लिखीं उधमसिंह पार्क, गदाघर और पार्वती चौक इसके अंदर दो लाइन का मेरे पास में जल बोर्ड से जवाब आया है कि वो इसका वर्क आर्डर कर रहे हैं और इसका मुहुर्त करा लिया जाये ये वो मुझे कह चुके हैं। दूसरा जेलर वाला बाग में सीवर लाइन है इसमें सीवर लाइन का गलती से टाइप हो गया था दरअसल ये पानी का है और सीवर तो वहां है नहीं क्योंकि ये झुग्गियां हैं तो पानी की समस्या इसमें अभी भी बनी हुई है, इसमें भी कुछ हो नहीं पाया। तीसरा प्वांइट सावन पार्क, अशोक विहार फेज़-3 जिसके लिये आधी लाइन डालकर छोड़ दिया गया तो जल बोर्ड से भी जवाब ये आया है कि पैसे कुछ डीडीए में जमा कराने है। मौखिक तौर पर मुझे यह बताया गया है कि जो आपने भी एक मीटिंग ली थी उसके अंदर की ये पैसे हम जल्द ही दे देंगे ये जल बोर्ड ने कहा है और बात हो गई है कि दे देंगे लेकिन अभी तक दिये नहीं हैं, अभी यही स्थिति है यही रिपोर्ट में भी उन्होंने मुझे लिखकर भेजा है। चौथा एफ-ब्लॉक जे.जे. कॉलोनी में लगभग तीन-चार महीने से सीवर लाइन भरी हुई है इसके अंदर इन्होंने फिर मुझे कहा है किये काम लगभग हम इसको शुरू कर रहे हैं इसका मुहुर्त कर

लिया जाये। पांचवा ए-1 केशवपुरम् का है इसके लिये इन्होंने ठेका कर दिया है और इसके लिये मुहुर्त के लिये बोल दिया है। डी-ब्लॉक अशोक विहार का इसमें भी यही कहा है की इसमें हम कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। सातवां सी-8 में बी-4 के सामने पीडब्ल्यूडी की सड़क ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है रिस्टोरेशन की खासतौर की अगर वो सड़क बड़ी है, ये बहुत बड़ी सड़क है अभी तक इस पर कुछ काम नहीं हो पाया है। इसके अलावा एक और लाइन पर काम हुआ है वो भी बहुत बुरी पोजिशन में है उसमें भी बस धंस गई थी अभी 10 दिन पहले। आठवां पानी की लाइन जगह-जगह पर है ये जनरल है तो इसके अंदर कोई जवाब इसमें आया नहीं है। वजीरपुर गांव के सीवर के लिये आया है इसमें भी यही आया है की इन्होंने टैंडर कर दिया है और दसंवा और ग्यारंवा, ग्यारंवें में सीधे आ जाता हूं उसके बाद में कि पानी की लाइन है पत्थर वाला बाग के अंदर जहां पर आदरणीय मंत्रीजी भी आईं थीं इसमें भी अभी ये कुछ खास कर नहीं पाये हैं। तो मेरा ये कहना है कि कुछ चीज़ों पर काम हुआ है जिसके अंदर इन्होंने जवाब भी दिया है किसी पर इन्होंने वर्क आर्डर भी कर दिये हैं कि कुछ पर टैंडर करे हुये हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी थोड़ी स्लो चल रही हैं।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री महोदया।

माननीया जल मंत्री (श्रीमती आतिशी): जी, अध्यक्ष महोदय जो कम्प्लेंट्स आईं थीं आपके पास सारी वो आपने मुझे भी फॉरवर्ड करीं थीं, चीफ सेक्रेटरी को भी फॉरवर्ड की थीं तो मैं सारे हाउस को

बता दूं कि पिछले एक हफ्ते से दिल्ली जल बोर्ड ने चीफ सेक्रेटरी साहब की सुपरविज़न में इस पर काफी काम किया है। कल रात को भी काफी लम्बी चर्चा हुई थी मेरी ऑफिसरों के साथ उन्होंने ये रिपोर्ट रखी है तो जो आपकी ग्रिवेन्सिज़ हैं उस पर सी.एस. की रिपोर्ट में क्या आया है मेरे पास वो मैं आपके सामने रख देती हूं। जो आपका वजीरपुर इन्डिस्ट्रियल एरिया है वहां पर ये कहा गया है इस रिपोर्ट में कि इन जे.जे. कलस्टर क्षेत्रों में जल आपूर्ति उपलब्ध है हालांकि जल आपूर्ति में सुधार के लिये निविदायें आमंत्रित की गई हैं और अवार्ड चरण में हैं। जेलर वाला बाग अशोक विहार फेस-2 में सीवर लाइन जाम होने के कारण स्थिति गंभीर हो गई है परंतु अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि फिलहाल सीवर लाइन चालू है निवासियों की लिखित पुष्टि दी गई है। सावन पार्क, अशोक विहार फेज.-3 में लगातार पानी ना आने की समस्या बनी हुई है इसके समाधान के लिये वहां पानी की लाइन का प्रावधान किया गया परंतु उसको कुछ जगह डालकर अभी तक अधूरा छोड़ दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान में सावन पार्क में जलापूर्ति की कोई कमी नहीं है हालांकि सुधार के लिये नई लाइन बिछाने का काम पहले ही सौंपा जा चुका है हालांकि डीडीए पार्क के अंदर से पानी की लाइन बिछाने के लिये डीडीए को restoration शुल्क का भुगतान वित्त से जारी होने के बाद किया जाना है। डीडीए को restoration शुल्क जमा करने के बाद काम शुरू किया जायेगा। एफ-ब्लॉक जे.जे. कॉलोनी में पिछले लगभग तीन से चार महीने से सीवर लाइन भर जाती है जल

बोर्ड अधिकारियों का कहना है लाइन डैमेज़ हो गई है इसको बदलवाना होगा परंतु जल बोर्ड ने इसको अभी तक नहीं बदला हैं इस पर रिपोर्ट में ये कहा गया है कि फिलहाल सीवर लाइन चालू है, निवासियों की लिखित पुष्टि संलग्न है हालांकि सीवर लाइन को बदलने के लिये निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं और अवार्ड चरण में है। ये दो और जो आपकी समस्यायें हैं ए-ब्लॉक केशवपुरम् और डी-ब्लॉक अशोक विहार के लिये भी यही कहा गया है कि सीवर लाइन फिलहाल चालू है लेकिन सीवर लाइन को बदलने के लिये निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं और अवार्ड चरण में हैं। केशवपुरम् सी-8 और डी-4 के सामने पीडब्ल्यूडी की सड़क पर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कुछ कार्य के लिये सड़क को खोद दिया गया था लेकिन इसके कारण यातायात में बहुत समस्या है। पानी की लीकेज की मरम्मत के लिये की गई खुदाई को ठीक कर दिया गया है और पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है हालांकि CC के साथ रोड़ की रिपेयरिंग शीघ्र की जायेगी। आपने ये कहा, आपकी समस्या थी की पूरी विधानसभा में जगह-जगह पानी लिकेज की समस्या बनी हुई है परंतु दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पिछले कई महीनों से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जल बोर्ड का कहना है कि पानी की लाइन में लिकेज की शिकायतों को दिन-प्रतिदिन नियमित रूप से अटेंड किया जाता है। आपका नेक्स्ट इश्यू था कि डब्ल्यूपीएक्स वजीरपुर गांव में सीवर भरने की समस्या लगातार हो रही है। यहां भी सीवर लाइन बदलने की बात जल बोर्ड द्वारा की जा चुकी है लेकिन अभी हुआ नहीं है इनका कहना है की फिलहाल सीवर लाइन चालू है,

निवासियों की लिखित पुष्टि भी संलग्न है हालांकि सीवर लाइन को बदलने के लिये निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं और अवार्ड चरण में हैं। इसी तरह से ए-370 और ए-431 बुनकर कॉलोनी और पत्थर वाला बाग जे.जे. कॉलोनी में पानी की लाइन की भी निविदियें आमंत्रित की गई हैं और अवार्ड चरण में हैं।

माननीय अध्यक्षः ये अभी, अभी क्या रहा राजेश जी, अभी कुछ बाकी रहा क्या?

श्री राजेश गुप्ताः जी, मैं इसी पर कुछ कहना चाहता हूं इसी पर ही। मैं एक बार फिर से आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का आतिशी जी का और स्पीकर साहब आपका धन्यवाद देता हूं और उन अधिकारियों का जिन्होंने इस पर काम किया है पिछले पांच-सात दिनों में लेकिन जैसे कि माननीय मंत्रीजी ने कहा की वैसे तो कहा कि चालू है अधिकारियों ने लिखकर दिया लेकिन फिर ये भी कहा कि हमने टैंडर इसके अंदर कॉल किये हैं तो ये खुद जानते हैं कि ये अब सीवर लाइन चलने की सिचुएशन में नहीं है। ये जाते हैं उस दिन चालू कर देते हैं लेकिन अगले दिन या उसके अगले दिन पक्का भर जाती हैं इसीलिये इन्होंने टेंडर कॉल किये हैं। दूसरा एक रोड़ की जो इन्होंने बात की वो मेन रोड्स हैं बिल्कुल और क्योंकि पीडब्ल्यूडी की मंत्री भी आप ही हैं तो अभी तीन-चार महीने पर उस पर काम नहीं हो सकता था। ठंड के दिनों में हमारे प्लांट्स बंद होते हैं तो यही अगर CC कर पाते लेकिन ये कर नहीं रहे थे जिसकी वजह से उसमें बस ंस गई, बिल्कुल मेन रोड है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है और पहले तो

बहुत-बहुत धन्यवाद है क्योंकि मुझे बहुत एक उम्मीद की किरण जिस तरीके से आप लोगों ने करा है मैं बहुत धन्यवाद देता हूं बार-बार इसके लिये और प्रोसेस में है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ हो जायेगा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, सभी का थैंक्यू।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान दुर्गेश पाठक जी।

श्री दुर्गेश पाठकः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा में पिछले कई महीनों से सीवर और पानी की बड़ी समस्या थी। पिछले हफ्ते ही मैंने आपको एक पत्र लिखा था और उसमें जो भी समस्यायें आ रही थीं मैंने आपको सूचित किया था पत्र के माध्यम से। मैं एक बार सारी समस्यायें समराइज़ वे में पढ़ देता हूं। नारायणा गांव के अंदर ऐसे लगभग 10 से 12 गलियां हैं जिसमें लगातार सीवर भरा रहता है और वहां पर गंदा पानी आने की समस्या है साथ ही साथ वाल्मिकी गली दसघरा विलेज में सी और डी ब्लॉक हमारा बुध नगर के अंदर, पांडव नगर के अंदर, सौ क्वॉटर के अंदर, गुरूद्वारा रोड, नारायणा विहार एक तरीके से डूब गया था पूरी तरह से पानी से सीवर के पानी के कारण उसकी समस्या मैंने लिखी थी। मैंने आपको हाउस नम्बर 460 से लेकर 495 सी ब्लॉक बुध नगर के अंदर लैट्रिन बाहर सड़कों पर बह रहा है और 25-25 गज के मकान हैं लोगों के और लोग अपने घर में भी नहीं रह सकते इतनी ज्यादा बदबू है वहां पर। ई-ब्लॉक नारायणा विहार के अंदर बी-ब्लॉक के अंदर पूरे नारायणा विहार के अंदर गंदे पानी और सीवर के इश्यूज़ हैं, पांडव नगर के अंदर, लोहा मंडी जेड-ब्लॉक के अंदर पूरे लोहा मंडी के अंदर इन्डिस्ट्रियल एरिया का

बहुत बुरा हाल है पूरी तरह से सीवर वहां सड़कों पर बह रही हैं। इसी तरह से जो कैम्प के इलाके हैं सोनिया गांधी कैम्प से लेकर सारे कैम्प्स वहां पर भी बड़ी दिक्कत है इस तरह से काफी जगहों पर पूरे नारायणा गांव, बुध नगर, लोहा मंडी, पांडव नगर, दसघरा, टोडापुर और कुछ-कुछ इलाकों में ओल्ड राजेन्द्र नगर, न्यू राजेन्द्र नगर जैसे इलाके में भी पानी की सॉरी सीवर बहने की ओवरफ्लो की समस्या थी। इसी तरह से मैनें कुछ पानी जो इस समय गंदा पानी आ रहा है उसकी भी समस्या लिखवाई थी ए से लेकर ई-ब्लॉक नारायणा विहार वहां पर भी गंदा पानी की समस्या है। नारायणा विलेज के अंदर अरावली स्कूल से लेकर माता वाली चौक, सीताराम चौक से लेकर माता चौक सीताराम चौक से लेकर डब्ल्यू जेड-880 वहां पर भी नारायणा विलेज के अंदर गंदा पानी की दिक्कत थी। होली चौक दसघरा वहां गंदे पानी की समस्या है, ए-85 नारायणा इन्डिस्ट्रियल एरिया, जे.जे. कल्स्टर, राजीव गांधी कैम्प, सोनिया गांधी कैम्प इन सारे इलाकों में सी-ब्लॉक नारायणा कम्यूनिटी सेंटर वहां गंदे पानी की दिक्कत थी। ए और बी ब्लॉक पांडव नगर के अंदर दिक्कत है सी-ब्लॉक के अंदर बुध नगर के अंदर दिक्कत है। कई जगहों पर मलबे नहीं उठे हैं जल बोर्ड के द्वारा जो काम किया है उसका भी मैंने एड्रैस इसमें अटैच किया है। कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर या तो पानी नहीं आता या पानी बहुत कम आता है तो होली चौक के आस-पास डबल स्टोरी हमारा न्यू राजेन्द्र नगर है, माता वाली चौक के आस-पास, पूरे इसमें मैंने डिटेल में लिखा है नारायणा विलेज के अंदर कई सारी ऐसी गलियां हैं जो पीछे पड़ती हैं उनमें पानी की

समस्या है या तो पांच मिनट आता है दस मिनट आता है। इसी तरह से सारे कलस्टर एरियाज़ में काफी दिक्कत है, संगम कॉलोनी के अंदर आज भी पानी की दिक्कत बनी हुई है लगातार। मैंने लगभग 27 ऐसी जगह इसमें मेंशन की हैं जहां पर सीवर बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है 30 से 35 साल हो चुके हैं सीवर वहां पर पड़े हुये और अंदर घूस के कारण बिल्कुल सीवर पूरी तरह से खत्म हुआ उसको बदलने के लिये कहा है साथ ही साथ लगभग 39 ऐसी जगह हैं जहां पर बोरवेल की जरूरत है क्योंकि पानी तभी वहां पर पहुंचाया जा सकता है उसका भी मैंने डिटेल में इसमें लिखा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि उसमें क्या प्रोग्रेस उनके पास report हुई है प्लीज़ बतायें।

माननीया जल मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय सबसे पहले तो मैं दुर्गेश पाठक जी का धन्यवाद करना चाहूंगी मुझे लगता है की जितने सलीके से इनकी सारी कम्प्लेंट्स आईं थीं कि उन्होंने एग्ज़ेक्ट्ली एग्ज़ेक्ट लोकेशन के साथ कहां पर समस्या थी, क्या समस्या थी वो शेयर किया। तो मुझे लगता है कि ऑफिसरों को भी उससे काफी आसानी हुई इश्यू को रिज़ोल्व करने में। तो मैं बाकी सब विधायक साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कुछ पैंडेंसी है आपके यहां कम्प्लेंट्स की जो आपको लगता है की अभी रिज़ोल्व नहीं हुई हैं तो आप भी अगर जितना स्पेसेफिक तरीके से कि कहां पर क्या प्रॉब्लम है एग्ज़ेक्टि्ली एग्ज़ेक्ट एड्रैस के साथ अगर वो दे देंगे तो ऑफिसर्स को भी सॉल्व करने में उनको आसानी होगी। जो सीवर रिलेटिड इश्यूज़ हैं जो लोकेशन्स अभी दुर्गेश पाठक जी ने बताईं होली चौक, वाल्मिकी गली, दसघरा

गांव में 43 एंड 201 बुध नगर, ए-ब्लॉक पांडव नगर, सौ क्वॉटर, नारायणा विहार, ई-ब्लॉक नारायणा विहार, बी-ब्लॉक पांडव नगर, जेड-ब्लॉक लोहामंडी, ए-ब्लॉक नारायणा इन्डिस्ट्रियल एरिया, सोनिया गांधी कैम्प, जे. जे. कलस्टर, मातावाली चौक, सीताराम चौक, नारायणा विलेज, डब्ल्यू जैड-700 नारायणा विलेज, वाल्मिकी मोहल्ला, डब्ल्यू जेड-75 टू डब्ल्यू जेड-51 टोडा पुर विलेज, बुध नगर ए-ब्लॉक बी-ब्लॉक, एच-ब्लॉक राजेन्द्र नगर। अध्यक्ष महोदय जो रिपोर्ट मुझे मिली है उसके अनुसार ये रूटीन मेन्टेनेंस की समस्यायें थीं और अब यहां पर ऐसा कहा गया है कि कोई भी सीवर ओवरफ्लो की समस्या नहीं है हालांकि अभी दुर्गेश पाठक जी ने जैसा बताया कई जगह पर इस रिपोर्ट में तो मौजूद नहीं है लेकिन ये बताया गया है इनके द्वारा कि इसमें कई जगह शायद सीवर की लाइन बदलने की जरूरत है। दूसरी बात जो मेरी काफी डिटेल में चर्चा हुई थी कल दिल्ली जल बोर्ड के साथ और चीफ सेक्रेटरी के साथ वो ये हुई थी कि काफी जगह जो सीवर का ओवरफ्लो हो रहा है वो इसलिये भी हो रहा है क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर storm water drains नहीं हैं, तो जो नालियां हैं नालियों में जो पानी जाना होता है वो पानी भी सीवर में जा रहा है। सीवर की उतनी band width नहीं है कि वो सारे को accommodate कर सके और इसलिये सीवर्स भी काफी ज्यादा उसकी वजह से ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो हमारी ये बात कल हुई है कि यूडी डिपार्टमेंट की अध्यक्षता में एक बारी इसको भी पूरा एनालाइज़ किया जायेगा कि कहां-कहां पर एमसीडी की ड्रैन्स की जरूरत है, दिल्ली जल बोर्ड भी

ये बात डिटेल में रखेगा और अगर हमारे विधायक साथी भी इस पर अपना फीडबैक देना चाहें कि कहां-कहां पर उनके एरिया में नालियों की जरूरत है सो देट जो नालियों वाला पानी है सीवर में ना जाये और सीवर ओवरफ्लो ना करे। तो फिर हम एमसीडी के साथ कॉर्डिनेशन में वो नालियां बनवाने का भी काम और उन नालियों की लगातार सफाई का भी काम करवायेंगे जिससे जो सीवर की लाइन्स पर प्रेशर डल रहा है वो प्रेशर कम हो जाये। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय ये भी बात हुई थी कि जब तक ये नालियां नहीं बनती हैं तब तक obviously सीवर लाइन्स की ज्यादा रेगुलर de-silting करने की जरूरत होगी। तो दिल्ली जल बोर्ड एक पूरा एनॉलिसिस भी करेगा इन एरियाज़ का और कितनी frequency से कौन सी मशीन के साथ सफाई होने की जरूरत है उसका भी एक एनॉलिसिस करेगा। अगर मशीनों की कमी है तो उन मशीनों को हायर किया जायेगा। ये बात भी सामने आई की सुपर सक्कर मशीन्स और रिसाइक्लर मशीन्स की जरूरत है तो उनका भी टैंडर फ्लोट करके 7 साल का टैंडर कल निर्णय हुआ है कि सुपर सक्कर मशीन्स और रिसाइक्लर मशीन्स का किया जायेगा कि बड़ी मशीन्स भी हमारे सीवर्स की क्लीनिंग और डिसेल्टिंग के लिये अवेलेबल हों। दुर्गेश जी ने जो अभी अपनी बात रखी की कई टैंडर्स के बारे में अभी इसमें नहीं दिया हुआ है। दूसरा मैंने अभी विभाग से ये भी रिक्वेस्ट किया है कि आपके यहां क्योंकि वो 24x7 का जायका का प्रोजेक्ट चल रहा है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इस वजह से भी हो जाता है कि कौन सा काम किसके एरिया में आता है। पानी का काम एक

ऑफिसर देखते हैं और सीवर का काम शायद दूसरे ऑफिसर देखते हैं, तो उसका भी कॉर्डिनेशन हम करेंगे सो देट आपके एरिया की प्रॉब्लम्स थोड़े बैटर तरीके से रिज़ोल्व हो पाये। अभी जो मुझे बताया गया है कि पैंडिंग प्रॉब्लम्स जो हैं अभी पानी की A-44 to A-56, A-61, B-38 to 48, B-32 to 22, B-53 to 54,की जो पानी की लाइन हैं ये वाला काम अभी भी पैंडिंग है। जो आपकी बाकी सारी कम्प्लेंट्स हैं दुर्गेश जी उनको रिज़ोल्वड बताया गया है।

श्री दुर्गेश पाठकः उसके लिये तो मैं धन्यवाद करूंगा स्पीकर साहब आपका माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का मंत्री जी का हमारे सी.एस. साहब का और जितने भी हमारे अधिकारी हैं सब लोगों का धन्यवाद करूंगा की पिछले एक हफ्ते में निश्चित रूप से ज़मीन पर चीज़ें बहुत तेज़ी से मूव की हैं मैं अपनी विधानसभा की बात कह सकता हूं जिसमें अधिकारी बहुत अच्छे हैं नीचे के जो हमारे अधिकारी हैं जो जे.ई. हैं ए.ई. हैं एस.ई. हैं वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कॉर्डिनेट करके काम किया है लेकिन एक प्रश्न ये उठता है की अगर ये पांच दिन, छः दिन, सात दिन के अंदर ये सारी समस्यायें रिज़ोल्व हो सकती हैं तो छः-छः महीने तक लोग परेशान क्यों थे इसकी अगर जिम्मेदारी फ़िक्स हो सके तो हमें जिम्मेदारी भी फिक्स करनी चाहिये जिससे आगे की समस्या ना हो, दूसरी ये है की ज्यादातर जगहों पर सीवर को क्लीन करके एक तरीके से फ़्लो ठीक किया गया है लेकिन इसका लांग टर्म सोल्यूशन हमें निकालना होगा। जैसे जहां पर सीवर लाइन बदलनी है उसको बदलना पड़ेगा। जहां-जहां पर आगे

de-silting नहीं हुई है। जैसे मैं आपको एक incident बताता हूं। हमारे पास सत्यापार्क के अंदर एसपीएस लगा, जिसके तहत एक लगभग 30 परसेंट एरिया का हमारा जो सीवर का पानी है वो एसपीएस को आगे पुश करके आगे बढ़ाना है मोतीनगर के आगे ले जाना है लेकिन वो एसपीएस इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई दिक्कत हर दिन आ जाती है, लीकेज आ जाती है, सारी समस्या आ जाती है। तो आप हर दिन दस, पन्द्रह दिन, बीस दिन में आप देखते होंगे कि पांडव नगर के अंदर वीडियोज सोशल मीडिया पर भी चलते हैं कि पांडव नगर के अंदर पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। उसका कारण है कि एसपीएस चलता नहीं है। जिस दिन हम लोग ज्यादा दबाव डाल करके एसपीएस चला देते हैं तो एसपीएस का पानी मोती नगर चला जाता है तो मोती नगर डूब जाता है। हमारे शिवचरण गोयल जी होंगे, वहां डूब जाता है क्योंकि आगे दस से पन्द्रह किलोमीटर की लाइन है वो लाइन de-silting नहीं हुई है उसको भी सुनते है कि हर दिन टेंडर लगा हुआ है पता नहीं क्या हुआ है। तो मेरा यह कहना है कि इसको एक ओवरऑल एक अच्छे से तरीके से एक-एक गली को प्लान करके कि जहां सीवर बदलने की जरूरत है, वहां तुरन्त सीवर बदले जायें। जहां पर पानी की लाइन बदलने की जरूरत है उसको तुरन्त पानी की लाइन बदली जाये। जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि चूंकि हमारे यहां 24x7 पानी का भी प्रोजेक्ट चल रहा है और साथ ही साथ सीवर एक अलग डिपार्टमेंट देखता है जल बोर्ड देखता है और पानी का वो देखते हैं तो उसमें भी निश्चित रूप से कई बार कन्फ्यूजन होता है

कि लोग पानी की कम्पलेंट लेकर जाते हैं तो वह कह देते हैं कि जी सीवर के कारण आ रहा है तो उसका भी अगर एक combined unit बन सके एक पूरा सिस्टम बन सके और एक नोडल हो सके जिसके तहत ये समस्या रिसोल्व हो सके तो मैं बहुत आभारी होऊंगा। फिर भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगा पिछले पांच छः दिनों में जिस तरह से आप लोगों ने effort लगाकर इसको रिसोल्व करने की कोशिश की है और मैं ये ही आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि सारे differences भूल कर अपनी दिल्ली को एक बेहतरीन दिल्ली बनाने के लिए खासकर ये समस्याएं तो ना रहें और मिलकर काम करें इसके लिए मैं बहुत-बहुत आपका धन्यवाद भी करूंगा।

माननीय अध्यक्षः श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों।

श्रीमती राजकुमारी ढिल्लोंः अध्यक्ष जी, कुछ समय पहले मैंने मेरी विधान सभा में जितने भी सीवर और पानी से सम्बन्धित कम्पलेंट्स हैं, शिकायतें हैं जो कि सुबह जब हम लोग अपने फोन पर बैठते हैं साढे सात, आठ बजे से लेकर और रात को जब हमारे हाथ में फोन होता है साढ़े आठ नौ बजे तक जब अन-नोन कॉल से फोन आता है तो ये ही है कि मैडम सीवर लाइन ओवर फ्लो कर रही है, सीवर लाइन ओवर फ्लो कर रही है। लेकिन मैं आज कुछ मुझे पांच और छः दिन से थोड़ा सा मुझे राहत मिली है। मैंने मुझे एक पत्र के लिए बोला गया था कि जितनी भी शिकायतें आपके यहां पर आ रही है तो उसमें तो मैं लिख भी नहीं पा रही लेकिन इतनी समस्यांए हैं अध्यक्ष जी। चार पांच रोज से थोड़ा सा हल्का सा हमें कुछ परसेंटेज आराम हुआ

है। लेकिन अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये सोल्यूशन है लॉँग टर्म सोल्यूशन हमें चाहिए। यदि हमने आज वो सीवर लाइन साफ करवाई है, उसको de-silting करवाई है तो अगले ही दिन नैक्स्ट डे हमारे पास फिर फोन आता है कि मैडम सीवर का पानी ओवर फ्लो कर रहा है। उदाहरण के तौर पर मैंने अभी आपको मैं कुछ बता रही थी कि तकरीबन एक 9 ब्लॉक सुभाष नगर में एक लाइन सीवर की ओवर फ्लो करने से उनके ड्राइंग रूम में बैडरूम में किचन में डेढ़ फुट पानी भरा हुआ है। मैं तकरीबन इसकी और जल बोर्ड को मैं लगातार शिकायत कर रही हूं कोई इसका सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। मेरा पूरा तिहाड गांव जहां कि 10 से 12 हजार लोग रहते हैं वहां पर संकरी-संकरी गलियां हैं चार-साढ़े चार फुट की। तकरीबन चालीस से पचास साल पुरानी सीवर लाइन है जब तिहाड़ गांव बसा था, लेकिन वहां के जो लोग है हर रोज डेली ये ही कहते हैं कि हमें एक बार सीवर का जो ओवर फ्लो होता है आप ठीक करवाते हैं नैक्स्ट डे फिर यहां पर सीवर ओवर फ्लो होता है। तो उनका लोगों का कहना है कि हमारा एक परमानेंट सोल्यूशन करवाया जाये क्योंकि वहीं से पानी की लाइन जाती है, वहीं से सीवर की लाइन जाती है। जब चालीस-पचास साल पुरानी सीवर की लाइन जो सीमेंटिड डली हुई है और वहीं से हमारी पाइप लाइन पानी की जा रही है तो उसमें रस्ट होने की वजह से लगातार गाद चॉक होने की वजह से पानी में वो कहीं ना कहीं मिल जाती है। लोगों के घरों में बदबूदार गंदा पानी आने से मेरा तिहाड़ गांव पूरा अक्सर मैं ये ही सुनती रहती हूं कि आज

किसी को लीवर में प्रोब्लम हो गई, आज किसी को गंदे पानी की वजह से टाइफाइड की प्रोब्लम हो गई। एक तिहाड़ गांव में मेरा कुछ एरिया ऐसा है बाल्मिकी बस्ती है वहां पर मतलब तकरीबन बहुत सालों से पानी की दिक्कत है क्योंकि वो टेल एंड पर है। लेकिन अध्यक्ष जी उसकी वहां पर टेल एंड जो है उस पर पानी पहुंचाने के लिए एक ओएलबी लगवाना है जिससे कि पानी प्रेशर से जाये। पीछे पानी की कमी नहीं है लेकिन वहां एक लाइन डालनी है वो लाइन काफी समय से मेरी पेंडिंग है, उसमें बहुत दिक्कत आ रही है। मेरे क्षेत्र में एम ब्लॉक में सुभाष नगर में चार सड़के हैं। हरि नगर में, फतेह नगर में एक छः सौ मीटर का लम्बा चोड़ा रोड है जोकि डेढ़ महीने से मैंने वहां पर खुदवाकर डाला हुआ है। एमसीडी से नया बनवाना है। वहां के लोगों का कहना है कि आप मैडम एक बार आप इसका ढक्कन उठाकर देखें। हमने जब वो ढक्कन उठवाये जेई और एई सभी मेरे अधिकारी जल बोर्ड के मेरे साथ गए, जब हमने ढक्कन उठाये तो उसमें उन्होंने सब्बल भी मारा जितने भी मेन होल थे वो इतना सैटल्ड था कि लोगों ने कहा कि आप रोड तो बनवा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मैडम हम चाहते हैं कि छः सौ मीटर की जो ये रोड है इसी में ये छोटी-छोटी गलियां सारी जुड़ी हुई है। मेन लाइन में वो हमारा मेन रोड है इसका पहले सबसे आप सीवर लाइन आप बदलवायेंगे हम तभी इसका आपको रोड बनवाने देंगे। ऐसे ही मेरी विधान सभा में एक जीरो नम्बर गली है बीई ब्लॉक। तकरीबन छः महीने से दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों ने

उसको खोदा था लेकिन वहां पर सीवर लाइन आज तक नहीं डाली। जेसीबी उसको तोड़कर चली गई। मजबूरन वो लोग वहां से निकलते हैं। वो वहां पर गिरते हैं। बहुत समस्या आई हुई है। पांच सड़कें ऐसी है जो एम ब्लॉक में, एमएस ब्लॉक में, सुभाष नगर में, तिहाड गांव में, फतेह नगर में, बड़ी-बड़ी खोदी हुई है। लेकिन लोग ठोकरे खाकर गिर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमें सड़क तो चाहिए लेकिन मैडम जो ये पानी और सीवर की लाइनें हैं इन दोनों मे से कम से कम आप एक लाइन इसको ठीक करवा दें। ऐसी ही हालत मेरी मायापुरी जेजे क्लस्टर में है। वहां पर फेज-II में जो पानी के टेंकर्स जो आते थे, अब कुछ समय से वहां पर पानी के टेंकर्स नहीं आ रहे हैं। ऐसी समस्याएं अनगिनत हैं। पूरा दिन मतलब लगातार तकरीबन दो ढाई तीन महीने से हमने लोगों को आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी पानी की लाईनें तो एक लाईन जो कि बैक लेन में दोनों सर्विस लाइन जाती हैं। contaminated water हो जाता है, लोगों के घरों में पहूंचता है। लोग बीमारियों से डरे हुए है। बहुत अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की बस एक मांग है हर जगह पर, हर ब्लॉक में पूरे विधान सभा में ये जो चालीस से पचास साल पुरानी सीवर लाईन है उसको मैडम बदलवाया जाये। मुझे कुछ उम्मीद नजर आ रही है क्योंकि हमने जो पत्र आपको दिया हुआ है शिकायत का उसके माध्यम से थोडा सा हमारा जो एक de-silting का काम था हल्का सा शुरू हुआ है। लेकिन लोगों का कहना है कि आज आपने de-silting करवा दी कल फिर ये चॉक हो जायेगा। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन करवाया

जाये, धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूं, मंत्री मैडम से कि कुछ ना कुछ हमारा सोल्यूशन आप जरूर करवायेंगी। धन्यवाद।

माननीया जल मंत्री (श्रीमती आतिशी): अध्यक्ष महोदय, राजकुमारी जी से भी हरि नगर की बहुत सारी कम्पलेंट्स आई थीं, जिसमें डब्ल्यूजेड-568 तिहाड़ विलेज, बी-121 हरिनगर, डब्ल्यूजेड-621 शिव मंदिर, तिहाड़ विलेज, बी-60 हरि नगर, 4/222 सुभाष नगर, ई/164 मायापुरी फेज-2, ए-175 ⁊तेह नगर, ए-74 पीली कोठी। इन सारी कम्पलेंट्स में दिल्ली जल बोर्ड ने सीवर मशीन्स के द्वारा ब्लॉकेज को हटाया है और रूटीन de-silting कर ली है। राजकुमारी जी ने ये कहा था कि काफी पहले इनकी विधान सभा में ठेके पर कर्मचारी हुआ करते थे, जो कई बारी अगर खास करके जैसे जो संकरी गलियां हैं वहां पर सीवर जाम हो गया तो कई बारी सिर्फ वहां पर जैटिंग करने के लिए वहां पर डंडों के माध्यम से ब्लॉकेज को क्लीयर करने के लिए काम करते थे लेकिन contractual workers को हटा दिया गया था। तो राजकुमारी जी ने कहा था कि उनकी आवश्यकता है। इसमें टेंडर इन्वाइट कर लिया गया है और 14 मार्च को इसकी ओपनिंग की डेट है। उसके अलावा कई जगह पर राजकुमारी जी ने सीवर की लाईन को रिप्लेस करने के लिए जो उनके पास ग्रेवांसेज आई थी, जिसमें ⁊तेह नगर ब्लॉक-1 सुभाष नगर, जनकपुरी के बी-ब्लॉक के कुछ हिस्से है और हरि नगर के ए-ब्लॉक के कुछ हिस्से। इसमें दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बताया गया है कि एलओआई स्टेज पर है और काम उसके बाद अवार्ड ऑफ वर्क के बाद शुरू हो जायेगा। ये अध्यक्ष महोदय मैं बता दूं

क्योंकि मुझे पता नहीं है कि हम सबकी प्रोब्लम्स ले पायेंगे कि नहीं ले पायेंगे। हालांकि रिपोर्ट आपके पास भी शेयर हो गई है। ये कल ही जब मैंने ब्रीफिंग ली थी इन सब मुद्दों पर तो इस ईशू को मैने ऑफिसर्स के साथ उठाया कि सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि टेंडर हो गया है या एलओआई पर आ गया है। इसकी कुछ स्पेशिफिक टाइम लाईन्स दी जायें और दिल्ली जल बोर्ड ने कोमिटमेंट दिया है कि वो एक अपडेटिड स्टेट्स रिपोर्ट देंगे जिसमें वो क्लीयरकट तौर पर बतायेंगे कि वर्क आवर्ड किस तारीख तक हो जायेगा, उसके बाद काम शुरू किस तारीख तक हो जायेगा और काम खत्म किस तारीख तक हो जायेगा और उन टाइम लाइन्स के हिसाब से हम इनकी मॉनिटरिंग करेंगे। राजकुमारी जी के यहां पर जो पानी की शार्टऐज और टेल एंड की समस्या थी तो वहां पर खजान बस्ती में आपके यहां पर एक नया बोरवेल किया गया है और बाकी एरिया में भी other works for improvement of water supply in the area are at NIT or award stage इसकी भी टाइमलाइन्स आपको दे दी जायेगी। पानी की सप्लाई में इनके यहां पर एमएस ब्लॉक में पानी की नई लाइन की आवश्यकता है, वो भी एलओआई स्टेज पर है। इसकी भी और डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। डी-ब्लॉक फतेह नगर से वेदिक मार्ग की भी सीवर लाइन बदलने की जरूरत है। ये टेंडरिंग प्रोसेस में है और इसकी भी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जायेगी।

माननीय अध्यक्षः अभय वर्मा जी।

श्री अभय वर्माः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जल बोर्ड के इस प्रस्ताव से पहले मैंने भी कई बार अपने विधान सभा क्षेत्र के समस्याओं को आपके बीच में रखा था।..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई विजेन्द्र जी ये कोई समस्या नहीं हुई।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं आप सीनियर है मैंने उनको बुला लिया, बाद में बुला लूंगा। अब समझ में नहीं आती बात। आपको हर वक्त कोई ना कोई समस्या खड़ी करनी है। बेमतलब समय खराब करना होता है सदन का। वो आप ही के साथी है।

श्री अभय वर्माः अध्यक्ष जी, पिछले चार साल से मैं लक्ष्मी नगर क्षेत्र का विधायक के रूप में काम कर रहा हूं। लेकिन अचानक चौथे वर्ष जल बोर्ड को लेकर सीवर लाइन को लेकर, पानी को लेकर इतनी बड़ी समस्या क्यों खड़ी हुई। इसके तह में भी जाने की आवश्यकता है। जब पहली बारिश हुई पिछले सीजन में पहली बारिश और वो रिकार्ड तोड बारिश हुई थी जो कि रिकार्ड पर है। उस बारिश के कारण अचानक सारे सीवर लाइन चॉक हो गए। जब मैं शकरपुर एरिया है हमारा एक वार्ड है, वहां का मैं दौरा किया तो वहां पर दौरा करने के दौरान पता चला कि इस वर्ष नगर निगम ने अपनी नालियों से गाद नहीं निकाले, जिसके कारण सारा पानी सीवर लाइनों में चला गया और चूंकि जरूरत से ज्यादा पानी चला गया इसलिए सारी सीवर लाइनें बैठ

गई। ये सर वहां के लोगों ने बताया और मेरे सत्ता पक्ष के साथी अभी मेरे पर नाराज होंगे क्योंकि इसी साल नगर निगम में आई थी इनकी सरकार और आने के बाद सरकार की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए अध्यक्ष जी, सच से सामना होना चाहिए सबका।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई देखिये।

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः नहीं जिम्मेदारी देखिये।

माननीय अध्यक्षः अभय जी मैं एक बात कह रहा हूं आपसे प्लीज। आपने अभी मेरे से शुरूआत अच्छी की। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी और सीवरेज की समस्या है। जो-जो जहां जिस कालोनी में सीवरेज की समस्या है, पानी की समस्या है, सीईओ भी बैठे हैं, सीएस भी बैठे हैं वो समस्या रखिये ना जी। आप दोषारोपण करेंगे..

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः नहीं-नहीं-नहीं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः आपकी किस कालोनी में सीवर जाम है बताईये।

श्री अभय वर्माः मैं समस्या का समाधान...

माननीय अध्यक्षः किस कालोनी में सीवर जाम है।

श्री अभय वर्मा: मैं बता रहा हूं लेकिन समस्या क्यों हुई..

माननीय अध्यक्ष: चलिए।

श्री अभय वर्मा: और समस्या का समाधान क्या है..

माननीय अध्यक्ष: अब इतना समय नही है।

श्री अभय वर्मा: वो भी हाउस में आना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: विजेन्द्र जी को भी बोलना है टाइम मैने पहले अनाउंस किया है।

श्री अभय वर्मा: मैं तीन चार मिनट में अपनी बात रख दूंगा सर। तीन चार मिनट में रख दूंगा। नालियों की सफाई नहीं हुई। गाद नहीं निकाले गए। पानी सीवर लाइन में गया, सीवर लाइन बैठ गया। उसके बाद आज सर जल बोर्ड घाटे में है। जल बोर्ड के पास मैन्टेनेंस के पैसे नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: आपकी विधान सभा में कोई समस्या नहीं है।

श्री अभय वर्मा: नहीं मेरी विधान विधान सभा में समस्या है।

माननीय अध्यक्ष: कोई समस्या है?

श्री अभय वर्मा: मुझे अधिकारी बताते हैं जी।

माननीय अध्यक्ष: नहीं समस्या है तो बताओ ना।

श्री अभय वर्मा: अध्यक्ष जी अधिकारी मुझे बताते हैं।

माननीय अध्यक्षः इसका मतलब कोई समस्या नही।

श्री अभय वर्माः अधिकारी बताते हैं कि हमारे पास मैन्टेनेंस के पैसे नहीं है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई आप मत बोलिये मैं देख रहा हूं अपने आप।

श्री अभय वर्माः समस्या ही तो बता रहा हूं सर।

माननीय अध्यक्षः अगर आपके विधान सभा में कोई समस्या है तो बताईये। नहीं तो बैठ जाइये। नहीं तो बैठ जाइये। अधिकारियों का बचाव मत करिये, मैं बहुत दुखी हूं।

श्री अभय वर्माः मैं किसी भी अधिकारी का बचाव नहीं कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः बचाव मत करिये अधिकारियों का।

श्री अभय वर्माः मैं जल बोर्ड के चेयरमैन..

माननीय अध्यक्षः बाद में आप चिल्लाते हैं मेरी विधान सभा.

श्री अभय वर्माः वाईस-चेयरमैन जलबोर्ड को मैं दोषारोपण लगा रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः मैं किसी भी दिन जल बोर्ड.....

श्री अभय वर्माः जल बोर्ड के चेयरमैन क्या कर रहे थे। जल बोर्ड के वाईस-चेयरमैन क्या कर रहे थे।

माननीय अध्यक्षः बैठिये आपको सब मालूम है।

श्री अभय वर्माः जल बोर्ड की मंत्री क्या कर रही थी। जल बोर्ड के मैम्बर क्या कर रहे थे।

माननीय अध्यक्षः बैठिये।

श्री अभय वर्माः अध्यक्ष जी, इतनी विकट स्थिति इस दिल्ली में क्रिऐट हुई है उसके कारणों को.

माननीय अध्यक्षः आप किसी कालोनी का नाम ले रहे है।

श्री अभय वर्माः आप भी स्थिति.

माननीय अध्यक्षः किसी कालोनी का नाम ले रहे है? नहीं जो पूछ रहा हूं, किसी कालोनी का नाम ले रहे है?

श्री अभय वर्माः मैं शकरपुर वार्ड पहले बताया हूं।

माननीय अध्यक्षः कालोनी का नाम बोलिये। शकरपुर वार्ड बहुत बड़ा है। कालोनी का नाम बोलिये।

श्री अभय वर्माः डी-ब्लॉक, सुन्दर ब्लॉक,..

माननीय अध्यक्षः हां, ये बोलिये न।

श्री अभय वर्माः गणेश नगर एक्सटेंशन मंडावली यहां तमाम एरिया हमारे चॉक पड़े हुए हैं और सिर्फ और सिर्फ अधिकारी ये कहते

हैं कि जल बोर्ड के पास अब मैन्टैनेंस के भी पैसे नहीं है। इस पर श्वेतपत्र क्यों नहीं सरकार लेकर आ रही है। जल बोर्ड नुकसान में क्यूं गया? अध्यक्ष जी अगर हम कारण पर नहीं जायेंगे तो हम समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। मैं एक बात और कहना चाहता हूं पानी पर। मैंने एरिया के नाम भी बता दिये सर। आपने मेरे को डिटेल में नहीं जाने दिया कोई बात नहीं। पानी की समस्या पर थोड़ा सा सुन लें। मंत्री महोदया ने बजट में कहा कि 840 एमजीडी पानी से हमने एक हजार नौ एमजीडी पानी कर दिया और साथ ही अपने बयान में उन्होंने कहा कि 09 लाख 34 हजार घरों में पानी देते हैं और लगभग 2422 किलोमीटर नए पानी लाईन डाल दिये। अध्यक्ष जी, लाईन डालने से कुछ नहीं होता है, पानी कैसे बढ़ेगा, पानी की मात्रा कैसे बढ़ाया जाये। दिल्ली में दो घंटे पानी सुबह और दो घंटे शाम में पानी देने के लिए पन्द्रह सौ एमजीडी पानी चाहिए। सरकार ने क्या कदम उठाये। आज नौ साल हो गए सिर्फ सौ डेढ सौ एमजीडी पानी बढ़ाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अपनी कमियों को नहीं देखना चाहती सरकार। सरकार ने पानी बढ़ाने के लिए क्या किये, पानी क्यों नहीं बढाया सरकार ने? आज हमारे क्षेत्र में ये स्थिति है अध्यक्ष जी पन्द्रह मिनट पानी नहीं मिलता, पन्द्रह मिनट पानी नही मिलता।

माननीय अध्यक्षः कालोनी का नाम बोलिये, कालोनी का नाम।

श्री अभय वर्माः कालोनी का नाम बता रहा हूं, डी ब्लॉक,

माननीय अध्यक्षः डी ब्लॉक कहां का?

श्री अभय वर्माः डी ब्लॉक लक्ष्मी नगर। जे एंड के ब्लॉक लक्ष्मी नगर। विश्वकर्मा पार्क लक्ष्मी नगर। एफ-ब्लॉक लक्ष्मी नगर। मंडावली का सेवा सदन, साकेत ब्लॉक और कष्टष्णा पुरी, गणेश नगर एक्सटेंशन, पांडव नगर का गणेश नगर एक्सटेंशन। पांडव नगर ए-ब्लॉक, बी-ब्लॉक, सी-ब्लॉक और एस-ब्लॉक इन सब जगहों अध्यक्ष जी पन्द्रह से बीस मिनट भी पानी नहीं मिलता। सरकार ने पानी नही बढ़ाया, दोष किसी और पर लगाये।

माननीय अध्यक्षः चलिये।

श्री अभय वर्माः मैं सीधा-सीधा सरकार को कटघरे में खड़ा करता हूं कि सरकार ने नौ साल कुछ नहीं किया। नगर निगम ने सफाई नहीं की। इसलिए ये स्थिति क्रिऐट हुई है।

माननीय अध्यक्षः बैठिये। श्रीमान ऋतुराज जी।

माननीया जल मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे साथी अभय वर्मा जी की बात का रिस्पोंस करना चाहूंगी। अभय वर्मा जी फिर ये अध्यक्ष जी के माध्यम से आपसे ये रिक्वेस्ट हैं कि जो आपने कॉलोनीज के नाम दिये, जहां पर पानी की समस्या है और सीवर की समस्या है अगर आप अध्यक्ष जी के माध्यम से एक बार मुझे वो डिटेल्स में पहुंचवा दें। जैसे मैंने कहा कि दुर्गेश पाठक जी ने जितनी स्पेशिफिक प्रोब्लम दी, स्पेशिफिक प्रोब्लम को रिसोल्व करना ऑफिसर्स के लिए थोड़ा ज्यादा आसान होता है। दूसरी बात, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली में पानी की आवश्यकता है। दिल्ली में जितनी तेजी से

आबादी बढ़ रही है और ये दिल्ली की नहीं अगर आप देखियेगा जो सभी मैट्रो शहर हैं, चाहे दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, बैंगलोर हो गया, जितनी स्पीड से आबादी बढ़ रही है उसकी मात्रा में और दिल्ली में खासकर ये समस्या है कि दिल्ली में अपना कोई वाटर रिसोर्स नहीं है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि कल हमारी रिव्यु मिटिंग जो हुई है इस पूरे मुद्दे पर तो चीफ सैक्रेट्री साहब ने पर्सनली जिम्मेदारी ली है कि ग्राउंड वाटर से हम दिल्ली के पानी की सप्लाई को कैसे augment कर सकते हैं। क्योंकि सैन्ट्रल ग्राउंड वाटर जो बोर्ड है उसकी रिपोर्ट है कि दिल्ली में काफी ऐसे एरियाज हैं और आपका जो एरिया क्षेत्र है वो उसमें शामिल भी है। जहां पर ग्राउंड वाटर की क्वालिटी भी अच्छी है और ग्रांउड वाटर का लेवल भी अच्छा है। तो ग्रांउड वाटर के माध्यम से हम दिल्ली के पानी की सप्लाई को कैसे augment कर सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी स्वयं चीफ सैक्रेट्री साहब ने ली है और सब एरियाज में जहां पर ग्राउंड वाटर से augment किया जा सकता है अलग-अलग प्रकार से पानी की treatment की जरूरत होगी। कहीं पर टीडीएस हाई है, कहीं पर अमोनिया हाई है तो उसके लिए ग्राउंड वाटर के लिए उपयुक्त अरेंजमेंट किया जाएगा। दूसरी हमारी ये भी बात हुई है कि क्योंकि अब गर्मियों को मौसम आ रहा है और खास करके अगर आपके यहां सप्लाई के पानी की कमी है तो ये भी हम explore कर लेंगे कि कहां-कहां बोरवेल शार्टटर्म में हो सकते हैं कि मीठा पानी कम से कम कुकिंग वगैरह के लिए एविलेबल हो लेकिन घर के बाकीयूजेज के लिए अगर बोरवेल का पानी भी उपलब्ध हो सके तो उससे मुझे

लगता है कि आपके एरिया की काफी समस्या सोल्व हो सकती है। आपने ये भी मुद्दा उठाया कि जल बोर्ड के पास मैन्टेनेंस के पैसे नहीं है। ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है कि पिछले एक साल से काफी ईशूज चल रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब हम चीफ सैक्रेट्री साहब से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि क्योंकि तीन अलग-अलग विभाग हैं जिनके coordination की आवश्यकता होती है जिसमें दिल्ली बोर्ड शामिल है, जिसमें अर्बन डव्लपमेंट डिपार्टमेंट शामिल है और जिसमें फाईनांस डिपार्टमेंट शामिल है। मुझे खुशी है इस बात की कि आज सारे अफसर यहां पर मौजूद भी हैं। अक्सर इस हाउस मे चर्चाए हमारी इम्पोर्टेंट मुद्दों पर होती है लेकिन एक भी अफसर ऑफिसर्स गैलरी में मौजूद नहीं होता। आज सारे अफसर यहां पर मौजूद हैं। तो हम चीफ सैक्रेट्री साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन तीनों विभागों में coordination करके ये ensure कर लें कि जो फंड मैन्टेनेंस के लिए चाहिए वो एविलेबल हो, जो फंड छोटे minor capital works के लिए चाहिए वो एविलेबल हो, जो फंड major capital works के लिए चाहिए वो एविलेबल हो। क्योंकि इस बारी, इस बात का मैं आश्वासन दे सकती हूं कि फंड की कमी नहीं है, बजट की कमी नहीं है, आने वाले साल में भी अभी कुछ ही दिन पहले हमने तकरीबन सात हजार दो सौ करोड रूपये का बजट दिल्ली जल बोर्ड के लिए पास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये coordination issues solve हो जायेगे तो ये समस्या कि मैन्टेनेंस के लिए पैसे नहीं है, ये समस्या भी जरूर रिजोल्व हो जायेगी। आप चिंता मत करिये वर्मा जी हम आपके भी इलाकों की

समस्याओं का समाधान करेंगे। आप ये मत सोचियेगा कि आप विपक्ष के विधायक हैं तो आप लोगों के इलाके की पानी की समस्याएं नहीं सोल्व होंगी।

श्री अभय वर्मा: मंत्री जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि कम से कम आपने संज्ञान में लिया जो बातें मैं कहना चाह रहा था। मैं एक बात सर बिल माफी पर बोलना चाह रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष: भई आपने जो भी देखिये...

...व्यवधान...

श्री अभय वर्मा: नहीं-नहीं, जल बोर्ड के बिल माफी पर बोल रहा हूं सर। ये सबसे जुड़ा हुआ समस्या है।

माननीय अध्यक्ष: मेरी एक बार बात सुन लीजिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: अभय वर्मा जी मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। जो भी कुछ आपने इन सब विधायकों ने लिख कर दिया है, आपकी जो भी समस्या है मुझे लिखकर दे दीजिए मैं चीफ सैक्रेट्री को भेजूंगा।

श्री अभय वर्मा: सर बिल माफी पर जो हाउस का समर्थन मिल जायेगा। पानी के बिल माफी पर बोलना चाह रहा हूं, दो मिनट सिर्फ।

माननीय अध्यक्ष: बोलिये।

श्री अभय वर्मा: मैं पिछले एक साल से सुन रहा हूं कि पानी के बिल को मफ किये जायेंगे कोई स्कीम लाने की बात चल रही है। सरकार से मैं आग्रह कर रहा हूं कि सबके बिल जीरो कर देना। ये स्कीम लायेंगे, स्कीम पास नहीं हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष: चलिए बैठिये।

श्री अभय वर्मा: अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। सबके बिल जीरो कर दो। बिल माफ हो जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष: बैठिये-बैठिये। ऋतुराज जी।

श्री ऋतुराज गोविन्द: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक हफ्ते पहले किराड़ी क्षेत्र के अंदर में जो लगातार पिछले कई महीनों से दिक्कतें आ रही थी उसको ले करके हमने आपको चिट्ठी दिया था, जिस विषय पर आज ये सदन बुलाया गया है। अध्यक्ष महोदय, किराड़ी क्षेत्र के अंदर में कम से कम 25 से 30 ऐसी कॉलोनीज है जहां पर या तो पानी पहूंच नहीं रहा है, पहूंच रहा है तो इतना गंदा पानी पहूंच रहा है जिसकी मतलब शिकायत लगातार बार-बार-बार की जा रही थी। जिन-जिन इलाकों के अंदर में गंदा पानी आ रहा था या पानी नहीं पहुंच रहा था वहां पर में उन लोगों को कम से कम पानी पहूंचाने के लिए हम लोग टैंकर का इस्तेमाल करते थे। पहले किराडी क्षेत्र में तीस टैंकर चलते थे जिससे सब तक कम से कम पानी पहूंचा पा रहे थे। अचानक पता नहीं क्या हुआ पिछले छः महीने के अंदर में वो तीस की संख्या को नौ कर दिया गया जिसके चलते एक तो पानी आ नहीं रहा था। गंदा

पानी आ रहा था और फिर टैंकर से भी जो पानी पहुंच पा रहा था वो पहुंचना बंद हो गया। जिसके चलते पूरा हा-हाकार मच गया। जो कालोनीज मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, खास करके ई-ब्लॉक, अगर नगर होली चौक से लेकर घोडी वाली कॉलोनी, गौरव नगर आनंद नगर, गौरी शंकर इन्कलेव, जनता इन्कलेव, सत्य इन्कलेव, हिंद विहार, हरि इन्कलेव पार्ट-1 (नजदीक एमएन पब्लिक स्कूल), कर्ण विहार पार्ट-4 (नजदीक ज्योती पब्लिक स्कूल) इसके साथ-साथ जो लगातार एक-एक, डेढ-डेढसाल से जहां समस्या चल रही है। बी-ब्लॉक इन्दर इन्कलेव फेज-1, जहां पर में पानी नहीं आता है। बलजीत विहार डी-ब्लॉक, 6 नम्बर गली से लेकर 10 नम्बर गली तक। बलजीत विहार ए-ब्लॉक (गली नम्बर 9 से लेकर के 12 तक) विद्यापति नगर ए-ब्लॉक (गली नम्बर 10 से लेकर के 17 तक) विद्यापति नगर बी-ब्लॉक पानी नहीं आता है।

उसके अलावा इंदर एंकलेव ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जी ब्लॉक में पानी की सप्लाई आती नहीं है। रमेश एंकलेव सी ब्लॉक पांच नंबर से लेकर के 15 नंबर गली तक पानी नहीं आता है। बी ब्लॉक अमन विहार बुद्ध चौक पर पानी नहीं आता है। कर्ण विहार पार्ट फोर सोम बाजार पर पानी का प्रेशर नहीं है, पानी नहीं आता है गली नंबर एक में। कर्ण विहार पार्ट 5 दो गली में पानी का प्रेशर नहीं आता है उसके अलावा रमेश एंकलेव गली नंबर 6 राजेश पवार गली नंबर 5 शनि बाजार रोड़ पानी नहीं आता है। प्रताप विहार पार्ट टू गली नंबर 4 नाले वाले रोड़ पर पानी नहीं आता

है। हरि एंकलेव पार्ट वन हरि हॉस्पिटल वाली गली में पानी नहीं आता है। ईई ब्लॉक एमएन स्कूल के पास हरि एंकलेव पार्ट वन में पानी नहीं आता है। बी ब्लॉक प्रेम नगर फर्स्ट में पानी का प्रेशर नहीं है। स्टेशन ब्लॉक प्रेम नगर फर्स्ट में पानी का प्रेशर नहीं है। नीति विहार गली नंबर 8, गली नंबर 11, गली नंबर 12 में पानी नहीं आता है। त्रिपाठी एंकलेव में पानी का प्रेशर नहीं है। जैड ब्लॉक नारायण विहार, प्रेम नगर सैकिण्ड में पानी नहीं आता है। जैड ब्लॉक प्रेम नगर सेकिण्ड गली नंबर 15 में पानी नहीं आता है। वाई ब्लॉक प्रेम नगर सैकिण्ड गली नंबर 9 से लेकर के 12 तक कटारिया रोड़ के राइट साइड में वकील चौक मेन नहर तक गली नंबर 9 से 12 तक में पानी नहीं आता है। जैड ब्लॉक प्रेम नगर सैकिण्ड गली नंबर दस एसएम पब्लिक स्कूल के पास पानी नहीं आता है। जैड ब्लॉक प्रेम नगर सैकिण्ड में पानी का प्रेशर नहीं है। जानकी विहार गली नंबर 6 से लेकर के गली नंबर एक, गली नंबर तीन में पानी नहीं आता है। यू टू ब्लॉक प्रेम नगर सैकिण्ड गली नंबर एक से लेकर छह तक में पानी नहीं आता है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, टी ब्लॉक प्रेम नगर सैकिण्ड सत्संग भवन में के बगल वाली गली में पानी नहीं आता है। वी ब्लॉक अवध विहार प्रेम नगर सैकिण्ड गली नंबर एक से तीन तक में पानी नहीं आता है। के ब्लॉक प्रेम नगर सैकिण्ड गली नंबर एक से लेकर तीन तक सत्तर फुटा की तरफ से पानी नहीं आता है। आई ब्लॉक प्रेम नगर सैकिण्ड गली नंबर दो में पानी नहीं आता है। जैड ब्लॉक 191 ब्लॉक एक्सटेंशन प्रेम नगर सैकिण्ड में पानी नहीं आता है। बी ब्लॉक प्रेम नगर सैकिण्ड

रेलवे लाइन की तरफ से गली नंबर छह से बाहर तक में पानी की समस्या है। यु वन धर्म एंकलेव, प्रेम नगर सैकिण्ड हिमालय पब्लिक स्कूल के पास डिस्पेंसरी के बगल हनुमान मंदिर के गली नंबर तीन में पानी नहीं आता है। डी ब्लॉक प्रेम नगर सैकिण्ड गली नंबर चार से सात में पानी नहीं आता है। यू ए शंकर विहार गली नंबर तीन आस्था विहार एफ ब्लॉक अगर नगर ई ब्लॉक, अगर नगर ए बी सी ब्लॉक हिंद विहार, गौरी शंकर एंकलेव वन टू थ्री प्रेमनगर थर्ड, डी ब्लॉक अगर नगर लक्ष्मी एक्सटेंशन, लक्ष्मी विहार एक्सटेंशन जनता एंकलेव प्रेम नगर थ्री, सत्य एंकलेव प्रेमनगर थ्री आदर्श एंकलेव, लक्ष्मी विहार, प्रवेश नगर बी ब्लॉक अगर नगर गली नंबर छह से लेकर ग्यारह तक पाण्डेय एंकलेव ए ब्लॉक सोम बाजार अगर नगर गली नंबर एक से लेकर ग्यारह तक उसके अलावा डी ब्लॉक अगर नगर ए ब्लॉक मीठा पानी ए ब्लॉक अगर नगर, विनय एंकलेव डी वन लक्ष्मी विहार। अध्यक्ष जी, इसमें सबसे इंपोरटेंट बात क्या है देखिए किरारी 99 प्रतिशत कच्ची कालोनी है एक सैकिण्ड एक सैकिण्ड, तीन दिन में जल बोर्ड पानी सप्लाई देता है, तीन दिन में एक बार ठीक है। तीस एमजीडी पानी का हमारा रिक्वायरमेंट है कम से कम और अगेंस्ट साढे आठ एमजीडी पानी मिलता है। चलो कोई बात नहीं है तीन दिन में पानी दे दो। दो घंटा पानी दे दो। कम से कम दे तो दो। साफ तो दे दो। ठीक है भई पानी बढ़ेगा तो हो सकता है मिलेगा। हम तो ये भी नहीं कहते रोज पानी दे दो। हम प्रवासी लोग हैं कच्ची कालोनी में बिहार यूपी के लोग रहते हैं तीन दिन में पानी मिलता है पानी नहीं पहुंच रहा है। पहुंच रहा है

तो गंदा पहुंच रहा है और जहां जहां गंदा पानी आ रहा था वहां कम से कम टैंकर से पानी दे पा रहे थे, इन्होंने क्या किया तीस टैंकर लगा हुआ था पता नहीं कौन सी पॉलिसी लेकर के आए तीस को घटाकर आठ कर दिया। जेई से लेकर ऐई से लेकर, बेलदार से लेकर के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर तक सब को उठा कर यमुनापार फेंक दिया और जो नया आदमी सब को लाकर बैठाया है उसको ये तक नहीं मालूम है कि वाल्व कहां से चलता है, कहां से क्या चलता है। त्राहिमाम मचा हुआ है चारों तरफ। अभी हंस रहे थे कई लोग आपको मैं बता दिया जो लिस्ट हमने दिया है एक एक की जा के जांच कराइए देखिए जाकर के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां राजनीति करने गए थे उनको जाकर पूछना चाहिए था, देखना चाहिए था कहां पानी आता है कहां नहीं आता है। अरे पानी बुनियादी चीज है अगर पानी भी नहीं दे सकते हैं तो हम क्या देगें बताइए। मैं तो इन अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं जो लिस्ट हमने अभी दिया है यहां पर में आप इसको जाकर के कम से कम रैन्डमली चैक कराइए चीफ सैक्रेट्री जाइए वहां पर ग्राउंड लेवल पर चैक करें तीन दिन में एक बार पानी देगें और वो भी नहीं देगें, पहुंचेगा नहीं, पहुंचेगा तो गंदा पानी पहुंचेगा। आप को मैं बताउं सत्तर फुटा रोड़ पर मेन पानी का लाइन टूटा हुआ है चार महीना हो गया उस पर गुल्ला ठोक दिया। गुल्ला मतलब होता है टैम्परेरी उसका सॉल्यूशन। उसका पाइप का टुकड़ा बदलना है छोटा सा टुकड़ा बदलना है। सड़क भी टूटा हुआ है उसके चक्कर में समझ रहे हैं और वो छोटा सा टुकड़ा नहीं बदल पा रहे हैं। मेन रोड पे लोग गिर रहे हैं गढढे में

गिर रहे हैं रिक्शा पलट रहा है सब हो रहा है ये स्थिति क्रियेट कर दिया है इन लोगों ने और पिछले एक सप्ताह से मैं आपको बताउं इस बात को भी एप्रिशियेट करता हूं पिछले एक सप्ताह से जब से ये मैटर मैडम ने रेज किया है आप लोगों ने इस सदन के अंदर आया है कुछ मेंटिनेंस का काम शुरू हुआ है। इस बात को भी हम एडमिट करते हैं कुछ शुरू जरूर हुआ है लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं ये लॉग टर्मस सॉल्यूशन तक जाए परमानेंट सॉल्यूशन हो कम से कम 50 गली ऐसा है जिसकी सड़क नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि पानी की लाइन बदलना है। लाइन नहीं बदल पा रहे हैं। तो विकट स्थिति है तो इसका समाधान हो मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहता हूं।

(समय की घंटी)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री महोदया।

माननीया जल मंत्री (श्रीमती आतिशी): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जो किराड़ी की इन्होंने पूरी लिस्ट दी है उसमें दिल्ली जलबोर्ड का एक्चुली एक ही रिस्पोंस है उन्होंने कहा है कि किराड़ी विधानसभा के अंतर्गत जनसंख्या लगभग 6.6 लाख है जिसके लिए 25 एमजीडी पानी की आवश्यकता है जबकि उपलब्ध 8.5 एमजीडी पानी की सप्लाई अच्छे दबाव पर प्रत्येक कालोनी में तीसरे दिन की जाती है। पानी की लीकेज एवं गंदे पानी की समस्या को दूर करने के लिए निविदा आमंत्रित की गई है जिसका वर्क ऑर्डर जल्द किया जाएगा। इसके अलावा पानी से वंचित क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए

टैंकरों से भी सप्लाई की जाती है। ये सभी समस्याओं पे यही आनसर दिया गया है किराड़ी की लेकिन क्योंकि इनमें से कई मुद्दे डिस्कस भी हुए थे कल जब हम अफसरों के साथ बैठे थे तो एक तो जैसे आपको जानकारी होगी कि दिल्ली में तीन एरियाज़ के लिए किराड़ी, बुराड़ी और संगम विहार के लिए तीन सीनियर ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दी गई है उनकी जो ओवरऑल समस्याएं हैं चाहे साफ सफाई की है, चाहे स्टार्म वाटर ड्रेंस की है, चाहे गलियों की है, चाहे पानी की सप्लाई की है तो एक बारी जो कंसर्न्ड ऑफिसर हैं उनको बुलाकर के स्पेसिफिकली किराड़ी की पानी की समस्या का क्या समाधान हो। दूसरी बात ये विधायक जी की बात बिल्कुल सही है कि इसमें से कई ऐसी चीजें हैं जो लाँग टर्म ठीक करनी होंगी क्योंकि अगर 25 एमजीडी पानी चाहिए और साढे आठ एमजीडी पानी आ रहा है तो पानी का क्राइसिस तो होगा ही लेकिन कम से कम हम ये एनश्योर कर लेगें कि जो टैंकर्स की आवश्यकता है किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में उन टैंकर्स की प्रोपर सप्लाई दी जाए, इंफैक्ट टैंकर्स की क्यूंकि कई विधायकों ने समस्या उठाई थी टैंकरों की समस्या पर मुझे आश्वासन दिया गया है दिल्ली जलबोर्ड की तरफ से कि सात दिन के अंदर अंदर अप्रैल के महीने में कितने टैंकर्स चाहिए सब एरियाज़ में उन टैंकर्स की लिस्ट बना ली जाएगी वो टैंकर्स की लिस्ट जैसे ही मेरे पास आती है मैं आपके माध्यम से सभी एमएलऐज के साथ शेयर भी कर लूंगी, तो वो अपना फीड बैक दे सकते हैं कि गर्मियों के हिसाब से जो टैंकर्स की रिक्वायरमेंट दिल्ली जलबोर्ड ने बनाई है क्या वो टैंकर्स की रिक्वायरमेंट

आपके एरिया के लिए पर्याप्त है कि नहीं है और मुझे ये लगता है कि जलबोर्ड को ये भी आदेश दिया जा सकता है मैं एक बारी बैठ भी जाउंगी उनके साथ कि टैंकर्स की रिक्वायरमेंट में छेड़छाड़ एमएलए से बातचीत किए बिना ना करें क्योंकि होता क्या है कि जब कहीं पे भी पानी नहीं आता तो ऐज एन एमएमए भी मुझे ये पता है कि सबसे पहले मेरे पर्सनल फोन पे ही फोन बजता है वो दिन का कोई भी टाइम हो वो चाहे सुबह साढे चार बजे हों, रात के दस बजे हों, दोपहर के दो बजे हों अगर कहीं पे पानी नहीं आएगा तो ये सभी विधायकों के साथ ये कहानी है कि सबसे पहले हमारे ही फोन पे फोन बजेगा। तो जो टैंकर्स की रिक्वायरमेंट है उसको विधायकों के साथ ही कंसलटेशन में फाइनलाइज किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, और जो बातें आपने रेज करी कि जो टैंडर्स की वो मैं आपको वो ओलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूं कि विद इन नैक्सट फयू डेज जो सारे टेंडर्स हुए हुए हैं आपके एरिया के उसमें टाइम लाइंस के साथ कि किस तारीख को अवार्ड होगा, किस तारीख को शुरू होगा और किस तारीख को काम खत्म होगा ये डिटेल्स भी स्पीकर साहब को प्रोवाइड कर दी जाएगीं।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान नरेश यादव जी।

श्री नरेश यादवः धन्यवाद अध्यक्ष जी जो आपने मुझे दिल्ली के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, जब भी सैशन यहां स्टार्ट होता है मैं अपने क्षेत्र महरौली की पानी की समस्या जरूर उठाता हूं। अभी तक के जितने भी सैशन हुए होगें उसमें मेरी पानी की समस्या जरूर होंगी। महरौली आप सब जानते हैं ऐतिहासिक

शहर है, कुतुबमीनार जो कि इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है ये हमेशा मैं बोलता आया हूं जब भी मैंने समस्या उठाई। अध्यक्ष जी, 2012 में मेहरोली में एक वाटर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ उसके बाद में उस वाटर प्रोजेक्ट में कुछ इंकवायरीज़ हुई सीबीआई इंकवायरी तक भी गई। 2015 में जब हमारी सरकार आई तो उसको दोबारा से रिस्टार्ट किया गया, रिस्टार्ट होने के बाद में मुझे उम्मीद थी कि मेरे पहले टैन्योर में जो 15 से 20 तक का था वो काम वहां पूरा हो जाएगा लेकिन 60 सत्तर परसेंट तक का वो काम पूरा हुआ और उसके बाद भी वो काम आज तक सैकिण्ड टैन्योर के भी चार साल चले गए हैं आज तक पूरा नहीं है। जो मेंटीनेंस डिपार्टमेंट है अध्यक्ष जी वहां पर क्योंकि लाइने डालने का काम चल रहा है और महरौली में चार नए यूजीआर बनाने का काम चल रहा है लेकिन वो यूजीआर भी बन गए एक यूजीआर का उद्घाटन भी हुआ 25 दिसंबर 2019 में लेकिन आज तक वो पूरी तरह से वहां ऑपरेशनल नहीं है जब कि आज महरौली की स्थिति ये है बहुत सारे हमारे विधायक साथियों ने यहां बात उठाई कि पानी दो दिन में आ रहा है, तीन दिन में आ रहा है। पानी जरूर आ जाए लेकिन मैं यहां आपके इस सम्मानित सदन में मैं बोल रहा हूं कि महरौली के अदंर कम से कम चार पांच दिनों में मैं मिनिमम बोल रहा हूं पानी आता है ऐसी स्थिति है जबकि कॉल मुझे तब करते हैं लोग जब उनके पास चार पांच दिनों के बाद भी पानी नहीं आता और मेंटीनेंस डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का ऐसा वहां पर एक झगड़ा चल रहा है कि दस साल जब उस कंपनी के प्रोजेक्ट कंपनी के पूरे हुए एमवीवी कंपनी

के, उस समय मंत्री हमारे मंत्री जी सौरभ जी थे तो वो कंपनी काम कंप्लीट नहीं कर पाई तो मंत्री जी से मैंने भी रिकवेस्ट की कि उस कंपनी को हटा दिया जाए, जो दस साल में पूरा नहीं कर पाई उसको हटा दिया गया। लगभग डेढ दो साल हो गए लेकिन आज तक प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ने कोई भी काम वहां पूरा नहीं किया। वहां की पानी की स्थिति एकदम खराब है। सीवर लाइनें क्योंकि सीवर का भी प्रोजेक्ट चला था, सीवर का एक फेज वन किया लाइनें डाल दीं out fall नहीं बनाए गए। उन लाइनों में लोगों ने सीवर की लाइनें जोड़ ली और आज पानी भरा रहता है। जो मेंटीनेंस डिपार्टमेंट है वो सीवर की सफाई नहीं करता। तो आज सोचिए कि वहां पर क्या हालात पैदा हो चुके हैं महरौली के अदंर। अध्यक्ष जी मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज पानी पे यहां चर्चा हो रही है और पानी के मुद्दे पे मुझे भी दो तीन बार बोलने का मौका दिया मंत्री जी का और आपका मैं धन्यवाद करता हूं। तो अध्यक्ष जी महरौली के लिए विशेष तौर पे कोई ऐसा पायलेट प्रोजेक्ट यहां पर हमारे सीनियर अधिकारी भी हैं कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो प्रोजेक्ट वाला मामला है वाटर का और सीवर का इसको एक बार पूरा कर दिया जाए, अब वो जलबोर्ड के हाथ में है। अब कोई कंपनी भी नहीं है जो कंपनी उसको कर रही है लेकिन जलबोर्ड के हाथ में आने के बाद बिल्कुल काम रूक गया है। कंपनी तो फिर भी कहीं ना कहीं हफ्ते दस दिन में 15 दिन में कोई लाइन डालती हुई नजर आती थी। लोग बताते थे कि आज हमारे यहां लाइन डल रही है लेकिन एक डेढ साल में बहुत बुरी हालत है। पानी पांच पांच छह छह

दिन में आ रहा है और जो उद्घाटन माननीय सीएम साहब ने 2019 में किया था वो आज किशनगढ़ यूजीआर बोलते हैं उसको ऑपरेशनल नहीं है तो उसकी स्थिति को ठीक किया जाए। ये दोनों लेटर मैंने अध्यक्ष जी आपको दिए थे, 9 तारीख में मैं बोला भी था इस पे। इसके अलावा अध्यक्ष जी हमारे क्षेत्र में मसूदपुर गांव और किशनगढ़ गांव की भी समस्या के लिए मैंने दिया है आपको रिटन में वहां पर भी जो वाटर लाइन और सीवर लाइन है वो बहुत पुरानी हो चुकी है और आज पुरानी होने की वजह से पाइप लाइन गल गए हैं, सीमेंट की सीवर लाइन थी उनसे पानी मिक्स हो के लोगों की बेसमेंट में जा रहा है। गंदा पानी उनको पीना पड़ रहा है जिससे वो बीमार हो रहे हैं। एक दो लाइन कहीं बदली जाती है लेकिन सारा एक पूरा का पूरा सिस्टम चेंज होने वाला वहां पर स्थिति है और एकदम से ये बहुत जरूरी जरूरी चीजें हैं जो मैंने चार पांच प्वाईंट पांच लैटर दिए थे, पांच लैटर जो इंपोरटेंट थे वो ही मैंने दिए थे इसके अलावा अध्यक्ष जी रजोकरी, रजोकरी भी एक ऐसा गांव है जहां पर फिल्टर पानी की कोई लाइन नहीं आती है 2019 में एक यूजीआर का उद्घाटन हुआ था पाइप लाइन पम्पिंग स्टेशन वगैरह होने का लेकिन वो यूजीआर बन के कंपलीट है। पाइप लाइन वहां पे डल चुकी है। द्वारका से पानी आना है और पम्पिंग स्टेशन में नई मोटर्स लग चुकी है हो सकता है उसकी वारंटी गारंटी भी समाप्त हो गई हो लेकिन अभी तक रजोकरी में पानी नहीं आया है, पानी का इंतजार कर रहे हैं कि भई कब पानी आएगा और क्योंकि फिल्टर लाइन है नहीं वहां पर टैंकर से सप्लाई है और टैंकर्स में भी

बहुत मारा मारी है। ट्यूब वैल्स करवाये हैं हमने कुछ लेकिन ट्यूब वैल भी पिछले काफी सालों से तो अब ट्यूब वैल लगने भी बंद हो गये हैं। कुछ ट्यूब वैल सैंक्शन पड़े हुए हैं, उनको भी नहीं लगाया जा रहा जलबोर्ड के द्वारा। अध्यक्ष जी, इसके अलावा एक बहुत बड़ा क्लस्टर कुसुमपुर पहाड़ी भी मेरे क्षेत्र में है उसकी स्थिति ऐसी है कि टैंकर्स भी सात दिन के बाद मिलता है एक परिवार को। वहां सारा का सारा पानी टैंकर से जाता है। लेकिन आज अगर टैंकर में पानी मिला तो सात दिन के बाद भरने को पानी मिलेगा उसको। सात दिन का स्टॉक वो लोग अपने जो कैन होते हैं उनमें भरते हैं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। एक बार साईकिल पे कैन ले जा के मैं उनके घर तक लेकर गया कि मैं देखूं कि ये कितनी मेहनत करके ये काम कर रहे हैं। तो अध्यक्ष जी, बहुत ही बुरा हाल है हमारे कुसुमपुर पहाड़ी में, वहां पर ट्यूब वैल्स के लिये भी मैंने काफी रिकवेस्ट दी वो नहीं हो रहे हैं। टैंकर्स भी सफिशियंट नहीं हैं। कम से कम टैंकर से ही दो तीन दिन में सप्लाई दी जाये। इसके अलावा अध्यक्ष जी मैंने कुसुमपुर पहाड़ी के लिये सजेस्ट किया था कि वहां एक यूजीआर बनाया जाये, एक पम्पिंग स्टेशन बनाया जाये। चाहे टैंकर से भी पानी उस यूजीआर में भर के वहां पर पाइप लाइन के द्वारा पानी दे दिया जाये लेकिन वो भी मैं काफी दिनों से उठाता हुआ आ रहा हूं लेकिन अभी तक कोई इसके उपर गौर नहीं है। अध्यक्ष जी महरौली की समस्या मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दिल्ली में पानी की समस्या सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी होंगी ॠतुराज भाई ने बताया काफी लंबी लिस्ट दी है मैं जल्दी जल्दी में

ऐसी लिस्ट नहीं बना पाया था उस समय क्योंकि मुझे बोलना भी था, मेरा नंबर भी आया हुआ था। तो अध्यक्ष जी, मैं भी जब डिटेल्ड लिस्ट दूंगा, मैं मंत्री जी को डिटेल्ड लिस्ट दूंगा इसी सारे काम में आप देखना कि मुझे लगता है कि 10 पेज की लिस्ट होगी अगर अलग अलग एरिया में दूंगा। महरौली विधान सभा में इंटर्नल आठ वाड्र्स हैं अध्यक्ष जी आठ वाड्र्स। जैसे हमारी विधान सभा में बड़े म्यूनिसिपल कारपोरेशन के तीन वार्ड हैं वहां पे आठ वार्ड, बहुत बड़ा एरिया है। मतलब महरौली विधान सभा की अपनी जनसंख्या कम से कम 5 लाख होगी, कम से कम जबकि वोट तो दो ढाई लाख के आस पास है। तो अध्यक्ष जी आपके माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन है हर बार इस सदन में हाथ जोड़ता हूं मैं कि महरौली की पानी की समस्या सेकिंड टैन्योर में एक साल बचा हुआ है उससे पहले पहले समाप्त की जाये, यही मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं और मंत्री जी से मैं ये भी निवेदन करता हूं कि एक विजिट भी मुझे दे दीजिये। जब आप विजिट करेंगे, लोगों से मिलेंगे, अधिकारियों के साथ जायेंगे तो रियल समस्या आपको ग्राउंड की पता चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री महोदया।

माननीया जल मंत्री (श्रीमती आतिशी): अध्यक्ष जी, नरेश जी ने पांच मुद्दे रखे थे तो एक तो उन्होंने कहा था कि मसूदपुर गांव में पुरानी सीवर की लाइन और पुरानी पाइप लाइन होने की वजह से पानी कटैमिनेटिड आ रहा है। तो मुझे ऐसा बताया गया है कि रूटीन मेंटेनेंस

हो गयी है वहां के एरिया की। लेकिन फील्ड स्टाफ को ये डायरेक्शन दे दी गयी है कि इंटेंसिव सर्वे किया जाये वाटर और सीवर नेटवर्क का और आने वाले साल का जो एनुअल एक्शन प्लान बन रहा है उसमें इसको उसके आधार पे जो पफील्ड सर्वे होगा उसके आधार पर शामिल किया जायेगा। तो मैं आपके माध्यम से विधायक महोदय को भी कहना चाहूंगी कि एक बारी जो उनके कंसर्न्ड एग्जैक्टिव इंजीनियर्स हैं उनके साथ ये भी फील्ड सर्वे करके उनको बता दें सो दैट आने वाले साल में इस काम को शामिल किया जा सके। रजोकरी गांव में ये कह रहे हैं कि अभी भी पानी की सप्लाई नहीं है इसमें the work for construction of 5.8ml capacity UGR at Rajokari Village is being executed. The physical progress of civil work is at 97% and E&M work is at 88%. The UGR sump is ready for testing. A new HT electric connection for operation of BPS is in process and in this regard, land has to be transferred to Power Department. The work is likely to be completed and commissioned by May 2024 subject to the availability of water. मेरे ख्याल से ये आखिरी लाइन ही सबसे इंपोरटेंट है कि अगर पानी की अवेलबिलिटी ही नहीं होगी तो यूजीआर बना के भी क्या होगा, पर जैसा मैंने आपको कहा ये दिल्ली की ओवरआल समस्या है और ग्राउंड वाटर के माध्यम से इसको हम टेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं अध्यक्ष महोदय कि अपर यमुना रिवर बोर्ड में भी हमारी काफी बातचीत चल रही है। दिल्ली ने हिमाचल के साथ एक एमओयू भी

साईन किया है कि जो हिमाचल का एक्सट्रा वाटर है वो दिल्ली उनसे खरीद सके नंबर वन, और दूसरा जो हथिनी कुंड बैराज से हमें 51 क्यूसेक पानी मिलता है इरिगेशन के लिये वो हमें इरिगेशन के बजाए ड्रिंकिंग वाटर के लिये अवेलेबल करवाया जा सके तो इन दोनों मुद्दों को भी हम लगातार टेकअप कर रहे हैं। अपर यमुना रिवर बोर्ड में भी अभी अपर यमुना रिवर कमेटी की भी बैठक हुई थी शेखावत जी की अध्यक्षता में, तो वहां पे भी इन इशुज को टेकअप किया गया है। infact GOI में भी मंत्री जी ने जो वहां पे उनकी सेक्रेटरी हैं उनको जिम्मेदारी दी थी और हमारे सीईओ साहब की शायद आने वाले हफ्ते में उनके साथ मीटिंग भी है इन इशुज को रिजॉल्व करने के लिये, सो हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली का सरफेस वाटर भी बढ़ेगा। लेकिन चूंकि सरफेस वाटर के लिये हम और राज्यों पे डिपेंडेंट हैं तो अभी ग्राउंड वाटर के माध्यम से दिल्ली की हम पानी रॉ वाटर ऑगमेंटेशन कैसे कर सकते हैं उसपे हम काम कर रहे हैं। जो आपकी कुसुमपुर पहाड़ी की समस्या है इसपे जलबोर्ड का कहना है कि ये समस्या टेक्निकल ग्राउंड पे सॉल्व करना ऐसा लगता है कि संभव नहीं है वहां पे पानी की लाइन देना, ये इन्होंने लिखित में दिया है लेकिन मुझे लगता है कि कोई न कोई दुनिया अब बहुत आगे पहुंच गयी है, कोई न कोई इसका समाधान तो हमें निकालना होगा नंबर वन। और नंबर टू, एक बारी आप इसका अगर हमें एनालसिस करके दे सकते हैं जलबोर्ड की टीम के माध्यम से कि वहां पे कितने पानी के टैंकर्स की आवश्यकता होगी कि हम कम से कम वहां पर रहने वाले लोगों को

एक डिग्निफाईड जिंदगी दे सकें कि जब तक हम वहां पे पानी की लाइन नहीं पहुंचा पाते तो कम से कम एक सम्मानजनक जीवन वहां के लोग जी पायें, उसके लिये कितने पानी के टैंकर्स की आवश्यकता है अगर आप जलबोर्ड की टीम के साथ बैठ के इसका कैलकुलेशन कर सकें तो ये प्रोवाईड करने की दिल्ली जलबोर्ड से पूरी कोशिश की जायेगी। जो आपका वाटर प्रोजेक्ट है उसका कांट्रेक्ट एग्रीमेंट 11 दिसम्बर 2022 को पूरा हो गया है। अब इस आने वाले वर्ष में इसको दिल्ली जलबोर्ड के बजट के माध्यम से किया जायेगा और इसका एस्टीमेट बोर्ड के सामने रखा जायेगा। ाइनली जो आपका सीवर प्रोजेक्ट है वो भी पेंडिंग कंप्लीशन है उसमें एक समस्या ये है कि कई कालोनिज़ शायद फोरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं तो कल जब हमारी रिव्यू मीटिंग हुई थी तब चीफ सेक्रेटरी साहब ने जलबोर्ड को ये डायरेक्शन दी है कि वो जो फारेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेने का प्रोसेस होता है उसको इनिशियेट करें क्यूंकि ऐसा पाया गया है कि जल बोर्ड के अधिकारी ये पहले से मान लेते हैं कि फारेस्ट डिपार्टमेंट की है तो वो हो ही नहीं सकती है। तो ये उनको कहा गया है, उनको आदेश दिया गया है कि वो परमिशन के लिये अप्लाई करें उसके बाद हम फारेस्ट डिपार्टमेंट से भी उसको टेकअप करेंगे। थैंक्यू।

माननीय अध्यक्षः बी.एस. जून जी।

श्री बी.एस. जूनः थैंक्यू सर। सर मैंने जो लैटर दिया था उसमें सबसे बड़ी इशु जो था वो राज नगर पार्ट में एक वार्ड है मेरा अनऑथोराइज कालोनी है उसका सीवर का था। कुछ मेंबर्स ने कहा कि

उनके यहां डिस्टिंक्ट इंप्रूवमेंट हुई है लेकिन मेरे यहां कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई। आज भी सीवर ओवरफलो कर रहा है, लोगों की नींव में जा रहा है, घरों में जा रहा हैं। गलियों में जा रहा है। आज ही मेरा एक रिसेंट वीडियो एक किसी ने भेजा। वो मैंने मंत्री जी को भी फारवर्ड किया था। हालत जस के तस हैं सर रत्ती भर भी इंप्रूवमेंट नहीं है। उसके अलावा सर दूसरे एरियाज़ हैं जैसे महिपालपुर है, वहां सीवर लाइन डाल दी गयी है लेकिन फुली कमिशनिंग आज तक नहीं हुई है। फिर सर दूसरा रंगपुरी है, सबसे वर्स्ट एरिया है विधान सभा का। सीएस साहब बैठे हुए हैं मैं उनसे रिकवेस्ट करूंगा कि एक दिन रंगपुरी को विजिट कर लें। हो सकता है उसके बाद आपको किराड़ी न जाना पड़े। तो सर बहुत ही खराब हालत है। तीसरे सर शाहबाद मोहम्मद्पुर रंगपुरी सालाहपुरी इनमें सीवर लाइन है ही नहीं सिर्फ इसलिये अटकी हुई है कि डीडीए ने अभी तक लैंड अलॉट नहीं की। दिल्ली जल बोर्ड तैयार है सीवर लाइन डालने के लिये लेकिन एसटीपी बनाने के लिये डीडीए ने लैंड अलाट आज तक नहीं की है, उन गांवों का भी बुरा हाल है। दूसरी बात सर मैंने टैंकर्स की थी कि जैसे हमारे यहां 17 जे जे क्लस्टर्स हैं सर जिनमें सिर्फ टैंकर्स से पानी भेजते हैं। टैंकर्स जैसे ऋतुराज भाई ने बताया था रिड्यूस कर दिये। इतने टैंकर कम कर दिये रमजान का महीना चल रहा है इवन उस टाईम भी हम उनको पानी नहीं दे पा रहे क्योंकि टैंकर ही नहीं हैं। तीसरा इशु है सर जैसे मंत्री जी ने बताया कि हम ग्राउंड वाटर से काम चलायेंगे। सर मेरे यहां 6 गांव हैं जो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। पिछले डेढ साल से जल बोर्ड ने ट्राईल

भेजी हुई है बोर सैंक्शन करने के लिये लेकिन आज तक उस फाइल पे कुछ नहीं हुआ। हर बार डीएम न्यू देहली उसको मीटिंग को पोस्टपोन कर देती हैं। तो अगर वो बोर भी हो जायें तो कुछ इंप्रूवमेंट लोगों को राहत मिल सकती है। तो सर यही तीन चार इशु थे बाकी जो डिटेल में मैं रिपोर्ट मंत्री जी को और आपको भी भेजूंगा कि कहां कहां पानी की दिक्कत है और कटैमिनेटिड वाटर की दिक्कत है। थैंक्यू वेरी मच सर।

माननीय अध्यक्षः विजेंद्र गुप्ता जी। अच्छा जवाब दे रही हैं माननीय मंत्री जी, ठीक है।

माननीया जल मंत्री (श्रीमती आतिशी): जो आपकी बोरवेल वाली समस्या है उसपे स्पेस्फिकली हमारी जो जून साहब ने रेज करी है उसपे हमारी चर्चा भी हुई थी और मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को रिकवेस्ट किया है कि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ कोआर्डिनेट करके इसको तुरंत करवा दें सो दैट बोरवैल के साथ कम से कम जो एक शार्ट टर्म में क्रासिस है वो पूरा हो जायेगा। बाकी जो जून साहब ने कहा कि उनके यहां अभी भी कंप्लेट्स रिजॉल्व नहीं हुई हैं तो उनको आने वाले टाईम में हम टेकअप कर देंगे।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः देखिए, एक सेकिंड, महेंद्र जी बैठिये। मैं ये समझता हूं सभी माननीय सदस्यों के यहां समस्यायें हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः दो मिनट, दो मिनट बैठिए प्लीज। विषय आज हैल्थ का भी है। मेरी थोड़ी प्रार्थना सुन लीजिए एक बार। थोड़ा-सा प्रार्थना सुन लीजिए। मेरे पास गुलाब सिंह जी की चिट्ठी आई है, शिव चरण गोयल जी की आई है, प्रलाद सिंह साहनी जी की आई है। मैं इसके अलावा सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ एक बार पॉइंटवाइज दो मिनट जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है मेरे पास भी जवाब आये हैं। सभी को बोलने का समय दूं तो कम से कम 5 दिन का सेशन चलाना पड़ेगा। साहनी जी दो मिनट रूकिये। मेरे पास लिखित में समस्या भेज दीजिए और लिखित में उसका जवाब आपके पास आयेगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः साहनी जी मुझे लिख के..

...व्यवधान...

श्री प्रलाद सिंह साहनीः एक-एक जेईई एक्सट्रा लगाया है। हमारे उस जेईई को दे दें। मटियामहल में जेईई लगाया है। बिल्लीमारन में जेईई लगा है। चांदनी चौक में क्यो नहीं लगा फिर?

माननीय अध्यक्षः प्रलाद जी बैठिए प्लीज।

श्री प्रलाद सिंह साहनीः सर मेरी एक छोटी-सी समस्या है।

माननीय अध्यक्षः मेरे साथ समझौता करके चलिए। मेरी प्रार्थना है।

श्री प्रलाद सिंह साहनीः अजीमुल हक ने जान के, हक साहब ने शरारत की है। चांदनी चौक जामा मस्जिद का एरिया है। उसके अंदर एक जेईई पुराना इनको एक महीने के लिए सारे वार्डों में दिया है।

माननीय अध्यक्षः साहनी जी मुझे लिख के दीजिए। प्लीज मुझे लिख के दीजिए।

श्री प्रलाद सिंह साहनीः चांदनी चौक में क्यों नहीं दिया है। बस ये ही कहना अध्यक्ष जी मुझे। जो है वो जानके ऐसे काम कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैं बात नहीं कर सकता। एक बार कोई व्यवस्था है पार्टी की, पार्टी की कोई व्यवस्था है।

सुश्री भावना गौड़ः सर हाउस को बढ़ा दो। हम अपनी बात तो रखें कम से कम अपनी। इतना गंभीर विषय है। केवल तीन विधान सभा ही ऐसी हैं जिसमें पानी नहीं है। बाकि की विधान सभा।

माननीय अध्यक्षः भावना जी बैठिए प्लीज। प्लीज बैठिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप बैठिए, मैं करता हूँ, बात करता हूँ।

श्री विजेंद्र गुप्ताः धन्यवाद स्पीकर महोदय। आज एक रेजुलेशन सदन के समक्ष रखा गया है। उस पर मैं अपनी बात कहने के लिए

खड़ा हुआ हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी मैं सदन का ध्यान कुछ मूलभूत ऐसी व्यवस्थाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिनमें बदलाव से स्थिति में सुधार होगा। सत्येन्द्र जैन जी जल मंत्री थे तो उन्होंने एक आदेश जारी किया कि 50 लाख से ऊपर की जो है एलोकेशन है उसका अप्रूवल मंत्री से लेना होगा। उसके बाद सौरभ भारद्वाज जी जल मंत्री बने और उन्होंने एक आदेश जारी किया कि एक रूपए का भी एलोकेशन अगर होगा तो उसकी अप्रूवल मंत्री से लेनी होगी। सर 10 हजार करोड़ रूपए का बजट है सालाना। तो लगभग 20 हजार फाइलें बन जाती हैं कम से कम। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि मंत्री के पास अगर 20 हजार से ज्यादा फाइल ऐलोकेशन की आयेंगी, अगर मान लीजिए एक गली में सीवर चेंज होना है तो वो जब तक मंत्री जी उसको अप्रूवल नहीं देंगे। यानि कि प्रक्रिया इतनी जटिल हो गई कि काम जो है वो कहीं ना कहीं उस पर उसका असर आ रहा है। पिछले 9 साल में कैपिटल एक्सपेंडिचर 25 हजार करोड़ रूपए हुआ है। 25 हजार करोड़ रूपए जल बोर्ड ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो स्थिति 9 साल पहले थी कि 50 परसेंट पानी या तो लीकेज में जा रहा है या चोरी हो रहा है। 9 साल में 25 हजार करोड़ खर्च करने के बाद भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम एक परसेंट पानी को भी चोरी या लीकेज से नहीं ठीक कर पाये, यानि कि उसको 49 परसेंट पर भी नहीं ला पाये तो इसमें सरकार को एक बार बताना होगा कि 25 हजार करोड़ रूपया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पर हुआ और किस प्रकार से आज

storm water drain और सीवर ये inter connected हैं। जहां सीवर ऑवरफ्लो होता है उसे storm water drain में डाल दिया जाता है। जहां स्टार्म वाटर ड्रेन का आउटफॉल नहीं है वो सीवर में मिला दी जाती है और इसके कारण स्थिति बद से बद्दतर हुई है। Master Plan for Storm Water Drain सरकार ने वायदा किया था कि हम लायेंगे, लेकिन वो सरकार ने अभी तक और आम आदमी पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो 25 साल से ये बात बार-बार रिपीट की गई कि मास्टर प्लान ग़ॉर ड्रेनेज और storm water drain पूरी दिल्ली एक एजेंसी के पास होगी। आज हो क्या रहा है कि multiplicity of अथोरिटी इस कदर है।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी इसमें 5 साल पुरानी बीजेपी की भी सरकार जोड़ लीजिए।

श्री विजेंद्र गुप्ताः चलिए मैं तो कहता हूँ आप और पीछे का भी ले लीजिए। 40 साल का ले लीजिए। 85 से ले लीजिए। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आखिर ये Master Plan for Storm Water Drain कब आयेगा? क्या ये किसी एक एजेंसी के अंडर हो सकता है? अगर Master Plan for Storm Water Drain एक एजेंसी के अंडर होगा तो निश्चित रूप से मास्टर प्लान बनेगा और एक एजेंसी के पास होगा। तो निश्चित रूप से सोल्युसन होगा। अभी इतनी सारी समस्यायें सामने आ रही हैं। मैं तो चाहता हूँ कि सरकार जल बोर्ड से संबंधित एक व्हाइट पेपर जो है श्वेत पत्र जारी करे कि आखिर हम कहां खड़े हैं। हम सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते हैं। इसके साथ-साथ मैं

ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार ये बताये कि ये बोर्ड व्यवस्था क्या है? दिल्ली जल बोर्ड ये एक तरह का ऑटोनोमस बोर्ड है। गवर्मेंट उसको सिम्पली फंडिग कर रही है। 10 हजार करोड़ का आपका सालाना बजट है जिसमें से आपने 2023-24 के बजट में 6,065 करोड़ रूपया फंडिंग आप करेंगे और 3500 करोड़ के करीब जल बोर्ड का रेवेन्यु, यानि कि रेवेन्यु पक्ष अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 35 परसेंट भी नहीं है। अब बोर्ड फैसले लेता है। बोर्ड के चेयरमेन हैं, बोर्ड के मेंबर्स हैं, बोर्ड बैठता है, बोर्ड सारी चीजों को डिसाइड करता है। गवर्मेंट एक एक्सटर्नल एजेंसी है। एस्सटीरियर है वो। इंटीरियर नहीं है। जल बोर्ड का पूरा या तो आप जल बोर्ड बोर्ड भंग कर दीजिए। इसको भी सरकार का एक डिपार्टमेंट बना दीजिए और डिपार्टमेंट फिर पूरी तरह सरकार के अंडर होगा तो सरकार अपनी जिम्मेदारी बोर्ड के ऊपर, बोर्ड अपनी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर अगर डालता रहेगा तो ये कोई solution इसमें होगा नहीं। इसके लिए जरूरी है कि हम इस पर अब जल बोर्ड की स्थिति देखिए। बैलेंस शीट ही नहीं बन रही है। ऑडिट तो बाद की बात है। बैलेंस शीट नहीं है। 2020-21 के बाद बैलेंस सीट नहीं बनी। 21-22, 22-23 और अब 23-24 चल रहा है, तो जब पैसे का लेखा-जोखा ही नहीं है, हिसाब किताब नहीं है। 500 करोड़ रूपया एक्शन प्लान के लिए रख दिया, पर एक्शन प्लान है क्या? डिटेल्ड कहां है उसके, डिटेल्स कहां है? उसकी डिटेल्स ही नहीं है। कोई प्लान नहीं है। कोई फ्यूचर एक्शन नहीं है तो कुल मिलाकर के जल बोर्ड में बड़ा भारी मैस है। मैं सरकार की तारीफ नहीं कर रहा

हूँ लेकिन आज का जो ये डिस्कसन है इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि बोर्ड की कितनी डिमांड पेंडिंग है। बोर्ड को जो grant किया, फंडिंग जो आपने करनी है जो बजट में provision हैं उसमें अधिकारी बीच में कहां से आते हैं और अगर बोर्ड अपने फाइनेंशियल irregularities को छुपाकर सिर्फ वन वे पैसा लेता जा रहा है और उसका कोई हिसाब किताब सरकार को नहीं दे रहा है तो क्या सरकार इसपे विचार नहीं करना चाहिए सरकार को कि जल बोर्ड किस दिशा में बढ़ रहा है। हम हर चीज को अगर राजनीतिकरण कर देंगे तो हमें लगता है कि हम स्थिति को सुधारने में पूरी तरह से ना कामयाब हो जायेंगे। अभी हम बड़ी हैरानी की बात है देश की राजधानी में हमारे माननीय सदस्य हाथ जोड़के प्रार्थना कर रहे हैं कि 7 दिन में तो एक बार पानी दे दीजिए। ये सुनकर.. मुझे लगता है मेरी कोई relevance नहीं है एक मेंबर के रूप में कि हम कर क्या रहे हैं, हम खड़े कहां हैं। 7 दिन में अध्यक्ष जी अगर कोई क्षेत्र के लोग पानी मांग रहे हैं अभी हमारे उन्होंने ऋतुराज जी ने पूरा एक लम्बा लेखा-जोखा दिया। तो प्रश्न ये है कि हमें आत्म मंथन करने की जरूरत है कि हम खड़े कहां हैं और हमें करना क्या है और रास्ता क्या है हमारा। मेरे पास जो जानकारी आयी है मैंने जो जानकारी जुटायी है। पिछले सप्ताह तक जब आपने ये स्पेशल सेशन किया तो मात्र 200 करोड़ रूपया सरकार के पास जल बोर्ड की डिमांड पेंडिंग थी। अब कुछ ज्यादा हो गई होगी। अब 500 हो गई होगी, 700 हो गई होगी और एक हफ्ते में। लेकिन सरकार दे पैसा। लेकिन सवाल ये है क्या ये सिर्फ 200 करोड़ की वजह से काम

रूक रहे हैं क्या? आप मंत्री की ऐलोकेशन अप्रूवल को हटाइये। 5 करोड़ रूपए कीजिए, 10 करोड़ रूपए कीजिए, कोई पॉलिसी पे वर्क के लिए कीजिए, लेकिन अब अध्यक्ष जी मैं आपके सम्मान में आप अध्यक्ष हैं, हम सबके पैट्रॉन हैं आप। मान लीजिए मैं आपके मानो ओ.पी. शर्मा जी आपके मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ इसलिए कि कोई पॉलिटिक्स ना हो। ओ.पी. शर्मा जी आपके बराबर के क्षेत्र में विधायक हैं। इन्होंने जाके अधिकारियों पे दवाब बनाया और पानी इन्होंने अपने एरिया में बढ़वा लिया। आप स्पीकर हैं आपको डैकोरम मेंटेंन करना है आप अपने क्षेत्र के लिए तो सवाल ये है कि distribution of water वो हम क्या उसके लिए कोई हमारा नीतिगत आधार है। मेरे क्षेत्र में, मैं भी क्षेत्र की बहुत सारी चीजों को यहां लिख के लाया हूँ।

माननीय अध्यक्षः वो मुझे राइटिंग में दे दीजिए विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेंद्र गुप्ताः हाँ जी, हाँ जी मैं शॉर्ट में करूंगा।

माननीय अध्यक्षः नहीं राइटिंग में दे दीजिए मुझे प्लीज।

श्री विजेंद्र गुप्ताः अब पॉकिट सी-8 है बी-5 है ए-1 है सेक्टर-8 पानी ही नहीं आता।

माननीय अध्यक्षः मैं रिक्वैस्ट कर रहा हूँ आप मुझे राइटिंग में दे दीजिए।

श्री विजेंद्र गुप्ताः मैं राइटिंग में दे दूंगा।

माननीय अध्यक्षः वो ज्यादा उचित रहेगा।

श्री विजेंद्र गुप्ताः मैं राइटिंग में दे दूंगा लेकिन अगर।

माननीय अध्यक्षः नहीं समय की फिर आप कहेंगे समय नहीं देते हैं।

श्री विजेंद्र गुप्ताः ठीक है मैं उसपे नहीं बोल रहा। मैं खत्म कर रहा हूँ अपनी बात को। जिस लाइन पे मैं जा रहा था मैं उस लाइन पे आकर वापस अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। हम अल्टीमेटली अगर आज सदन में हर मेंबर के पास समस्याओं का अम्बार है, तो उसकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है ये। ये जनता जब त्राहिमाम, त्राहिमाम करती है तो ये चीजें सामने आती हैं। मेरा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि आपने स्पेशल सेशन किया, एक दवाब बना। 5 दिन में समस्याओं का समाधान कुछ आगे बढ़ा। लेकिन मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इसका कोई परमानेंट सोल्युशन बनाइये कि हमें इस तरह दवाब बनाके काम ना कराना पड़े। सरकार जिम्मेदारी को ओटे, व्यवस्था को ओटे। आज सदन में चीफ सेकेट्री साहब हैं सीईओ हैं और बाकि एडिशनल चीफ सेकेट्री साहब हैं बहुत सब लोग हैं लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ उनके यहां होने से हमें क्या लाभ हो रहा है? वो सदन की इस कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते जवाब तो आपको ही देना है। आज भी जवाब आप दे रहे हैं, कल भी जवाब आप देंगे। उस दिन भी जवाब आपने ही दिया था कि अधिकारियों को बुलायेंगे। तो सवाल ये है जब जिम्मेदार आप हैं, कार्रवाई आपको करनी है तो फिर ये इस तरह का प्रपंच करने से समस्यायें हल नहीं

होंगी। ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं सरकार की अपनी कमी है जिसके कारण ये परिस्थितियां बन रही हैं। धन्यवाद।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः जरनैल सिंह जी,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं प्लीज मैं हाथ जोड़के रिक्वैस्ट कर रहा हूँ। मैंने किसी एक को दिया ना मुझे 20 को देना पड़ेगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं एक गुलाब जी आप लिख के दीजिए मुझे। अगर समस्या का हल चाहते हैं मुझे लिख के दीजिए प्लीज। मैं बार-बार रिक्वैस्ट कर रहा हूँ। मैं अब समय नहीं दूंगा। जरनैल सिंह जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः उनके जवाब मेरे पास आ गए हैं मैं भेजूंगा। इतना समय नहीं है कि मैं सबको बुलावा लूं। कम से कम 15 विधायकों के लिख के आये हैं। जरनैल जी अंतिम है ये।

श्री जरनैल सिंहः थैंक्यू स्पीकर साहब आज जिस तरीके से सदन के अंदर दिल्ली वालों की हर दिन की समस्याओं का जो पानी और सीवर से संबंधित है हल किया जा रहा है ये अपने आप में काबिल-ए-तारीफ है। दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों के हमारे साथी

अपनी समस्याओं को बता रहे हैं और मंत्री महोदय खुद एक-एक इशु को address कर रही हैं और अधिकारी भी यहां मौजूद हैं तो अपने आप में एक अच्छा संदेश भी इससे जा रहा है। स्पीकर साहब मैंने भी अपने इलाके की जो प्रोब्लम्स बतायी थीं मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि मेरे एरिया के अंदर एच-2 ब्लॉक विकासपुरी और एच-1 ब्लॉक विकासपुरी गली नंबर 5 से 7 तक कृष्णा पार्क, गली नंबर 14 संतगढ़, गली नंबर 21 संतगढ़, गली नंबर 24 संतगढ़, 7 और 8 ब्लॉक तिलकनगर, 69 और 70 ब्लॉक अशोक नगर, गली नंबर 2 और 3 बेस्ट ब्लॉक, डब्लु जेड 11 से लेकर डब्लु जेड 12 बी तक, कृष्णापुरी केजी 3 में 60 नंबर से लेकर 90 नंबर तक इसके बाद डी 171 से डी 256 तक सीवर की लाईन की दिक्कत है इसके पहले वाले सारे पानी के ईशु थे। इसके बाद गली नंबर 2, 3, 4, 5 और 11 संतगढ़, सी 131 से लेकर सी 122 तक गणेशनगर इसके बाद ई 1 से लेकर ई 40 नंबर तक तिलक बिहार में, इसके बाद स्पीकर साहब ए/1ए विकासपुरी एक्सटेंसन गली नंबर 14 और 15 संतगढ़, आर जेड ब्लॉक में विष्णु गार्डन में पानी की दिक्कत चल रही है और इसके बाद सीवर की लाईन चेंज होनी है Ajay Enclave डी ब्लॉक के अंदर जिसमें मकान नंबर डी 102 से लेकर 112 तक शामिल हैं। इसके बाद हाउस नंबर 177 टू 197 तिलक बिहार और इसके बाद सी ब्लॉक में ही पानी की भी दिक्कत चल रही है, गणेश नगर में सी 11 से सी 19 तक। उसके बाद एच 1/52 एच 1/82 तक विकासपुरी के अंदर जो ब्लॉक है वहां सीवर की दिक्कत चल रही है। लाईन ओवरफ्लो हो रही है। जे

जी 2 ब्लॉक विकासपुरी के अंदर मकान नंबर 760 से लेकर मकान नंबर 744 तक पिछले काफी दिनों से गंदे पानी की दिक्कत आ रही है। एच1 35 से लेकर एच1 51 तक सीवर का ओवरफ्लो की दिक्कत काफी दिनों से आ रही है। संतगढ़ और पष्टथ्वी पार्क गली नंबर 7 पष्टथ्वी पार्क और गली नंबर 20 संतगढ़ में पानी की लाईन की दिक्कत चल रही है। पानी की सप्लाई की दिक्कत चल रही है। गंदे पानी की दिक्कत चल रही है। 5बी 16 टू 5बी 18 सीवर की लाईन काफी समय से बता रहे हैं चेंज होने वाली है पर हो नहीं पा रही। स्पीकर साहब इसके बाद जे.जी. 3 ब्लॉक विकासपुरी और इसके बाद 23 ब्लॉक तिलकनगर यहां सीवर की काफी लम्बे समय से समस्या चल रही है और एक चीज अप्रीशिएबल है स्पीकर साहब बड़ी-बड़ी 3 जगह पर तिलकनगर विधान सभा क्षेत्र में पानी की लीकेज चल रही थी जिसमें नजफगढ़ रोड लाला गणेशनाथ खत्री मार्ग और डिस्ट्रिक सेंटर के पास 3 मेन पॉइंट थे तो तीन में से 1 पॉइंट पे रिपेयर हो गई है और मेरे को बताया गया कि बाकि के जो 2 पॉइंट हैं उन पर भी आज कल में रिपेयर शुरू हो जायेगी। तो जो बदलाव पिछले एक हफ्ते में देखने को मिला है उसपे तो तसल्ली है पर ये आगे चालू रहे और हर काम की समय-सीमा हमें बता दी जाए स्पीकर साहब क्योंकि बहुत लम्बे टाईम से हमारे को बताया जा रहा है कि ये चीजें प्रोसेस में हैं। इस वजह से नहीं हो पा रहीं, उस वजह से नहीं हो पा रहीं। पर सबसे बड़ी बात ये ही होगी कि इन सभी कामों की एक समय-सीमा हमारे को बता दी जाए। 34 काम मोटे तौर पर मैंने यहां पर बतायें हैं स्पीकर

साहब। इसके अलावा तिलकनगर जो मेन कॉलोनी है वहां पर काफी समय से शुरूआत से दो टाईम पानी की सप्लाई आती थी, पिछले कुछ महीनों पहले वहां एक समय की सप्लाई कर दी गई और बताया गया कि जब मायापुरी यूजीआर चालू हो जायेगा तो उसको फिर से दो समय की सप्लाई बहाल कर दी जायेगी। पर वो अभी तक नहीं हूई। स्पीकर साहब, उसपे मैं चाहता हूँ कि उसकी भी समय-सीमा हमें बताई जाए। इसके अलावा हर वार्ड में एक-एक डिसेल्टर मशीन सब जगह है मेरी आस-पास की विधान सभाओं में भी, मेरी विधान सभा में तीन वार्ड हैं और सिर्फ दो डिसल्टर मशीन है। एक डिसल्टर मशीन बढ़ाई जाए। 1500 लीटर वाली बुलेरो एक मशीन की जरूरत है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट वाली लेबर ना होने की वजह से पिछले काफी समय से दिक्कत चल रही है तो उस लेबर का भी अरेंजमेंट कराया जाए। मेरे को बताया गया कि टेंडर उसका हो गया है। पर उसको सुनिश्चित कर दिया जाए कि इतने दिन के अंदर लेबर आ जायेगी। क्योंकि बहुत सारे काम लेबर ना होने की वजह से ही रूके पड़े हैं। इसके अलावा जो शुरू में बात की गई थी कि एमसीडी की ड्रेन और सीवर तो मैं अगर अपनी विधान सभा की बात करूं तो मैक्सिमम एमसीडी की ड्रेन्स का लोड सीवर के ऊपर ही है। इसका भी कोई परमानेंट सोल्युशन निकाला जाये। क्योंकि अच्छा नहीं लगता पब्लिक को हम जाके बोलें वो अब बोलते हैं जी एमसीडी भी आपकी है, दिल्ली सरकार भी आपकी है तो उसका समाधान निकाला जाए। दोनों डिपार्टमेंट आपस में बैठकर कोई ना कोई हल निकालेंगे तो जरूर निकल जायेगा और बात बार-बार पानी की

हो रही है, थोड़ा-सा रूख में नरमी भी दिख रही है और पानी तो अपने आप में सारी दुनिया जानती है कि पानी की तरह बन जायेंगे तो रास्ता अपने आप निकल जायेगा। पत्थर की तरह ना बनें। बहुत सारे पत्थर रास्ता रोकने के लिए पड़े हैं पर सारे पानी की तरह बन जायेंगे तो रास्ता अपने आप निकल जायेगा। थैंक्यू स्पीकर साहब।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री महोदया।

माननीया जल मंत्री (श्रीमती आतिशी): जो जरनैल भाई ने लिस्ट हमें दी थी और आज जो पढ़ी है वो थोड़ी-सी अलग है।

...व्यवधान...

माननीया जल मंत्री (श्रीमती आतिशी): पर अभी वो विजेन्द्र जी चले गए हैं उन्होंने पिछली बार मुझे कहा था कि हमें स्पीकर साहब से बात करनी है। अपने आपस में विधायकों से बात नहीं करनी है। तो इसलिए अब मुझे स्पीकर साहब को बताना पड़ेगा कि जरनैल सिंह जी की समस्याओं का क्या समाधान है। मैं आपको मिस कर रही थी विजेन्द्र जी।

...व्यवधान...

माननीया जल मंत्री (श्रीमती आतिशी): जी। तो जरनैल सिंह जी जो आपकी प्रोब्लम्स थीं। जो सीवरेज के इशुस एच ब्लॉक विकासपुरी, ओ ब्लॉक कृष्णा पार्क, जीजी वन ब्लॉक, हाउस नंबर 80 विकासपुरी, गली नंबर 5 कृष्णा पार्क, गली नंबर 3 कृष्णा पार्क, डबल स्टोरी

तिलक नगर के जो मुद्दे हैं इनमें दिल्ली जल बोर्ड ने जो मशीनें लगाके सीवर की सफाई का काम है उसको पिछले एक हफ्ते में लगातार किया है। उसकी रूटीन डिसिल्टिंग की जा रही है। जो डबल स्टोरी तिलक नगर में है वहां पर टेंडर हो गया हैपानी की सीवर की लाईन बदलने का और ऐसा कहा गया है कि 31 मई, 2024 तक ये काम पूरा हो जायेगा। जो पानी की आपकी समस्या है जेजी 3 विकासपुरी, बेस्ट ब्लॉक विष्ण गार्डन केसोपुर विपेज, 7 एण्ड 8 ब्लॉक तिलकनगर और इसमें मिक्स्ड हैं एक्चुएली आपकी पानी की और सीवर की। इन सब एरियाज में विष्णु गार्डन में tail end की augmentation के लिए टेंडर float कर दिया गया है 31 मई तक पूरा हो जायेगा। केसोपुर विलेज में सप्लाई एवेलेबल हैं 10, 15 घर छोड़के जो elevated portion में हैं। उसी तरह से 7 और 8 ब्लॉक तिलक नगर में जल बोर्ड के अनुसार अभी कोई भी पानी की शोर्टेज नहीं है लेकिन आने वाले समय में अगर गर्मियों में आवश्यकता होगी तो टेंकर्स को deploy कर दिया जायेगा। जहां तक कि आपके बचे हुए सीवर के काम हैं उसमें भी ये ही बताया गया है कि रेगुलर ब्लॉकेज और डिसल्टिंग की जा रही है। परन्तु मैं ये कहूंगी कि जो detailed problems जरनैल जी ने अभी बतायीं हैं जो अभी समाधान प्रस्तुत किये गए हैं दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा वो अभी पर्याप्त नहीं लग रहे हैं। तो जरनैल सिंह जी के इलाके की जो समस्या है उनको अभी और डिटेल में अधिकारियों के साथ टेकअप किया जायेगा।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी चर्चा का उत्तर दें सभी का उससे पहले कुछ चीजें मैं माननीय मंत्री जी के और अधिकारियों के सामने रखना चाहता हूँ। पानी गंदा आने का एक मुख्य कारण है सीवर ओवरफ्लो होने का। मैक्सिमम एरिया में सीवर जो ओवरफ्लो होते हैं वो 7 से लेकर 12 बजे तक होते हैं। समवैल दिल्ली में कितने बने थे कब बने थे, सीवरेज का ओवरफ्लो पानी बढ़ा है मकान चार मंजिल हो गए लेकिन समवैल की कैपेसिटियां नहीं बढ़ी हैं। उनका आउटफॉल के पाइप नहीं बढ़ें। मोटरें नहीं बढ़ी। हमारे समवैल भर जाते हैं तो हमारी सीवर लाइन ओवरफ्लो होती है। माननीय मंत्री जी से अधिकारियों से मैं प्रार्थना करूंगा इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें। दिल्ली में समवैल नए नहीं बने हैं। आबादी बढ़ी है। सीवर का पानी समवैल में जायेगा, समवैल उसको बाहर फैकेगा जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा हम कुछ भी कहते रहें, आलोचना करते रहें ये अधिकारियों को देखना पड़ेगा। दूसरा माननीय मंत्री जी ने जैसा अपने उत्तरों में बताया है ठेकेदारों की पेमेंट का समाधान कुछ निकला या नहीं निकला, तब तक ठेकेदार काम करना आरंभ नहीं कर रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः वो एक ही बात है। इस चीज की और माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगा कि देखें। एक मेंटेनेंस labour सभी विधान सभाओं में कम कर दी गई हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई मैं अपनी बात रख लूं दो मिनट। कम कर दी गईं और 29 फरवरी को टेंडर करने की परमिशन दी गई थी ये मैं इसलिए जानकारी में दे रहा हूँ कि 280 में इस बार जिन भी विधायकों की समस्या हैं मैक्सिमम जल बोर्ड को लेकर के आईं थी। सीईओ साहब को मैंने बुलाया था 25 तारीख तक जितनी समस्यायें हैं उनको अलग से भेजी गई थी और एक मीटिंग हुई उन समस्याओं को लेकर 280 की। 25 तारीख के बाद जो समस्याएं आई हैं वो परसों भेजी गई हैं और जो लैटर के माध्यम से आपने व्यक्तिगत मुझे दिये थे वो सीएस को और माननीय मंत्री जी को मैंने भेजे थे जिन पर आज चर्चा हो रही है दो पहलू से हम काम कर रहे हैं। उसमें जो लेबर की प्राब्लम है मैंने वहां रेज की थी अब जो लेबर 29 तारीख को टैंडर हुए हैं वो भी त्रिपाठी जी बोल रहे हैं बिलकुल हटा दी गई, कहीं दी गई हैं, कहीं नहीं दी गई लेकिन उसमें बहुत माननीय मंत्री जी का ध्यान लाना चाह रहा हूं जो लेबर मेनटेनेंस में थी वो 45, 50, 55 साल की हो चुकी है परमानेंट है, दे आर नॉट एबल वो फावड़ा उठाएं या गैती उठाएं वो काम नहीं कर सकते हैं उसका समाधान निकालना है उनको जलबोर्ड के कहीं और उनको ट्रांसफर करें और वहां यंग लेबर दी जाए जो मेनटेनेंस के काम को ठीक से कर सके, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। समवैल की मैंने बात की distribution of water tanks की समस्या आप लोगों ने उठाई है ये भी बहुत महत्वपूर्ण पाइंट है इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा।

सुश्री भावना गौडः अध्यक्ष जी उसके लिए कम से कम टैंकर तो.

माननीय अध्यक्षः हां वो सारे जो टैंकर जहां-जहां जितने विधायकों को चाहिए। एक और समस्या बहुत गंभीर है जिसकी ओर इशारा किया गया। हमारे यहां से जेई, एई, एक्सईएन ट्रांसफर कर दिये गये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः एक सेकंड। ये हर विधायक इससे परेशान है नये जो आए हैं उनको इलाके की बिलकुल जानकारी नहीं। इसमें एक पॉलिसी बननी चाहिए विधायकों की सहमति से, ट्रांसफर पॉलिसी अपनी जगह है लेकिन दिल्ली की जनता की समस्या अपनी जगह है। एक ट्रांसफर पॉलिसी बने ताकि अधिकारियों को इलाके की जानकारी रहे। नये आए हैं उनके साथ विधायकों को जा-जाकर गलियां बतानी पड़ती हैं ये बहुत बड़ी समस्या है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई साहनी जी, मैं रख रहा हूं, मैं आप ही की समस्या रख रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई साहनी जी, मैं इस बात को रख रहा हूं, दो मिनट बैठिये। ये ट्रांसफर जो किये गये अभी ठीक गर्मियां आने से पहले किये गये, ठीक चुनाव से पहले किये गये इससे कहीं न कहीं

एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, इसको गंभीरता से देखा जाए। अंत में सीईओ से जब बातचीत हुई जिसको विजेन्द्र गुप्ता जी ने भी जिक्र किया कि अपना जलबोर्ड जो फंड जनरेट करता है सीईओ ने बोला कि यूडी से डायरेक्शन आई है। अब यूडी बोर्ड को डायरेक्शन दे सकता है या नहीं दे सकता that is a matter of decision. जो डायरेक्शन आई है कि मेन्टेनेंस में जलबोर्ड अपने द्वारा रेज किये गये फंड को ही खर्च करेगा capital को नहीं खर्च करेगा। मदनजी भी उस दिन सामने थे ये बड़ी अजीब सी बात है। एक चीज और पहले अगर पॉसीबल है हम लोगों को विधायकों को अधिकार था कि हम कुछ काम अपने एमएलए फंड से करवा लेते थे वो अब विड्रा हो गया, वो अगर संभव हो तो दोबारा चालू किया जा सके तो इस पर भी एक विशेष ध्यान दिया..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: नहीं अब नहीं चर्चा हो चुकी अब इतना समय नहीं न प्लीज। 8 लोगों में से 2 लोगों को बुलवाया सत्ता पक्ष से 8 बोले बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: ऋषि जी अब मैंने बातें रख दी हैं सारी। बाकी मुझे लिखकर दीजिए आप। मैं बार-बार विधायकों से प्रार्थना कर रहा हूं किसी का भी है लिखकर दीजिए जो भी है।

माननीय जल मंत्री (श्रीमती आतिशी): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज मुझे लगता है कि ये बहुत ही रेयर होता है कि पक्ष और विपक्ष

सभी किसी बात पर सहमत हों लेकिन आज मुझे खुशी है इस बात की कि जो सारी चर्चा हुई, जो सारे मुद्दे उठे और जो कई समाधान की बात हुई हैं मुझे लगता है कि आज ऐसा वो रेयर ओकेजन है कि पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक इन मुद्दों पर सहमत हैं और सब मिलकर इनका समाधान चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कई सारी समस्याएं आई हैं और जैसे विधायकगण भी हमारे साथी विधायक बता रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में काफी स्पीड से इन सब कामों पर काम हुआ है। विजेन्द्र गुप्ता जी ने एक बात कही मैंने नोट भी करी थी कि ये सवाल उठता है कि अगर एक हफ्ते में काम हुआ तो पहले क्यो नहीं हो रहा था। ये दुर्गेश पाठक जी ने भी बात कही कि जो ये मुद्दे उठा रहे हैं जो इन्होंने जो असेंबली में रखे हैं और जो पिछले 4-5 दिन में रिजाल्व हुए अगर 4-5 दिन में रिजाल्व हुए तो उससे पहले भी रिजाल्व हो सकते थे। तो मुझे ये लगता है कि ये बिलकुल जांच का विषय है और इस पर मैं जरूर आज जांच के आदेश भी दूंगी कि ऐसा क्या बदला कि 4-5 महीने से रुके हुए काम अगर 4-5 दिन में हो सकते हैं तो इसकी जिम्मेदारी तो 100 परसेंट तय होनी चाहिए। जिम्मेदारी की जो बात है कि..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: भई विजेन्द्र जी अब बोलने दो।

माननीय जल मंत्री (श्रीमती आतिशी): नहीं मैं कह रही हूं कि अगर कुछ हो गया 4-5 दिन में तो ये तो बिलकुल जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, जब आप बोलते हो सत्ता पक्ष के लोग टोकते हैं तो बड़ी परेशानी होती है, तो उनको बोलने दीजिए,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं अब हो गया आपका, आप बीच में। पहले तो मुझसे बात करके बोलिए, बैठिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी मैं, नहीं बैठ जाइये अब। माननीय मंत्री जी खड़ी हैं बोल रहे हैं। बैठिए आप।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः हां कोई बात नहीं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई विजेन्द्र जी आप बैठिये प्लीज।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी मुझसे बात करिये बैठ जाएं मैं समय नहीं दे रहा हूं। विजेन्द्र जी जो बोल रहे हैं रिकार्ड से निकाल दीजिए जो भी आप बोल रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः हां बिल्कुल, बैठिए आप।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी जब आपको विधायक डिस्टर्ब करें। अगर आपको विधायक डिस्टर्ब करेंगे तो बोलना नहीं मुझे।

माननीय जल मंत्री (श्रीमती आतिशी): अगर विजेन्द्र जी की बात को रिकार्ड से हटा दिया गया है तो उसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो गया है पर हम अलग से उस पर बैठ जाएंगे। दूसरी बात यह भी एक महत्वपूर्ण बात उठी है जलबोर्ड के ओवरआल ढ़ांचे के बारे में। उसके यूडी डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट के कोआर्डिनेंस के बारे में।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई विजेन्द्र जी, आप बार-बार डिस्टर्ब करेंगे तो मैं मजबूर हो जाउंगा स्टैप लेने के लिए। मंत्री जी को बोलने दें। आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया 10 मिनट आप बोले हैं किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, आप चार बार डिस्टर्ब कर चुके हैं मंत्री जी को। बाहर जाकर बयान देते हैं हमें समय नहीं मिलता, बाहर कर दिया जाता है।

माननीय जल मंत्री (श्रीमती आतिशी): आप बोलने तो दीजिए मुझे गुप्ता जी। अगर आप बोलने नहीं देंगे तो आपकी बात का जवाब

कैसे होगा। दूसरी बात मैं भी इस बात से सहमत हूं कि अभी जो बातें सामने आई हैं इससे ये बिलकुल साफ है कि एक ओवरआल ढ़ांचे में जिस तरह से दिल्ली जलबोर्ड का काम है, जिस तरह यूडी डिपार्टमेंट का उसमें रोल है उनका दिल्ली सरकार से दिल्ली सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो कोआर्डिनेशन है इसमें कोई न कोई तो भारी समस्या है वर्ना पिछले 6 महीने से 8 महीने से एक साल से जो विकट समस्या दिल्ली जलबोर्ड में पैदा हो गई है ऐसी समस्या मुझे लगता है कि दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं पैदा हुई होगी। यहां पर हमारे साथी भी विधायक हैं कई दो बारी विधायक रह चुके हैं, कई तीन बार विधायक रह चुके हैं लेकिन जो पिछले एक साल में दिल्ली जलबोर्ड के छोटे-छोटे कामों के लिए कि कभी सीवर की मशीन नहीं है, कभी 100 मीटर पानी की लाइन रिपलेस होनी है वो रिपलेस नहीं हो रही है। बीच सड़क पर पानी की पाइप लाइन बह रही है, सड़क टूट रही है वो ठीक नहीं हो रही है। पानी के टैंकर की आवश्यकता है पानी के टैंकर नहीं पहुंच रहे हैं। देखिये दिल्ली जैसे शहर में हमेशा पानी और सीवर की समस्या का समाधान करना मुश्किल रहा है, इसलिए मुश्किल रहा है अध्यक्ष महोदय क्योंकि दिल्ली की जितनी आबादी है और जितनी स्पीड से बढ़ती हुई आबादी है और अक्सर जो दिल्ली में माइग्रेंट्स आ रहे हैं, जो प्रवासी लोग आ रहे हैं अनॉथराइज कालोनीज और झुग्गी क्लस्टर्स में रह रहे हैं, तो जो दिल्ली का अपना इनफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है वो दिल्ली में आने वाले जो माइग्रेशन है उसे मैच नहीं कर पाता लेकिन जितनी समस्या पिछले एक साल में हुई है, मैं तो यह भी

कह सकती हूं कोविड के लॉकडाउन के दौरान इतनी समस्या नहीं हुई। तब भी समस्याओं का समाधान हो जाता था, उस इमरजेंसी में भी जितनी समस्या पिछले एक साल मे हुई। तो यह बिलकुल जो जलबोर्ड का, दिल्ली सरकार का, यूडी डिपार्टमेंट का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो संबंध है मुझे लगता है कि पिछले एक साल उसकी सारी फाल्टलाइन सामने लेकर आया है और आखिरकार इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है। आखिरकार इसका खामियाजा हमें एज इंडिविडुअल्स नहीं दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ता है कि अगर ये समस्याएं सुलझती नहीं हैं तो जिन लोगों के घर में पानी का टैंकर नहीं पहुंच रहा, जिसके घर के सामने पानी की लाइन लीक कर रही है, जिसके घर के सामने पानी का जो सीवर है वो ओवरफ्लो कर रहा है इसका खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है और जो सारे लोग हम इस हाउस में बैठे हैं, हम जनप्रतिनिधि होने के नाते जो सारे अफसर यहां मौजूद हैं जो अफसर दिल्ली सरकार में भी और काम करते हैं हम सब अपनी तनख्वाह दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से पाते हैं।तो इसलिए हमारी दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेही है और जो पिछले एक साल में दिल्ली की जनता के साथ अतिवाद हुआ है, जो उनके साथ अत्याचार हुआ है दिल्ली जलबोर्ड की समस्याएं न सुलझने की वजह से इस पर एक जांच की आवश्यकता है। उस जांच के बाद वाइट पेपर भी निकले, उस जांच के बाद जिन अधिकारियों की वजह से, जिसकी भी वजह से चाहे बोर्ड की वजह से, बोर्ड के सदस्यों की वजह से, अधिकारियों की वजह से जिसकी भी गलती है उस पर सख्त

से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि आखिरकार हम सबकी जवाबदेही है। चाहे एज पब्लिक रिप्रजेंटेटिव्स चाहे एज आफिसर्स दिल्ली की जनता के प्रति है और दिल्ली की जनता जितनी परेशान हुई है उसका जवाब किसी न किसी को तो देना पड़ेगा। दूसरी बात, जो बाकी अभी स्पेसिफिक मुद्दे उठे सीवर से जुड़े हुए, पानी से जुड़े हुए, टैंकर से जुड़े हुए, लेबर से जुड़े हुए उनकी दो-तीन चीजों की वैसे तो मैंने तकरीबन जब सब लोगों के सवाल उठे तो मैंने सबके जवाब दे भी दिये थे लेकिन मोटा-मोटी मैं एक रिकैप कर देती हूं कि आज हमारी क्या-क्या चर्चा हुई। सबसे पहले जो दिल्ली में पानी की सार्टेज है जैसा मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश से भी हमारी बात चल रही है और अपर यमुना रिवर बार्ड और रिवर कमेटी में भी हमारी कोशिश चल रही है कि जो हमें 51 क्यूसेक्स पानी मिलता है इरिगेशन के लिए वो हमें ड्रिंकिंग वाटर परपजेज के लिए मिले और दूसरा हिमाचल के साथ हमारा एमओयू हो गया है, हिमाचल हमें पानी देने के लिए तैयार है और इसमें मैं हमारे विपक्ष के साथियों से भी अनुरोध करूंगी कि अगर वो थोड़ी मदद करें क्योंकि अभी हरियाणा ने इसमें रोड़ा अटकाया हुआ है। वो यह कह रहे हैं कि अगर हिमाचल पानी देता है तो उसका पहला हक हरियाणा का बनता है, दिल्ली का नहीं बनता। तो अगर हमारे विपक्ष के साथी इसमें मदद करें क्योंकि इनकी पार्टी की सरकार है हरियाणा में। तो अगर अपर यमुना रिवर बोर्ड में हरियाणा भी हमारा समर्थन करे तो हमें हिमाचल प्रदेश का पानी अगर अपर यमुना रिवर बोर्ड का निर्णय आ जाता है तो हमें अगले ही दिन 100 एमजीडी पानी मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा एक दिन के अंदर-अंदर हमें मिल जाएगा। तो

इसलिए मैं आपसे भी इस सहयोग की उम्मीद करती हूं। दूसरी बात ground water augmentation की मैंने बात करी कि दिल्ली में बहुत सारे इलाके हैं खासकर जो नार्थ दिल्ली में और जो यमुना नदी के आसपास के इलाके हैं वहां पर पानी का स्तर भी अच्छा है, वहां पर पानी की क्वालिटी भी ठीक है तो वहां पर खासकर पानी की सप्लाई को augment करने के लिए एक ground water augmentation का हम पूरा प्लान बना रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद उसकी पर्सनली जिम्मेदारी भी ली है। सीवर की समस्या को लेकर दो मुद्दे हैं मुझे लगता है जो इंपोर्टेंट हैं, एक है कि जो हमारे ट्रंक सीवर्स हैं और जो पेरिफेरल सीवर्स हैं उनकी प्रॉपर डी-सिल्टिंग। उस डी-सिल्टिंग की प्रक्रिया को शुरु कर दिया गया है। उस डी-सिल्टिंग की प्रक्रिया की क्या टाइम लाइंस होंगी वो भी मैं हाउस के सामने पेश कर दूंगी स्पीकर साहब के माध्यम से। दूसरा जो एमसीडी के साथ कोआर्डिनेशन की जरूरत है कि storm water drains जहां पर नहीं हैं वहां पर ड्रेन्स बनाई जाएं और जहां पर ड्रेन्स का पानी सीवर में आ रहा है उसको रोका जाए कि हमारे सीवर्स ओवरफ्लो न हों लेकिन जब तक ये पूरा काम नहीं हो जाता तब तक मशीन्स की पूरी उपलब्धता दिल्ली जलबोर्ड के द्वारा करवाई जाए ताकि कोई भी समस्या दिल्ली के लोगों को न हो और दूसरा पर्याप्त contractual labour की भी आवश्यकता करवाई जाए क्योंकि जैसा अध्यक्ष महोदय ने बताया बहुत सारा जो परमानेंट स्टाफ है दिल्ली जलबोर्ड का उनकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि जो सीवर क्लीनिंग वगैरह के काम हैं अगर हाथ से, डंडे से, मेनुअली जेटिंग

मशीन चलाकर करने हैं तो उसके लिए उनकी उम्र उन्हें अलाउ नहीं करती है। टैंकर्स की समस्या, इसको हम पर्सनली टेकअप करेंगे विदइन वन वीक मगर मैं आपके माध्यम से सभी एमएलऐज को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि उनके कौन-कौन से एरिया में कितने वाटर टैंकर्स की रिक्वायरमेट है वो एरिया बता दें, वहां पर कितनी आबादी है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप सिर्फ एक नंबर मत लिखकर दीजिएगा क्योंकि नंबर से उसका कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता है। तो अगर आप कौन से एरिया में किस वजह से कितनी आबादी के लिए कितने टैंकर की रिक्वायरमेंट है अगर सारे हमारे जो सदस्य हैं स्पीकर साहब के माध्यम से हमें प्रोवाइड कर देंगे तो हमें भी टैंकर्स का प्लान बनाने में आसानी होगी। बाकी अध्यक्ष महोदय, अभी भी काफी सारे मुद्दों के रिजोल्यूशन की आवश्यकता है, तो मैं दिल्ली जलबोर्ड की तरफ से दिल्ली सरकार की तरफ से यह कमिट करती हूं कि हम रेग्यूलर बेसिस पर जिस प्रकार हमने अपडेट्स दिये हैं ये वाली रिपोर्ट भी आपको सौंप दी जाएगी। जिस प्रकार हमने अपडेट्स दिये हैं वो अपडेट्स हम असेंबली को देते रहेंगे। कल रात को करीब साढ़े 3 बजे मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब से काफी डिटेल्ड रिपोर्ट भी आई है लॉगटर्म सोल्यूशंस को लेकर। मैं खुद अभी उसे पढ़ नहीं पाई हूं तो मैं उसको पढ़कर हाउस के सामने भी शेयर कर दूंगी और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि शॉर्टटर्म सोल्यूशंस के साथ-साथ जिन एरियाज में ज्यादा प्राब्लम्स हैं वहां पर टाइम बाउंड तरीके से लॉगटर्म सोल्यूशंस की शुरुआत की जाए, थैंक यू।

माननीय अध्यक्षः अब श्री दिलीप कुमार पाण्डेय जी माननीय मुख्य सचेतक द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं न कहें

(पक्ष के सभी सदस्यों द्वारा हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

संकल्प पारित हुआ।

अल्पकालिक चर्चा नियम-55, श्री मदन लाल जी।

अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)

श्री मदन लालः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे यहां सदन में इस मामले पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, अभी हम सीवर और पानी की चर्चा कर रहे थे। सीवर और पानी की वजह से एक और बड़ा खतरा लोगों के हेल्थ को हो गया है। सीवर की वजह से बीमारियां फैल रही हैं और उन बीमारियों से ग्रस्त कोई छोटा बच्चा अगर मोहल्ला क्लीनिक तक चला जाए तो वहां डॉक्टर्स के पास दस्त की कोई दवाई छोटे बच्चे को देने के लिए नहीं है जो लगभग पिछले एक साल से ये स्थिति बनी हुई है। आज हालत यह हो गई है कि बहुत सारे ऐसे मरीज जो छोटी-छोटी बीमारियों की वजह से चाहे वो सीवर रिलेटेड हों, दस्त, उल्टी, वाटर कंटेमिनेशन की वजह से एक आम रोग है। जब भी कभी कोई जाता है मोहल्ला क्लीनिक तक या

अस्पताल तक तो अस्पताल में उस बच्चे को दवाई देने के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि कुछ आफिसर्स जानबूझकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं दिल्ली में कि दिल्ली के सरकार अस्पताल चाहे वो बड़े अस्पताल हों, चाहे वो मोहल्ला क्लीनिक हों उनमें दवाइयों की सप्लाई और खासकर जो इसेंशियल्स दवाई हैं। प्रेगनेंट वूमन, अगर कोई प्रेगनेंट महिला अगर हास्पिटल चली जाए और खांसी-जुकाम की बात करे तो डॉक्टर्स के पास उसको देने के लिए जुकाम की कोई सेफ दवाई नहीं है ये भयावह स्थिति है। अगर कोई हल्के दर्द के लिए पेन किलर लेने जाए डॉक्टर के पास तो ब्रूफेन नहीं है। ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो आदमी रोजमर्रा की जरूरतें समझकर अस्पताल जाता है और ये दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में central procurement agency है उसका काम है दवाइयों को प्रिक्योर करना। एक टैंडर डाला गया था 29/12/2022 को, किन्हीं आफिसर्स की मदद से एक साल तक उस टैंडर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और अंत में वो टैंडर खत्म हो गया। उसके बाद एक नया टैंडर कोट किया क्योंकि खानापूर्ति करनी जरूरी है आफिसर्स के लिए कल को कोई उंगली न उठाए और वो टैंडर भी मार्च में इसी महीने में खत्म हो जाएगा अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एक भयावह स्थिति उत्पन्न होगी। दिल्ली में अगर मेडिसिंस ही नहीं होंगी, एक साल पहले का टैंडर, एक साल तक कोई कार्रवाई न होने के कारण खत्म हो गया। एक नया टैंडर इस महीने के अंत तक खत्म हो जाएगा तो फिर दवाई कहां से आएगी। लोग जो रोज अस्पताल में जाते हैं उनका क्या होगा और एक हमारी दिल्ली की

सरकार जिसका लगभग 14 परसेंट बजट केवल हेल्थ सेक्टर को जाता है इतने बड़े बजट को देने वाली सरकार।

(माननीया उपाध्यक्ष श्रीमती राखी बिरला 1.19 बजे अध्यक्ष के आसन पर पीठासीन हुई)

माननीया अध्यक्षः कंटीन्यू रखिये।

श्री मदन लालः थैंक यू अध्यक्षा जी, लगभग 14 परसेंट के बजट को देने वाली सरकार आज अपने अस्पतालों को जरूरी दवाइयां मुहैया नहीं करा पा रही हैं और उसका केवल एक कारण है कि कुछ एक आफिसर्स हैं जो पिछले लगभग एक साल से किसी के इशारे पर, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो इसके बारे में भी जांच करवाएं और जो दोषी अधिकारी हों उन्हें दंडित करवाएं। ये लोगों की सेहत के साथ खेलना है, ये लोगों को जीते जी मारना है। बच्चे को दस्त मे भी अगर दवाई नहीं मिलेगी तो आप समझो उसकी क्या हालत होगी। इतने बड़े बजट देने के बाद भी अगर दवाइयां उपलब्ध नहीं होंगी तो हम कैसे इस दिल्ली को दुनियां का और इस देश का सर्वश्रेष्ठ नगर घोषित करेंगे। अध्यक्षा जी, इसके लिए कौन आफिसर रिस्पांसिबल है उनकी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे और लोगों को इससे सबक मिले। पीछे माननीय मंत्री जी के indulgence से लोकल परच्येज अलाउ कर दी गई थी कि लोकल परच्येज करके आप टैंडर के द्वारा लोकल परच्येज करा लीजिए पर उसके साथ एक राइडर लगा दिया गया। वो राइडर था कि आप परच्येज तब करेंगे जब

ओरिजनल इनवाइस जिस कंपनी ने वो मेन्यूफेक्चर की है वो उसके साथ लगा होगा। ये कैसा राइडर है, ये कैसी शर्त है जहां से आप दवाई खरीद रहे हैं वो खरीददार सीधा कंपनी से नहीं खरीद पा रहा है क्योंकि जो कंपनी मेन्यूफेक्चर कर रही है वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कैमिस्ट तक आता है और अगर आप कहेंगे कि ओरिजनल इनवाइस चाहिए तो आपने एक रास्ता बंद कर दिया कि आप उसको खरीदने नहीं दे रहे हैं। अध्यक्षा जी, जैम एक सरकारी संस्था है वहां से कोई भी सरकारी चीज सरकार के माध्यम से खरीदी जा सकती है। दिल्ली के अस्पतालों में 400 से 600 तक मेडीशियंस की लिस्ट है पर जैम पर केवल 11 दवाइयां उपलब्ध है ऐसे में जैम भी एक कारगर उपाय नहीं है। अगर आप देखें तो इसी के साथ ऊपर वाली बड़ी सरकार ने जितने भी टैस्ट हैं सब बंद करा दिये हैं। दो प्राइवेट एजेंसी थीं जो दिल्ली में लोगों के टैस्ट करती थीं। टैस्ट करने के माध्यम की वजह से लोगों को बड़ा रिलीफ था। लोगों को अर्ली स्टेज पर पता चल जाता था कि वो कौन सी बीमारी से ग्रस्त हैं। मोहल्ला क्लिनिक इसमें बहुत बड़ा एक सहयोगी संस्था थी अब वो उनके बंद होने के बाद और बंद भी क्यों हो गये पिछले एक साल से करोड़ों रुपये की पेमेंट इन दोनों एजेंसीज को ये आफिसर किसी न किसी बहाने से नहीं होने दे रहे हैं। यही कारण है कि आज लोग मोहल्ला क्लिनिक हों चाहे बड़ी अस्पताल हों वहां जाते हैं और यह कहकर लौटा दिये जाते हैं कि टैस्ट अभी बंद हैं। अध्यक्षा जी, it is sorry state of affair सरकार फंड देने को तैयार है, सरकार ने फंड एलोकेट किये हैं। बहुत बड़ा बजट जैसा मैंने कहा लगभग 14

परसेंट बजट हेल्थ सेक्टर को देने के बावजूद भी हम बहुत सारी चीजों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हास्पिटल्स में अगर दवाई नहीं होंगी, मोहल्ला क्लिनिक्स में अगर दवाई नहीं होंगी तो फिर लोग मोहल्ला क्लिनिक क्यों जाएंगे और वहां मिल क्या रहा है। बहुत सारी जरूरत की चीजें जो जरूरतों की दवाइयां हैं उनकी उपलब्धता नहीं है। किसी प्रेगनेंट महिला को अगर जुकाम की दवाई कोई सेफ नहीं मिलेगी तो आने वाली संतति का क्या होगा। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि वो इस ओर ध्यान दे और ऐसे दोषी अफसरों को जैसा अभी माननीय जल मंत्री जी ने कहा कि वो जरूर इसके बारे में संज्ञान लेंगी, दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

ऐसे ही वो लोग जो हैल्थ सैक्टर को बदनाम कर रहे हैं, जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं और दवाइयों की प्रिक्योरमेंट नहीं कर रहे हैं या उसको जानबूझ कर डिले कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ पहले उनको आईडेंटिफाई करना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे अफसरों को आईडेंटिफाई करें और उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मुद्दे पर बोलने का मौका दिया पर सीवर से रिलेटिड ये समस्या भी एक बड़ी है कि सीवर की वजह सेजो बीमार हो रहे हैं उनके लिये भी दवाई मोहल्ला क्लिनिक में नहीं मिल रही है। धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः बहुत बहुत धन्यवाद मदन लाल जी। ऋतुराज झा जी।

श्री ऋतुराज गोविंदः धन्यवाद अध्यक्षा जी, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।

माननीया अध्यक्षः समय सीमा का ध्यान रखियेगा।

श्री ऋतुराज गोविंदः ठीक है जी। अध्यक्षा जी, दिल्ली की जनता केजरीवाल जी से बहुत प्यार करती है और खासकर के गरीब लोग जिसकी हम चर्चा करते हैं कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति जो अनऑथोराईज कालोनी में रहते हैं, जे.जे. क्लस्टर्स में रहते हैं, जो एलआईजी फ्लैट्स में रहते हैं, दिल्ली के जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं, वो अपने बेटे की तरह एकदम केजरीवाल जी को मानते हैं क्योंकि उनकी सभी बुनियादी जरूरतों का ख्याल एक परिवार की तरह रखते हैं। बिजली फ्री देते हैं, पीने का पानी देते हैं, बच्चों की पढ़ाई कराते हैं, उनके लिये दवाई का इंतजाम कराते हैं मोहल्ला क्लिनिक्स के जरिये, हॉस्पिटल्स के जरिये, महिलाओं को फ्री बस सर्विस देते हैं, पूरी सुरक्षा के साथ, सम्मान के साथ और अब तो एक हजार रूपया महीना भी आ गया है। अब इसकी क्रोनालॉजी को समझना बहुत जरूरी है। पूरे देश में एक ही पालिटिकल पार्टी है जो भाजपा को चार चार बार हराती है। मोदी जी को नगर निगम में भी नहीं छोड़ा जहां दिल्ली में रहते हैं। इससे इतना बौखलाये हुए हैं, इतना तिलमिलाये हुए हैं कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, केजरीवाल जी की जो सरकार है दिल्ली के अंदर, और जो जो सुविधा वो दे रहे हैं, जिससे कि गरीब जनता उनको मसीहा मानती है, बेटा मानती है, उस पर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी बिजली का सब्सिडी रोकने की कोशिश करते हैं ताकि

लोगों को फ्री बिजली न मिले, पानी पर क्या सब हो रहा है अभी पूरी सदन ने पूरा दो घंटा चर्चा किया है, कैसे पानी रोक दिया जाये, कैसे मेनटेनेंस न हो, कैसे लोगों को गंदा पानी पहुंचे, कैसे टैंकर न मिले, दो घंटा इसपे चर्चा हुआ है और निगम के जब चुनाव थे 2022 में तो मोहल्ला क्लिनिक्स में लोगों को दवाई न मिले, हॉस्पिटल्स के अंदर में कंप्यूटर ऑपरेटर को हटा दिया ताकि ओपीडी की पर्ची न बने, और जांच न हो। इसके लिये गंदा खेल खेला गया था और पूरे के पूरे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गयी। बसों के मार्शल हटा दिये ताकि महिलायें जो हैं उनके अंदर जो सेंस आफ सिक्योरिटी थी वो न हो, उनके साथ क्या सब हो रहा है। तो हर एक उस चीज को चोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, गंदी राजनीति के तहत जिससे कि गरीब आदमी का भला न हो। अब दवाई किसको चाहिये सरकारी अस्पताल में, मोहल्ला क्लिनिक्स में। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार की वो योजना है अध्यक्ष महोदय कि गरीब से गरीब क्षेत्र में, कच्ची कालोनियों में, जे.जे. क्लस्टर में, मेरे खुद के क्षेत्र में 12 मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, 12 मोहल्ला क्लिनिक्स, कई बार मैं विजिट पे जाता हूं तो रोज डेढ सौ से दो सौ लोग वहां इलाज कराते हैं, रोज। आप सोचिये साढे पांच हजार से ज्यादा परिवार तो ऐसे हैं जोकि हर महीना बीपी और शुगर की दवाई वहां से लेते हैं कम से कम दो से ढाई हजार तीन हजार रूपया का फायदा मिलता है। वो वो लोग हैं जो बेचारे मजदूरी करते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जाकर के मोहल्ला क्लिनिक में दवाई लेते हैं।

माननीया अध्यक्षः कम्पलीट कीजिए।

श्री ऋतुराज गोविंदः और देखिये 2022 में चुनाव था तो दवाई रोक दिया, 2024 में चुनाव है अभी लोकसभा का चुनाव है फिर विधान सभा का चुनाव है, ये चुनाव आते ही ये पढ़ाई रोकेंगे, दवाई रोकेंगे, पानी रोकेंगे, बिजली रोकेंगे, अब तो ये क्रोनोलॉजी दिल्ली की जनता को एक एक आदमी को समझ में आ गया है कि हो क्या रहा है। पहले अफसरों पे कब्जा किया सर्विसिज लेकर के, एक तरफ ब्लेम करते हैं अभी गुप्ता जी खड़ा होके हल्ला कर रहे थे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इनको भी सब बात समझ में आता है लेकिन किसी भी तरीके से चाहते हैं कि गरीब लोगों का इलाज न हो, उनको दवाई न मिले, केजरीवाल जी जो सुविधायें दे रहे हैं पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का, जो सही मायने में जो अंत्योदय कर रहे हैं, जो रामराज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का भला करके, वो न हो सके, उसको किस तरीके से फेल किया जा सके, ये वो भाजपाई हैं मैं आपको बता दूं अगर आपके क्षेत्र में अगर कोई अच्छी सड़क होगी जिसको लोग तारीफ कर रहे होंगे विधायक जी ने बहुत अच्छी सड़क बनाई है तो वहां क्या करेंगे सीवर में बोरा के अंदर में रेत भर करके सीवर में घुसा देंगे ताकि सीवर का पानी उपर आये तो लोग विधायक को गाली दें। ये लोग नाले जाम कर देते हैं ताकि लोग गाली दें और फिर बोलेंगे वहां जाके हल्ला करेंगे देखो नर्क हो गया, नर्क हो गया, नर्क हो गया, फोटो खिंचायेंगे, वीडियो

बनायेंगे। ये इनकी राजनीति है। ये बदनाम करने के लिये, अपनी घटिया राजनीति को सिद्ध करने के लिये किसी भी हद तक जा सकते हैं।

माननीया अध्यक्षः ऋतुराज जी।

श्री ऋतुराज गोविंदः आप ये समझ लो कि पानी देना, दवाई देना पुण्य का काम है और जिन गरीब लोगों को क्योंकि ये पूंजीपतियों के गोद में खेलने वाले लोग हैं, अब तो इलेक्टोरल बाँड से भी साबित हो गया कि वैक्सीन बनाने वाले कंपनी से कैसे पैसा लिया गया, कैसे गेमिंग कंपनी से जो है एक बार ईडी का रेड किये, दूसरे दिन पैसा लेकर के उसको छोड़ दिये। तो मतलब लीगल तरीके से एक्टॉर्शन कैसे करना है, कोई इनसे सीखे। तो इनका चेहरा तो बेनकाब हो रहा है लेकिन दिल्ली की जनता को परेशान किस तरीके से किया जा रहा है दवाई रोक करके, टेंडर में मतलब ये कहते हैं एक कमरे में बंद कर दिये हैं बोले दरवाजा बंद कर दिया अब तुम निकल के दिखाओ। हैं कि नहीं, कैसे निकलोगे। तो उल्टे सीधे, उल्टे सीधे क्लॉज डाल डाल के, डाल डाल के ऑर्डर करते हैं। अस्पताल को बोलते हैं आप इस तरीके से दवाई नहीं खरीद सकते, उस तरीके से, अरे सरकार के अंदर किसी समस्या का समाधान न हो, ऐसा हो सकता है। ये बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स बैठे हैं, ढाई ढाई तीन तीन लाख रूपया तनख्वाह लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, बंगला लेते हैं, सारी सुविधायें लेते हैं इनको सरकार ने, इनको देश ने इतना leverage इसलिये किया है ताकि लोगों का काम रोकेंगे? इनकी जिम्मेदारी है वो रास्ता निकालें जिससे कि लोगों का काम हो। किस तरीके से गरीब तक दवाई पहुंचे, सारी जांच हो,

सारा इलाज हो, मोहल्ला क्लिनिक की इतनी चर्चा हुई, कोफी अन्नान जो फार्मर यूएन जनरल सेक्रेटरी हैं, जो दिल्ली के अंदर देखने के लिए आये थे। पूरी देश में चर्चा हुई है, दुनिया में हुई है।

माननीया अध्यक्षः चलिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री ऋतुराज गोविंदः अमेरिका के अखबारों में छपा है। उस मोहल्ला क्लिनिक को कैसे फेल किया जाये उस चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये जितने भी लोग हैं कम से कम मैं आपको बता दूं एक एक क्षेत्र, एक एक विधान सभा क्षेत्र में हर महीने 50 से 60 हजार लोग ऐसे हैं जिनको मोहल्ला क्लिनिक से बेनिफिट मिलता है, वो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, वो दवाईयां अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जांच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आपने मुझे इस विषय पे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं धन्यवाद करता हूं और इसकी जांच होनी चाहिये और किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर इन गरीब प्रवासियों का दवाई और इलाज नहीं रूकना चाहिये धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः अखिलेश पति त्रिपाठी जी। समय सीमा का सब ध्यान रखें, बोलना सब चाहते हैं लेकिन समय का ध्यान कोई नहीं रखता है।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः सभापति महोदया, पीछे अभी ऋतुराज भाई ने बताया कि जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली का काम रोकना याद आ जाता है। आज अच्छा रहा कि जलबोर्ड पर चर्चा हो रही थी तो सरकार को कटघरे में खड़ा करने के

लिये विजेंद्र जी कुछ बातें कह रहे थे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि दिल्ली की जनता को रिप्रजेंट करते हैं आप लोग, कम से कम एक बार तो कह देते कि जो दोषी अफसर हैं उन पर कोई कार्रवाई होना चाहिये। अच्छा लगता। सदन की गरिमा बढ़ती, मर्यादा बढ़ती इससे। पीछे अभय जी खड़े हुए, वो भी कह रहे थे सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, अच्छा होता कि वो कहते कि एलजी साहब जो अफसरों पर दबाव बनाकर के फाईनेंस डिपार्टमेंट से पैसा रूकवाने का काम कर रहे हैं, जो फाईनेंस सेक्रेटरी फाईनेंस डिपार्टमेंट के लोग पैसा रोक रहे हैं उन पर कार्रवाई की बातें करते, कुछ जिम्मेदारी फिक्स करने की बात करते, अच्छा लगता। अच्छा लगता, जनता की बात होती। लेकिन मुझे लगता है कि पूरा विपक्ष राजनीति करने आया था, समस्या पर समाधान की बात करने नहीं आये थे। और ये पूरी दिल्ली के लोग जान रहे हैं। पूरी दिल्ली के लोग जान गये हैं कि किस तरीके से आदरणाीय अरविंद केजरीवाल जी के कामों को रोकने के लिये पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का अमला, ..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः तरीका नहीं है, बिल्कुल ये तरीका नहीं है।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः पूरा जोर शोर से लगा हुआ है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल हैं, ये रूकेंगे नहीं, ये झुकेंगे नहीं। काम तो करा के छोड़ेंगे। इशारा तो जायेगा कभी कभी साथी हैं, चलता रहता है वो चोर की दाढ़ी में तिनका, अब सदन में बोल रहे हैं तो अब

गड़बड़ कर रखा है आप लोगों ने तो थोड़ी खुजली हो रही है। समझ में आ रहा है गलती कहां पे है उसको सुधारने का काम करिये, उसको सुधारने का काम करिये। कितना हाय लगेगा उन गरीब लोगों का दवाई रोक दिया गया मोहल्ला क्लिनिक में। क्या दवाई नहीं मिलनी चाहिये लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोग सहमत नहीं हैं क्या उस पर?.. उस पर नहीं मिलना चाहिये क्या, इस पर बोलते हैं कि जिस अधिकारी की लापरवाही की वजह से ये दवाईयां मिल नहीं पा रही थी, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हुआ इसके लिये चलिये एलजी साहब के पास चलते हैं, उनको सस्पेंड कराने का काम करते हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने लिखा कि जिन जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिये। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखा कि ये हैल्थ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है कि दवाईयां नहीं मिलती हैं, सही से कार्यान्वयन सरकार की नीतियों का नहीं होता है तो अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिये। लेकिन आज सवाल पूछने के लिये खड़ा हुआ हूं कि उन अधिकारियों को सस्पेंड कौन करेगा जो लापरवाही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बतायें अभी कुछ साथी कह रहे थे मुझे बोलने का मौका देना, देंगे, लेकिन आप बताना जरूर भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जो अधिकारी एलजी के इशारे पर काम नहीं कर रहे, सरकार के कामों को रोकने का काम कर रहे हैं क्या उनको सस्पेंड करने के लिये यहां से उठकर के सदन से एलजी के घर पे चलने का काम करेंगे, क्या एलजी उनको हटाने का काम करेंगे, या इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आदरणीय

अरविंद केजरीवाल जी के कामों को रोकने का काम करेंगे, उनको संरक्षण देने का काम करेंगे, बहुत शाबाश, तुमने काम रोका है तुमको एक विभाग से छोड़कर के दूसरे विभाग का भी सेक्रेटरी बनाने का काम देंगे। ये काम कर रहे हैं आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपको गरीबों से मतलब नहीं, उनकी दवाइयों से मतलब नहीं, अस्पतालों में काउंटर पर पर्ची काटने वाले सारे कर्मचारियों को हटा दिया गया। मुझे याद है मैं उस समय पीटिशन कमेटी का चेयरमैन था, इस तमाम मुद्दे पर बहुत गहनता से अधिकारियों को बुलाकर के चर्चा की गयी। सभापति महोदया, जब पूछा गया कि आपने इन कर्मचारियों को क्यों हटा दिया, तो कह रहे जी एक एआर स्टडी होगा और उसके बाद जो है इन कर्मचारियों को लगाया जायेगा। हम लोगों ने पूछा कि भई जब ये कर्मचारी दस साल से काम कर रहे थे तो क्या ऐसे ही काम कर रहे थे, कोई स्टडी नहीं हुई थी? बोले नहीं जी, वो नई बीमारी एक आई है एलजी साहब के यहां से, वो बीमारी एआर स्टडी कहलाती है, जब तक नहीं होगा, तब तक नहीं लगेंगे। एआर स्टडी के नाम पे रोक देते हैं आप लोग। तो आज मैं दिल्ली के लोगों से अपील भी करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक नायाब मॉडल देने वाले अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को रोकने के लिए पूरा ताकत लगा रहे हैं। वो सरकार जिसने शिक्षा में एक नायाब मॉडल दिया, इनके पेट में दर्द होता है 16 प्रदेशों में सरकार है वहां तो एक मॉडल शिक्षा का आप प्रस्तुत नहीं कर पाये, गुजरात में टेंट वाला स्कूल दिखा देते हैं। जब हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मॉडल मोहल्ला क्लिनिक

का मॉडल बनाया, निशुल्क इलाज, निशुल्क ऑपरेशन, निशुल्क रेडियोलॉजी का जांच, सब कुछ सुनिश्चित कर दिया अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने तो पेट में दर्द होना शुरू कर दिया। मैं कहता हूं आप भी अपने अस्पतालों में कर देते जो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं। आप कर दीजिये जो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं वहां भी फ्री हो जायें रेडियोलॉजिकल जांच, वहां भी सारी दवाइयां फ्री मिलने लगें।

माननीया अध्यक्षः त्रिपाठी जी कंप्लीट कीजिये।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः आपके पेट में दर्द क्यों होता है। आप कहते हो हम कर नहीं सकते, लेकिन दिल्ली के लोगों ने जो वोट किया अरविंद केजरीवाल को, उसका बदला लेंगे। तो 2024 में दवाइयों को रोकने का काम करोगे, 2024 में आपको कंक्ल्यूड करने के लिये, बाहर करने के लिये दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी का साथ देने का तय कर लिया है, दवाइयां जो रूकी हैं उसकी मैं निंदा करता हूं, जिन अधिकारियों ने इसमें लापरवाही की है इसकी जांच होनी चाहिये, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिये और अगर विपक्ष सहमत है तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो खड़े होंगे, बोलेंगे तो जरूर कहेंगे कि जो लापरवाह अधिकारी थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिये।

माननीया अध्यक्षः बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः अगर कहेंगे तो जनता के साथ खड़े हैं अन्यथा नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन सिंह बिष्ट जी। समय सीमा का ध्यान रखियेगा बिष्ट साहब।

श्री मोहन सिंह बिष्टः सम्मान के योग्य आदरणीय अध्यक्षा महोदया। निश्चित रूप में अल्पकालिक चर्चा में जो आपने मुझे भाग लेने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। वास्तव में यदि हम इसको पढ़ के देखें तो बहुत सी अच्छी बातें दिल्ली के अंदर ये हो रहा है, दिल्ली के अंदर ये होने वाला है लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं जिस सरकार के अंदर, जिसके मेंबर यदि गलती से या उपर वाले की वजह से बीमार हो जाता है आप के ही सरकार के डीजीईएचएस जो डिपार्टमेंट आपने वो कमेटी बनाई है, उस कमेटी का आपने एक टीम बनाकर के विधायकों के यदि इलाज नहीं होता, वो रिइम्बर्समेंट की ाईल डेढ डेढ साल से आज भी आपके इस डिपार्टमेंट के पास पड़ी हुई है, आखिर कौन सोचेगा उसके बारे में? हम बहुत सी बातें लिख देते हैं बोल रहे हैं हम, इसकी मंशा अच्छी हो सकती है लेकिन सरकार की मंशा कैसी है? आज रिइम्बर्समेंट की फाईल धूल फांक रही है इस प्रकार की स्थिति इस सरकार के द्वारा हुई है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिये। यदि सदन का मेंबर ही सुरक्षित नहीं रह सकता, उसके इलाज की रिइम्बर्समेंट नहीं मिल सकता, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूं। अध्यक्ष जी, यह भी सत्य है। वास्तव में उदासीनता है, काम न करने का बहाना है। आप लोग इस सरकार के माध्यम से जो कमेटी बनाई जाती है, जो

डॉक्टर्स उसमें अप्वाईंटमेंट किये जाते हैं, लाखों रूपया उनको तनख्वाह मिल रही है, पगार मिलती है आखिर उसके बारे में क्यूं नहीं चर्चा करते, क्यूं नहीं चर्चा होती? मान लिया यदि सदन का मेंबर इस बात को उठा रहा हो तो निश्चित रूप से इस बात का भी विशेष ध्यान देना चाहिये। मेरा कहना सीधा ये है कि आज दिल्ली सरकार के जिन अस्पतालों की बात आप लोग इस संकल्प के माध्यम से कह रहे हैं ये सत्यता है। बहुत सी चीजें इसमें देखने को मिला कि अस्पतालों के अंदर जो भी कर्मचारी या लेबर या दवाई बांटने वाला वो लगा था। सरकार क्या ऐसी पालिसी नहीं बना सकती, उनको परमानेंट करे, उनके पैसे ठीक समय से दे, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो सकती थी क्या? लेकिन कुछ नहीं हुआ, ढाक के तीन पात वाली कहानी इसमें चरितार्थ होती है। मोहल्ला क्लिनिक जिनकी बात आप कह रहे हैं इसमें पूरे सदन के अंदर मोहल्ला क्लिनिक जैसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई इस प्रकार की दवाइयों की व्यवस्था देने वाला नहीं, आखिर मोहल्ला क्लिनिकों की स्थिति क्या है ये दिल्ली में जा करके देख लीजिये आप। मोहल्ला क्लिनिक में न डॉक्टर है, न आपका कंपाउंडर है, न आपकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को देखना होगा, ये नहीं किएक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगायें। भई आरोप और प्रत्यारोप इस सदन के अंदर लगा सकते हैं, जनता पे तो आपका उत्तरदायित्व बनता है, जवाबदेही बनती है। आखिर सरकार क्या कर रही है, क्यूं नहीं करना चाहती सरकार? यदि सरकार की इच्छाशक्ति ठीक हो तो उन कामों में सरलता आ सकती है। इसी प्रकार

से डिस्पेंसरियों की यही हालत है। आपके मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो जांच करने की बात की जा रही है वो परीक्षण कहीं नहीं हो रहा, वो दूसरे हॉस्पिटलों में पर्चियां बना दी जाती हैं, कमीशन सैट किया जाता है और कमीशन लिया जाता है डॉक्टरों के माध्यम से। सरकार उसमें क्या काम कर रही है, सरकार क्यूं नहीं करना चाहती है? इसी प्रकार से अध्यक्षा महोदया, डीटीसी के कर्मचारी हैं, आज उनकी पेंशन नहीं मिल रही हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के 60 साल सरकार के कामों में दिया हो आज वो व्यक्ति धक्के खा रहा है। पेंशन के लिये तरस रहा है, उसके घर का चूल्हा नहीं जल रहा है। मैं ये चाहता हूं कि इनपे भी इसी प्रकार से कार्रवाई और उनके जो पेंशन नहीं मिला, सरकार उसके लिये पैसे का अरेंजमेंट करे। रिटायर्ड टीचर हैं, टीचरों को भी इस प्रकार से..

माननीया अध्यक्षः विषय पे रहें।

श्री मोहन सिंह बिष्टः मैडम ये सब विषय इसी से संबंधित हैं।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्टः अरे भईया बात सुनो।

माननीया अध्यक्षः बिष्ट साहब आप मुझ से बात करें और स्वास्थ्य का विषय है आप विषय पर रहें।

श्री मोहन सिंह बिष्टः अध्यक्ष महोदया, जो जिस प्रकार से ये संकल्प लिखा हुआ है मैं उसी पर, उन्हीं विषयों पर चर्चा कर रहा हूं।

मेरा कहने का सीधा सीधा है आज जिस प्रकार से सरकार फाईनेंशियली पूरी तरह से इनकी व्यवस्था चर्रमर्रा गयी है, आखिर क्यूं नहीं करना चाहती है। आज आप देख लीजिये जो डीटीसी में जो दस हजार मार्शल लगे थे उन मार्शलों की भी हालत क्या है? इसी प्रकार से आपने एक तो हॉस्पिटल को एक बहाना बना लिया लेकिन वो भी तो एक इसी टाईप के मजदूर हैं न। उनके लिये क्यूं नहीं ऐसी व्यवस्था सरकार कर सकती है? सरकार अपने आप एक ऐसा व्यवस्था तय करे जिससे उन लोगों को लाभ मिल सकता है, उनकी रोजी रोटी चल सकती है। दूसरी ओर बहुत से ऐसे पद आज भी रिक्त हैं, उन रिक्त पदों को क्यूं नहीं भरा जा रहा है? सरकार ऐसा कोई काम क्यूं नहीं करना चाहती? हमारा सिर्फ, यहां जितने भी मेंबर्स आये हैं उनका सिर्फ एक काम नहीं है आरोप प्रत्यारोप, समस्या का समाधान होना चाहिये, जनता को लगे कि वास्तव में सदन के मेंबर हैं उसका रिजल्ट मिलना चाहिये, ये मेरा कहना है।

माननीया अध्यक्ष: चलिये। धन्यवाद।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो चर्चा का विषय रखा ये बड़ी ठीक रखा है लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने का तरीका, ये ठीक नहीं है, सरकार को अपने गिरेबान में जरूर झांक के देखना चाहिये ये मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब श्री दिलीप पाण्डेय माननीय मुख्य सचेतक संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति लेंगे।

श्री दिलीप पाण्डेयः अध्यक्ष महोदया, आज जिन दवाइयों और टैस्ट के न होने के उपर जो गंभीर चर्चा इस सदन पटल पर हुई है उससे जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव मैं इस सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं।

माननीया अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

अब आप प्रस्ताव पेश करें।

श्री दिलीप पाण्डेयः अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के पटल पर दिल्ली के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, जो डिस्पेंसरीज हैं, जो अस्पताल हैं उनमें दवाइयों की कमी, कंज्यूमेबल्स की कमी, टैस्ट न हो पाने की जो समस्या है इसपे बहुत गंभीर चर्चा हुई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः बैठ जाईये।

...व्यवधान...

श्री दिलीप पाण्डेयः मुझे लगता है कि आप लोग चेयर से बात करें आप ही कहते हैं कि चेयर से बात की जाए। तो आप मुझ से बात मत करें, चेयर से बात करिये।

माननीया अध्यक्षः आपको प्रस्ताव चाहिये था आपको दे रहे हैं न प्रस्ताव, बैठ जाईये, अननेसेसरी।

...व्यवधान...

श्री दिलीप पाण्डेयः मुझ से मत कहिये, आप अध्यक्ष महोदय।

माननीया अध्यक्षः दिलीप पाण्डेय जी आप कंटिन्यू करिये।

...व्यवधान...

श्री दिलीप पाण्डेयः अध्यक्ष महोदया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा दिनांक 15 मार्च, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में संकल्प करती है किः यह सदन गंभीर चिंता व्यक्त करता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभिन्न मोहल्ला क्लिनिक, औषधालय, अस्पताल की जरूरी मुफ्त दवाईयों, कंज्यूमेबल्स और फ्री लैबोरेटरी टैस्ट की भारी कमी का सामना कर रहा है। यह सर्वविदित तथ्य है अध्यक्ष महोदया कि गरीब लोग, आम लोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के इन मोहल्ला क्लिनिकों, औषधालयों और अस्पतालों पर पूरी तरह से अपने इलाज के लिये निर्भर हैं क्यूंकि वे प्राईवेट अस्पतालों के महंगे इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत चिंता

का विषय है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिकों, औषधालयों और अस्पतालों में मुफ्त दवाइयों और लैब टैस्ट की अनुपलब्धता की वजह से गरीब लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और इससे लोगों के बीमार होने का खतरा बढ़ रहा है और शहर में दहशत भी फैल सकती है जो अभी अभी महामारी से उबरा है। अध्यक्ष महोदया, उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह सदन संकल्पित करता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लीनिकों, ओषधाल्यों और अस्पतालों में दवाइयों, उपभोग्य सामग्रियों, लैब टैस्ट्स और अन्य सुविधाओं की कमी या अनुपलब्धता की समस्या को युद्धस्तर पर तुरंत हल किया जाए। (2), उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे। (3), यह सदन मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को एक सप्ताह के भीतर इन कमियों को दूर करने का निर्देश देता है, जिस दौरान वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। (4), इस मामले पर आगे विचार करने के लिए शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 2024 सुबह 11 बजे दिल्ली विधान सभा की बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से इस संबंध में अपनी एक डिटेल रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः अब श्री दिलीप पाण्डेय जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है, वो हां कहें,

जो इसके विरोध में है, वो ना कहे,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हॉ पक्ष जीता

संकल्प स्वीकार हुआ।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी चर्चा का जवाब देंगे।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री सौरभ भारद्वाज): अध्यक्षा महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पर बोलने का मौका दिया और मदनलाल जी ने, अखिलेश त्रिपाठी जी ने, ऋतुराज भाई ने, दिलीप पाण्डेय जी ने इस विषय को सबके सामने रखा है और मुझे लगता है कि जो समाज का सबसे गरीब तबका है, उसके लिए सरकारी अस्पतालों की दवाईयाँ ही इकलौता माध्यम है। जो मिडल क्लास है, हालांकि मिडल क्लास भी बड़ी मात्रा में आज हमारे मोहल्ला क्लीनिकों से दवाइयाँ लेता है, सरकारी अस्पतालों में भी मिडल क्लास जाता है। बट मिडल क्लास को अगर दवाई नहीं मिली तो चलिए वह अपनी जेब से पैसे खर्च करके बाजार से दवाई ले भी लेंगे। मगर जो बड़े तौर पर आपका गरीब तबका है, आपके सरकारी अस्पतालों में अगर दवाइयाँ खत्म हो गई और वो हो रही हैं, तो उनको दवाईयाँ कैसे मिलेंगी, ये सवाल आज इस सदन के सामने है। अब दवाइयाँ क्यों खत्म हो गई हैं। एक साधारण सी प्रक्रिया है जो सरकारी अस्पतालों में चलती है। एक एजेंसी है जिसको सैंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी, सीपीए कहा जाता है, जो पूरी दिल्ली की, दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था होती है, अस्पतालों

हों, डिस्पेंसरी हों, मोहल्ला क्लीनिक हों इन सबके लिए सीपीए जो है, दवाई प्रोक्योर करता है और इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसका टेंडर होता है। जाहिर सी बात है एक टेंडर जब खत्म होने वाला होता है उससे पहले ही दूसरे टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाती है ताकि ये टेंडर खत्म हो उससे पहले आपके पास नया टेंडर जो है मैटिरियलाइज हो जाए, नई कम्पनी आ जाएं और वो दवाईयों का डिस्ट्रिब्यूशन, ये कंटीन्यूइंग चीज है, इसको आप रोक नहीं सकते, कभी नहीं रोका गया। मैं इस सदन को बताना चाहूंगा अध्यक्षा महोदया आपके माध्यम से कि इस विषय में टेंडर 2022 में, 29 दिसम्बर, 2022 में ये टेंडर किया गया, निविदा आ गई और उस टेंडर की टैक्नीकल evaluation अफसर करते रहे, करते रहे, करते रहे, पूरे साल करते रहे और वो टेंडर एक्सपायर हो गया। भई आपने किसी कम्पनी से रेट मंगाए, वो रेट कब तक वैलीड होंगे, टेंडर ही एक साल का है आपका, तो कम्पनी ने ये कहा कि इस साल के अंदर में इस रेट में दवाई दे सकते हैं। आपने एक साल से ज्यादा बिता दिया, टेंडर की वैलिडिटी ही खत्म हो गई, दवाईयों के रेट बढ़ गए और अब आपका जो करंट टेंडर है वो मार्च में एक्सपायर हो रहा है, इसी महीने जो है मार्च में वो टेंडर एक्सपायर हो जाएगा। आपके मोहल्ला क्लीनिकों में आपके अस्पतालों में, आपके डिस्पेंसरियों के अंदर दवाईया खत्म हो गई होंगी। अब मैं आपके माध्यम से, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र हैं विपक्ष में हैं, उनसे अपने विधायक साथियों से इसकी जो भी लोग हैं, अखबार में इसको पढ़ें, बड़े-बड़े वकील पढ़ेंगे इसको वो पढ़ें, बड़े-बड़े जज साहब पढ़ेंगे वो पढ़ें, बुस्रिजीवी पढ़ें,

भारतीय जनता पार्टी के हों, कॉग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के हों, जो भी हों, वो सब पढ़ें, मैं एक हल्थ मिनिस्टर के नाते उन लोगों से जानना चाहूंगा, अपने विपक्ष के मित्रों से जानना चाहूंगा कि एक साल तक जिस टेंडर को नहीं किया गया, जानते हुए कि अगर ये टेंडर नही हुआ तो दिल्ली के अंदर दवाईयों की मारा-मारी हो जाएगी जिन्होंने नहीं किया, उनका क्या करना चाहिए? कुछ तो करना चाहिए उनका। मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मैं उनका कुछ भी कर सकूं, क्योंकि वो शक्तियाँ मेरे से छीनकर एलजी साहब को दे दी हैं केंद्र सरकार ने। तो मुझे नहीं करना, एलजी साहब को करना है। तो हमारे विपक्ष के साथी बताएं कि उस हैल्थ सेक्रेटरी का क्या किया जाए जिन्होंने पूरी दिल्ली की दवाईयों के टेंडर एक साल बाद भी फाइनल नहीं किए और वो टेंडर खत्म हो गया और नया टेंडर शुरू नहीं हुआ। मैं, हो सकता है, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, मैं तो अभी-अभी मंत्री बना हूं, मुझे तो नहीं जानकारी, बहुत बड़े-बड़े विद्वान लोग हैं, वो मुझे बताएं कि अब चुनी हुई सरकार उस हैल्थ सेक्रेटरी का क्या करे, उस डीजीएचएस का क्या करे, उस सीपीए के अफसर का क्या करे, उनका क्या किया जाए? उनकी आरती उतारी जाए, उनकी सदन के अंदर तस्वीर लगा दी जाए, क्या किया जाए उनका? क्योंकि, या उनको कोई जो है अवॉर्ड दे दिया जाए, या उनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे दिया जाए, क्या किया जाए उनके साथ। एक ही सुझाव आ रहा है मेरे पास पीछे से वो कह रहे हैं उनको उपराज्यपाल बना दिया जाए। ये सुझाव पीछे से लाकड़ा जी की तरफ से आए, मेरा नहीं है। मैंने तो सिर्फ सदन

को बताया है। तो अध्यक्षा महोदया अब आप ये सोचिए, मदनलाल जी ने तो खांसी-जुकाम की बात की है। खांसी-जुकाम तो बहुत छोटी बात है, जिनकी किड़नी फेल हो रखी हैं, वो लोग इन दवाईयों पर आश्रित हैं, जिनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो रखीं हैं, स्टैंट डल रखें हैं, वो लोग इन दवाईयों पर आश्रित हैं, जिनकी मां को छोटी बच्ची को जिनके घर में कैंसर हो रखा है, वो लोग इनके ऊपर आश्रित हैं। कैमोथैरिपी होनी है, किसी की रेडियोथैरिपी होनी है वो लोग इसपर आश्रित हैं, उनका क्या होगा? और दवाईयों के बिना तो आपका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, ऑपरेशन में भी कुछ दवा तो लगती हैं, कुछ इंजेक्शन तो लगते हैं, ना ऑपरेशन होगा, ना सर्जरी होगी, ना दवाई मिलेगी। आप ये सोचिए की उन लोगों का क्या होगा? वो लोग मर जाएंगे और इस वक्त दिल्ली के अंदर ऐसा कोई सोच-विचार नहीं है कि ऐसे अफसरों का क्या किया जाए। मेरा मानना ये है कि जो उन अफसरों ने किया वो क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल उनके ऊपर क्रिमिनल मुक्कदमा किया जाना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए और हम सब लोग जो हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हमारे पास चूंकि कुछ छोड़ा नहीं है केंद्र सरकार ने, चर्चा करने के अलावा केंद्र सरकार ने कुछ नहीं छोड़ा, कि भई इसपर चर्चा कर लो। इसके बाद प्रावधान रखे गए थे। प्रावधान ये भी रखा गया है कि अगर सीपीए से दवाईयाँ ना मिले तो आप लोकल रेट कॉंट्रैक्ट कर लो या लोकल टैंडर करके, लोकल कैमिस्ट से दवाई खरीद लो जिसको लोकल परचेज कहा जाता है। अब अफसरों को ये समझ में आ गया कि सीपीए से तो दवाईयाँ नहीं आएंगी कुछ दिनों

बाद, मगर ये तो लोकल टैंडर जो कर रखें हैं उससे दवाई आ जाएगी, तो उसको कैसे रोका जाए। तो उसके लिए भी एक उलजलूल ऑर्डर निकाला गया, हैल्थ डिपार्टमेंट द्वारा और मैंने अभी कुछ दिनों पहले मैडिकल सुप्रिंटेंडेंटस थे जितने उनकी एक मीटिंग की, 1 मार्च, 2024 को मैंने मैडिकल सुप्रिंटेंडेंटस की मीटिंग की, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि फिलहाल भी सीपीए से आने वाली 50 परसैंट दवाईयाँ आनी बंद हो चुकी हैं। आने वाले कुछ दिनों के अंदर बाकी दवाईयाँ भी बंद हो जाएंगी क्योंकि सीपीए का टैंडर एक्सपायर होने वाला है। जो लोकल परचेज के ऊपर और जो लोकल कैमिस्ट से खरीदने के ऊपर जो टैंडर द्वारा किया जाता है, ओर्डर निकाले गए हैं हैल्थ डिपार्टमेंट द्वारा, जिसके बारे में जितने भी मैडिकल सुप्रिंटेंडेंटस और एमडीज थे और वहां पर हैल्थ सेक्रेटरी मौजूद थे, स्पेशल सेक्रेटरी, हैल्थ मौजूद थे, उन सबने बोला कि आपने जो ये कंडीशंस लगाई हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं हैं, ये सम्भव नहीं हैं। अब क्यों नहीं हैं, मैं आपको बताता हूं। आपने बोल दिया कि आप लोकल कैमिस्ट से जो परचेज कर रहे हैं, उसके लिए ओरिजनल मैन्फ्रैक्चरर, गवर्नमेंट अप्रूड लैब से टैस्ट की रिपोर्ट दें। क्या बात कर रहे हैं आप, ये कैसे हो सकता है? आप अपने लोकल कैमिस्ट के पास जाएं दवाई लेने और आप बोलें की तेरे जो ओरिजनल मैन्यूफैक्चर्र हैं वो गवर्नमेंट लैब से टैस्ट कराके मेरे को रिपोर्ट दे, वो क्यों देगा और जब आपने उस लोकल कैमिस्ट से टैंडर कर लिया, कॉट्रैक्ट कर लिया, कॉट्रैक्ट के बाद आप उसके ऊपर ये कंडिशन कैसे लगा पाओगे। आप ये जरूर कर सकते हो कि आपके पास जो कैमिस्ट

से दवाई आ रही है, आप उस सबकी टैस्ट कराओ। आप टैस्ट कराओ। सरकारी अस्पताल कहीं से भी दवाई खरीदे वो टैस्ट करा ले उसका, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी आपके पास। आप ये कहें कि नहीं लोकल कैमिस्ट को कहो कि ओरिजनल मैन्यूफैक्चर्र गवर्नमेंट अप्रूड लैब से टैस्ट रिपोर्ट देगा तब आप दवाई लोगे, फिर तो आप मारना चाहते हो मरीजो को। आप ये चाहते हो कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लीनिकों में, डिस्पेंसरियों में दवाई आनी बंद हो जाएं, जो मरीज बीमार हैं वो और बीमार हो जाएं, जो ज्यादा गम्भीर हैं वो मर जाएं और दिल्ली के अंदर हाहाकार मच जाए, क्योस मच जाए। देखिए राजनीति सब करते हैं, डैमोक्रेसी है, राजनीति करने का हक सबको है। सब एक दूसरे की छोटी-मोटी जो है टांग खिंचते हैंकि भई इससे बेहतर होने के लिए क्या करूं, ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, मगर आज जिस लेवल पर राजनीति को लाया गया है, वो मुझे लग रहा है कि बहुत घटिया है। मतलब इससे घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए और मैं आपको ये भी बता रहा हूं, इससे भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र मेरे सामने बैठे हैं, इन बेचारों का कोई फायदा नहीं है इसमें। इनका कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो पाएगा इसके अंदर क्योंकि ये चीज दिल्ली के अंदर 2015 में भी हुई, ये चीज दिल्ली में 2020 के चुनाव में भी हुई और यही चीज दिल्ली के अंदर 2025 में भी होगी। आप अगर कामों को अफसरों के जरिए रूकवाओगे, तो जनता को समझ में आएगी, ऐसा कोई ना है कि हम गूंगे हैं, हम बोलेंगे नहीं। हम चीख-चीख के बोलेंगे हम सबको बताएंगे कि आपने क्या किया और

कागज हैं हमारे पास सारे के सारे जिसमें सबके काले चिट्ठें हैं कि आपने किस तरीके से आपके अफसरों ने अलग-अलग लेवल के ऊपर दिल्ली की जनता को परेशान किया और उसका नुकसान एलजी को नहीं होगा, एलजी साहब को तो शाबासी मिलेगी ऊपर से कि बहुत बढ़िया, इनको होगा नुकसान। इनसे जनता पूछेगी 2025 के अंदर कि भईया दवाईयाँ जब नहीं मिल रही थी तो उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तुमने कितनी चिट्ठियाँ लिखी एलजी को, तुम कितनी बार मिलने गए एमएचए के अंदर कि जी इस अफसर के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जनता इनसे पूछेगी ये लोग जवाबदेह हैं वो अफसर जवाबदेह नहीं है। वो चीफ सेक्रेटरी जो यहां पर बैठे हुए थे वो जवाबदेह नहीं है। वो एलजी साहब जिनको दिल्ली के ऊपर बिठा दिया गया है, वो जवाबदेह नहीं हैं, उनकी जवाबदेही नहीं है। इन बेचारों की जवाबदेही है और दिल्ली के अंदर ये चीज, हर चीज में की जा रही है। चाहे वो टैस्ट हों, टैस्ट को रोकने का भी तरीका किया गया है, टैस्ट वाली जो कम्पनीज हैं, जो मोहल्ला क्लीनिक के अंदर टैस्ट करती थी, उनकी पिछली एक साल से पेमेंट नहीं हुई। वो लोग लिखकर दे चुके हैं कि हम ये टैस्ट नहीं कर सकते, हमारा काँट्रैक्ट खत्म करो। उनकी भी मार्च के अंदर आखिरी डेट है, मार्च के बाद उन्होंने हाथ जोड़ दिए है, उन्होंने बोला भई हम नहीं कर सकते तुम्हारे टैस्ट। उसके बावजूद कोई नया टेंडर नहीं किया है कि कौन सी नई कम्पनी आएगी, कौन जो है टैस्ट करेगी मोहल्ला क्लीनिक के अंदर, चाहे वो ब्लड टैस्ट हो, यूरिन टैस्ट हो और कोई टैस्ट हो। अस्पतालों के

अंदर भी ज्यादातर टैस्ट आउटसोर्सड हैं। उसके लिए भी कोई नया टैंडर नहीं किया गया है। अभी-अभी जल बोर्ड के विषय में बात कही जा रही थी, मैं जल बोर्ड के विषय में भी अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूरे हाउस को बताना चाहता हूं, कोई टैंडर जल बोर्ड के अंदर नहीं हो रहा है, कोई भी। ये जो जल बोर्ड की जितनी भी रिपोर्ट दी गई, उसके अंदर क्या शब्द इस्तेमाल किए गए, उसमें क्या कहा गया। टैंडर कर दिए गए हैं, वर्क ओर्डर की प्रक्रिया जारी है। अरे भई वर्क ओर्डर की प्रक्रिया कैसे जारी है। जब तुम्हारे टैंडर में कोई आ ही नहीं रहा, जब वो उसके अंदर कोई पार्टी ही नहीं आ रही, तो उसके अंदर वर्क ओर्डर की प्रक्रिया कैसे जारी है? उन्होंने बात को घुमा दिया, उन्होंने बोल दिया टैंडर कर दिया, टैंडर तो कर दिया ये बात सही है। टैंडर तो एक चीज के दो-दो, तीन-तीन बार करे जा चुके हैं, मगर वो सब विधायकों के यहां टैंडर नो शो चल रहे हैं। तो वो आए अफसर उन्होंने गोलमोल बात घुमाई और गोलमोल बात को फिर घुमाकर चले गए और कल 3 बजे आचार संहिता लग जाएगी, वर्क अवॉर्ड होगा कब? होगा ही नहीं। तीन महीने तक बात गई, हो ही नहीं सकता आपका, नहीं हो सकता ना?

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः गुप्ता जी।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री सौरभ भारद्वाज): वर्क ऑर्डर नहीं होता। तो मैं अध्यक्ष महोदया जितनी, हो सकता है गुप्ता जी को ज्यादा

पता हो, जितनी मुझे पता है, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंसड हैं। मैं ये बात कह रहा हूं कि चुनाव के समय में अचार संहिता के समय वर्कओर्डर नहीं होते।

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री सौरभ भारद्वाज): खैर आप पता कर लीजिए।

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री सौरभ भारद्वाज): चलिए, आप देख लीजिएगा।

...व्यवधान...

माननीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री सौरभ भारद्वाज): तो कोई भी वर्कओर्डर जो है, कल 3 बजे जब अचार संहिता लग जाएगी उसके बाद नहीं खुलेगा। तो बहुत ज्यादा दिक्कत जो है वो की जा रही है और चलिए आपने पानी में कर ली, सीवर में कर ली मगर जब आप लोगों की जिंदगी के साथ खेलने लगोगे तो मुझे लगता है कि राजनीति जो है उससे नीचे के स्तर की राजनीति जो है, फिर नहीं आ सकती। मैं सदन के, फिर भी अपने बिष्ट साहब ने जो भी बोला, अच्छा बोला मैं उनका धन्यवाद करूंगा और उन्होंने ये बात बोली कि बिल्कुल बात है, सरकार की जवाबदेही है और सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि काम हों। मैं सदन को कहना चाहता हूं कि हम कोशिश कर रहे हैं

काम हों। मगर कोई और तरीका हो, हमारे किसी भारतीय जनता पार्टी के मित्र के पास कि ये कर दो, तो वो मुझे जरूर बताएं, हम वो कर देंगे, है ना? कि भई ये चिट्ठी लिख दो, एलजी साहब से मिल आओ, कहीं और चले जाओ, अफसर को बुला लो और दिलीप भाई ने एक बड़ी अच्छी रैजुलूशन इसके अंदर की है, उसके अंदर उन्होंने मोटे तौर पर ये कहा है कि मुख्य सचिव को ये जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि मैं मुख्य सचिव को इसके बारे में दो-तीन बार लिख चुका हूं कि उनको जिम्मेदारी दी जाए कि एक हफ्ते के अंदर वो ये सुनिश्चित करें, दो चीजें कि दिल्ली के अस्पतालों, डिस्पैंसरीज और मोहल्ला क्लीनिकों के अंदर दवाइयाँ सुनिश्चित हों और इनके अंदर जो लैबरोटरी टैस्ट है, ब्लड टैस्ट हैं वो सुनिश्चित हों, वो जो हैं मुख्य सचिव सुनिश्चित करें और एक हफ्ते का समय जो है वो मुख्य सचिव को दिया गया है। मगर कॉन्क्रीट जो है इसकी जानकारी मुख्य सचिव लेकर आएं और इसके ऊपर काम करें क्योंकि ये मामला दिल्ली के स्वास्थ्य से संबंधित है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद। अब श्री नरेश बाल्यान जी, माननीय सदस्य दिल्ली के अनधिकृत कालोनियों में बिजली के मीटर लगाने के लिए डीडीए या संबंधित..

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः गौतम जी आप चेयर को नहीं बताएंगे पहले कौन सा टैकअप करना है, आप का विषय ले लिया जाएगा। या इससे

संबंधित प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने की अनिवार्यता के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।

ध्यानाकर्षण (नियम-54)

श्री नरेश बाल्यान: धन्यवाद अध्यक्षा महोदय। दिल्ली सरकार ने बिजली के क्षेत्र में बहुत सारे शानदार काम किए हैं, चाहे बिजली के बिल आधे करने का हो, दो सौ यूनिट तक फ्री करने का हो। लेकिन पिछले तीन-चार महीने से कोई भी आदमी अगर बिजली का मीटर अनोथराइज्ड कॉलोनी में अप्लाई करता है तो बीएसईएस के अधिकारी कहते हैं कि डीडीए ने इन कॉलोनियों के ऊपर बिजली का मीटर लगाने के लिए एनओसी लेने के लिए कहा है। तो अब डीडीए के अधिकारियों से बात हुई कि अनोथराइज्ड कॉलोनियों में डीडीए का क्या लेना-देना है, तो डीडीए वाले कहते हैं जी की ये सारा क्षेत्र लैंड पूलिंग के अंदर है, 2007 में जो सरकार ने घोषणा की थी कि लैंड पूलिंग के तहत इसकी एनओसी मतलब इन कॉलोनियों के अंदर डीडीए के पास ये जमीनें है। अध्यक्ष महोदया, अगर मान लीजिए किसी का कोई मकान बना हुआ है, कॉलोनी के अंदर 90 परसैंट मकान बने किसी ने एक मकान, 50 गज का, 30 गज का मकान नया बना तो उसके अंदर लैंड पूलिंग क्या करेगी। लैंड पूलिंग अनोथराइज कॉलोनी में होना पोसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से। क्योंकि ये जो मास्टर प्लान के हिसाब से बात कर रहे हैं, ये 2002 के मास्टर प्लान में, 2007 के लैंड पूलिंग की बात कर रहे हैं और वो अनोथराइज कॉलोनियों में किसी भी तरीके से पोसिबल नहीं है कि लैंड पूलिंग लागू हो जाए।

अब मान लीजिए कोई बिल्डर अगर मकान बना रहा है, बिल्डर अगर कोई फ्लोर बना रहा है तो उसको एनओसी लेकर आनी है, तो अब डीडीए ने एक नई दुकान खोल दी। दो लाख, तीन लाख रुपए एक एनओसी की लेते हैं और उनको मीटर मिल जाते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी बीस-पच्चीस गज का मकान बना रहा है, वो चक्कर ही काटता घूम रहा है। अब किसी ने अपना मकान तोड़ा और दो मंजिल का नया मकान बनाया, 50 गज का किसी का मकान है तो उसने कहीं, जब मकान बन रहा है तो कहीं न कहीं अड़ोस-पड़ोस में कहीं किराये पर रह रहा है वो। तो किराये पर रहने के दौरान उसने मकान बनाया, उसकी रजिस्ट्री कर दी, उसके पानी का मीटर लग गया, लेकिन बिजली का मीटर नहीं लग रहा। और जब वो लोग चक्कर लगा रहे हैं डीडीए के ऑफिस में तो कह रहे हैं कि बीएसईएस मेल भेजेगा। ये मतलब उन लोगों को unnecessary परेशान किया जा रहा है और ये सारा का सारा मास्टर प्लान, लैंड पूलिंग को लेकर ये कहा जा रहा है कि भई जब तक एनओसी नहीं मिलेगी और डीडीए एनओसी किसी को कोई दे नहीं रहा। लगभग मेरी उत्तम नगर विधान सभा में चार से पांच हजार कनैक्शन पेंडिंग हैं और लगभग तीन-चार महीने हो गए हैं। लोग लगातार चक्कर लगा रहे हैं, कभी डीडीए के ऑफिस में, कभी बीएसईएस के ऑफिसों में, लेकिन मीटर नहीं मिल रहे हैं। कई मकान ऐसे हैं कि जिसने दो मंजिल मकान बना रखा था और अब एक मंजिल और उसके अंदर उसने एक छत और डाल दी। अब मान लीजिए किसी के तीन भाई थे तो दो ने पहले बना रखा था एक ने अब बना लिया तो वो,

मतलब अब अच्छा एक चीज और बड़ी मजेदार चीज है इसमें। कि मान लीजिए कोई एनओसी ले भी आया, अब किसी का दो सौ गज का प्लॉट था दो भाईयों का, तो एक ने बना लिया और वो एनओसी ले आया। अब जब वो एनओसी उस कॉलोनी की आ गई तो उस कॉलोनी के लिए मतलब हर प्लॉट की एनओसी चाहिए। हर प्लॉट की एनओसी तो मतलब लोग डीडीए के दफ्तरों में ही चक्कर लगाए जाएंगे। तो मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि डीडीए से बैठकर मंत्री जी से भी बात हुई थी कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जल्दी निकाला जाए, लोगों को unnecessary परेशान किया जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत बुरी तरीके से डीडीए के अधिकारी, मतलब बीस गज, 50 गज, 100 गज के मकानों से जिस तरीके से पैसे की उगाही की जा रही है, तो ये बहुत गलत है, थैंक्यू।

माननीया अध्यक्षः गुलाब सिंह यादव जी।

श्री गुलाब सिंहः धन्यवाद अध्यक्षा महोदय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इशू नरेश बालयान जी ने सदन के समक्ष रखा है और क्योंकि मेरी विधान सभा भी इससे पूरी तरह से प्रभावित है और सिर्फ ना की अनोथराइज कॉलोनी, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी बिजली के कनैक्शन देने से मना कर रहे है और दिल्ली के इतिहास में जहां तक हमें याद है कि आज तक डीडीए का कोई रोल नहीं रहा बीएसईएस के कनैक्शन को रोकने का, ना उनके पास कोई अधिकार है। जानबूझ कर ये फरमान जो है इन्होंने नवम्बर, दिसम्बर में पिछले वर्ष लागू किया और जमकर पैसे की वसूली हो रही है। प्रीतमपुरा बुलाया जाता

है लोगों को, बीएसईएस ये कहकर पल्ला झाड़ लेता है भाई साहब हमने तो वहां लिखकर भेज दिया अब आप वहां चलकर अप्रोच करो। वहां जाकर वो अप्रोच करते हैं उनसे पैसे मांगे जाते है, धड़ल्ले से डेली का काम है और भाई साहब के यहां आप बता रहे हैं तीन-चार हजार कनैक्शन है, मेरे यहां पर तो करीबन 10 हजार कनैक्शन पेंडिंग होंगे। तो इतना बुरा हाल है इसमें मेरा निवेदन है, इसमें दिलीप भाई, सोमनाथ भारती जी और शायद विजेंद्र गुप्ता जी आप विपक्ष के साथियों में से कोई डीडीए के सदस्य हैं, तीन एमएलए। तो मेरा निवेदन आपसे भी है कि आप जब भी एलजी साहब के साथ में ये मीटिंग हो तो इस विषय को जरूर आप उठाएं और इसकी एक लिखित की कॉपी भी हम आपको एज ए डीडीए मैंबर दे देंगे और मुझे लगता है कि जो-जो अनोथराइज्ड कॉलोनी वाले एमएलए है, ये दिक्कत तो सबको आई होगी, ये आनी शुरू हो गई है। किसी के यहां नहीं आई है तो बहुत जल्दी आने वाली है। और रोजाना लोग आपके चक्कर काटेंगे, पहले तो हमारा लैटर जाता था उससे कनैक्शन मिल जाता था कोई दिक्कत थी ही नहीं। अब कोई लैटर-वैटर को पूछ नहीं रहा है जी। डीडीए वाले कह रहे हैं कि जी पैसा लेकर आओ बाद में देखेंगे।.. अच्छा दूसरी बात, नरेश जी ने कहा कि भई उन्होंने कहा लैंड पूलिंग में आ जाएगी इसलिए रोक दिया ऽलांना, विषय वो नहीं है। इन्होंने आधार नरेश जी ये बनाया है कि कुछ एरिया के अंदर, कुछ बिल्डर लोग जो हैं, वो अलग से कॉलोनी-वलोनी डवलप कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड में नई कॉलोनियाँ। मान लिया आप उसमें रोक लो, हालांकि अधिकार तो आपको उसमें भी

रोकने का नहीं है। लेकिन जो नई एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कॉलोनी वगैरा काटने का जो काम रहे हैं आप वहां तो रोक सकते हो, लेकिन दिल्ली की 1739 कालोनियों के अंदर जिसके अंदर दिल्ली सरकार ने पानी की लाइन, सीवर लाइन, रोड, ट्रांसफार्मर लगा दिए, पोल लगा दिए, सारी सुविधाएं दे दी आप उनमें कैसे रोक सकते हो? तो ये तो पोसीबल नहीं है। तो इसके अंदर मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से भी आप बात करें और हम लिखित में जो है वो स्पीकर महोदय को भी एक चिट्ठी भेजेंगे, वो हमारे behalf पे एलजी साहब को भी लिखें और सारे मैंबर्स को भी हम चिट्ठी लिखेंगे ताकि इसका कोई जल्दी से जल्दी समाधान हो सके, बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद।

माननीया अध्यक्ष: अब सदन की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 22 मार्च, 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभी साथी लंच के लिए आमंत्रित हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 22 मार्च, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

नोट: माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार दिनांक 22 मार्च, 2024 की सदन की बैठक रद्द कर दी गई व सदन की अगली बैठक दिनांक 27 मार्च, 2024 को होनी तय की गई (दिल्ली विधान सभा समाचार भाग-2 संख्या 140 दिनांक 22 मार्च, 2024)

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BULLETIN PART-II
(General information relating to legislative & other matters)
Friday, 22 March 2024/02, Chaitra, 1946 (*Shaka*)

No. 140

Sub: Regarding cancellation of the sitting of the House on 22nd March 2024 and determining the next sitting of the House on 27th March 2024.

Hon'ble Members are hereby informed that the Hon'ble Speaker has directed that the sitting of the House scheduled for today i.e. 22nd March 2024 stands cancelled.

Further, in pursuance of sub-rule (1) of Rule-17 (Adjournment of the House and procedure for reconvening) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, the Hon'ble Speaker has determined that the next sitting of the House shall be held on 27th March 2024 at 11.00 AM.

Deputy Secretary

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग–II
(विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित जानकारी)
शुक्रवार, 22 मार्च, 2024 / चैत्र 02, 1946 (शक)

संख्या : 140

विषय: दिनांक 22 मार्च 2024 को सदन की बैठक निरस्त कर अगली बैठक दिनांक 27 मार्च, 2024 को निर्धारित करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया है कि आज दिनांक 22 मार्च, 2024 को होने वाली सदन की बैठक रद्द की जाती है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम–17 (सदन का स्थगन और पुनः समवेत करने की प्रक्रिया) के उप–नियम (1) के अनुसरण में, अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया है कि सदन की अगली बैठक दिनांक 27 मार्च, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे होगी।

उप सचिव

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।